20 अक्टूबर, 2024 ★ वर्ष 33, पृष्ठ संख्या 68, अंक 10

राजस्थान सुजस

RISING RAJASTHAN

REPLETE • RESPONSIBLE • READY

अब तक 18,00,000 करोड़ ₹ से अधिक के एमओयू

अच्छे मानसून के बाद अब

निवेश वर्षा

मीरा महोत्सव
श्रीकृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा का स्मरण

राजस्थान में स्थित मेड़ता का प्रसंग आते ही भक्त शिरोमणि मां मीराबाई की श्रीकृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा, अदम्य साहस व पूर्ण समर्पण का स्मरण हो आता है। लगभग सवा पांच सौ वर्षों के बाद भी उनका जीवनवृत जन-जन का पथ-प्रदर्शन करता हुआ अन्तस को भक्तिरस का पान करवा रहा है।

अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में शहर के मध्य में स्थित राव दूदागढ़ (मीराबाई पेनोरमा) प्रांगण में पद्म विभूषण पं. हरिप्रसाद चौरसिया की बांसुरी की धुन, अनवर खान मांगणियार के सुरों की धारा और लोक कलाकारों की लोकनृत्य प्रस्तुतियों के साथ दो दिवसीय "मीरा महोत्सव" का आयोजन हुआ। आयोजन संगीत नाटक अकादमी, राजस्थान पर्यटन विभाग, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण एवं उपखण्ड स्तरीय पर्यटन विकास समिति मेड़ता द्वारा किया गया।

आलेख एवं छाया
नरेन्द्रसिंह जसनगर, प्रबंधक, मीराबाई पेनोरमा, मेड़ता सिटी

प्रधान सम्पादक
सुनील शर्मा

सम्पादक
अलका सक्सेना

सह-सम्पादक
डॉ. रजनीश शर्मा

सहायक सम्पादक
मोहित जैन

आवरण छाया
सुजस

राजस्थान सुजस में प्रकाशित सामग्री में व्यक्त विचार लेखकों के अपने एवं आंकड़े परिवर्तनशील हैं। आवश्यक नहीं कि शासन उनसे सहमत हो। सुजस में प्रकाशित सामग्री का विभाग किसी भी रूप में उपयोग कर सकेगा।

ग्राफिक डिजाइनिंग
प्रिन्ट 'ओ' लैण्ड
लागत मूल्य : 44.00 रुपये

सम्पर्क
सम्पादक
राजस्थान सुजस (मासिक)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
सचिवालय, जयपुर-302005
मो नं. 80948-98098
e-mail :
editorsujas@gmail.com
publication.dipr@rajasthan.gov.in
Website :
www.dipr.rajasthan.gov.in

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान का मासिक

वर्ष : 33 अंक 10 | अक्टूबर, 2024

इस अंक में

भरपूर अवसर भरे सरोवर 05

बांध के बंधन से बंधी परवाजें 34

श्रद्धासुमन 36

धन-धान्य की धरा गंगानगर 18

लोक जीवन	02
संपादकीय	04
मरुधरा के बांध	06
झालावाड़ के 25 बांध हुए लबालब	09
जयसमंद	10
राणा प्रताप सागर	12
क्षेत्र की लाइफलाइन है कोटा बैराज	14
छापरवाड़ा बांध	16
The Vision 2045 Framework	21
माही बजाज सागर	22
राज्य का गौरव बीसलपुर बांध	24
पांचना बांध	26
जवाई की जैव विविधता	30
रेत के धोरों में 'पेंगोंग झील'	32
ग्रामीण पर्यटन की झलक देवमाली गांव	58
पैरा ओलंपिक	60
आदि गौरव सम्मान समारोह	66
भीमलत महादेव मंदिर	67

राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 37

बरसात के साथ बरसी खुशियों की सौगात 28

चरैवेति....चरैवेति.... 62

उत्साह, उमंग और उल्लास का "त्योहार"

आप सभी सुधि पाठकजन को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं! इस शरद ऋतु में यूं तो हर ओर त्योहारी उत्साह, उमंग और उल्लास का वातावरण है, लेकिन राजस्थान में दीपावली के अलावा इस उल्लास की एक से ज्यादा वजह हैं।

पहली तो यह कि इस वर्ष बेहद अच्छी बरसात से प्रदेश के बांध करीब-करीब अपनी पूरी क्षमता तक अमृतमयी जल से भरे हुए हैं। इसका अर्थ है आज भी कृषि प्रधान हमारी अर्थव्यवस्था में हमारे अन्नदाता 'अच्छे जमाने' की आस में प्रसन्न हैं।

इसके अलावा निवेश के पूर्व के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से प्रदेश में अब तक 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि के निवेश एमओयू हस्ताक्षरित हो चुके हैं। प्रदेश में निवेश की यह बरसात यूं ही नहीं हो रही है, निवेश के इस मानसून की हवाएं पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का विजन साथ लेकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा किए जा रहे सतत प्रयासों से राजस्थान की ओर मुड़ी हैं। सितम्बर में दक्षिण कोरिया और जापान की सफल यात्रा के बाद अक्टूबर में जर्मनी और ब्रिटेन की यात्रा ने इस मुहिम को और ऊंचाई दी है।

इस वर्ष निकलने वाली बम्पर भर्तियों ने युवाओं को उनका लक्ष्य दे दिया है। मुख्यमंत्री भर्ती प्रक्रिया में नियमों के सरलीकरण एवं एकरूपता के लिए भी प्रयासरत हैं। दिसम्बर में होने वाले 'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में आने वाले निवेश से प्रदेश में रोजगार के क्षेत्र में अवसरों की बाढ़ आने वाली है। राजस्थान आने वाले विभिन्न देशों के प्रतिनिधि, देश-विदेश की अपने-अपने क्षेत्र की दिग्गज कम्पनियां राजस्थान में निवेश के लिए उत्सुक हैं। कहा जा सकता है कि राजस्थान में यह दीपावली आने वाले महीनों में भी जारी रहेगी और आप सभी उत्साह, उमंग और उल्लास के इस त्योहार के भी साक्षी होंगे। इसी विश्वास और दीपावली की अनन्त शुभकामनाओं के साथ अक्टूबर माह का यह अंक आप सुधि पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है।

(सुनील शर्मा)
प्रधान संपादक

RISING
RAJASTHAN

REPLETE • RESPONSIBLE • READY

भरपूर अवसर, भरे सरोवर

नव अवसरों और संभावनाओं की पहचान लिए राजस्थान आने वाले दिनों में एक बड़े परिवर्तन का साक्षी बनने जा रहा है। अगर प्रकृति साथ दे तो मानवीय प्रयासों को और प्रोत्साहन मिल जाता है। राजस्थान में कुछ ऐसा ही घटित हो रहा है। अच्छे मानसून के कारण इस वर्ष प्रदेश के लगभग सभी छोटे-बड़े बांध छलक रहे हैं, बड़े भू-भाग में भूजल में भी अभिवृद्धि हुई है। इन बांधों पर निर्भर पशु-पक्षी, किसान, आमजन सभी को काफी समय के लिए पानी का सुभीता हो गया है। कई बांध ईको-ट्यूरिज्म साइट के रूप में उभर रहे हैं, जो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के लिए वरदान साबित होंगे।

राज्य सरकार ने प्रदेश में गिरी एक-एक बूंद को सहेजने और उसके सदुपयोग के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री जी की अनूठी पहल 'कैच द रेन' कैम्पेन जैसे नवाचार हों, संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी, यमुना जल समझौता, देवास परियोजना या मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, सभी ऐसे ही प्रयास हैं। सिंचाई, पेयजल, औद्योगिक क्षेत्रों और इकाइयों, निर्माण परियोजनाओं सरीखी सभी आवश्कताओं हेतु पर्याप्त जल उपलब्धता के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। इधर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के रूप में एक ऐसा गेम चेन्जर इवेंट प्रदेश में 9 से 11 दिसम्बर तक होने जा रहा है जो प्रदेश में निवेश के अब से पहले की सभी उपलब्धियों को छोटा कर देगा। मुख्यमंत्री देश-दुनिया को यह बताने में सफल हुए हैं कि अब राजस्थान नए अवसरों, नवाचारों और निवेश संभावना की धरती है। वह समय बीत गया जब अवसरों की कमी और कठोर प्रकृति से जूझते यहां के लोगों को प्रदेश से निकलकर देश-विदेश में मौके तलाशने की जरूरत पड़ी, हालांकि राजस्थान के वासियों ने देश-दुनिया में अपनी लगन, मेहनत और मेधा से व्यापार और हर क्षेत्र में बड़ा नाम किया।

मुख्यमंत्री ने स्वयं जापान, कोरिया, जर्मनी, यूनाईटेड किंग्डम की यात्राएं कीं, राज्य सरकार के कई मंत्री मिडिल ईस्ट और अन्य देशों में राइजिंग राजस्थान का संदेश और आमंत्रण लेकर पहुंचे। भारत के साथ ही विभिन्न देशों के राजनयिक, उद्योगपति, निर्माण, ऑटोमोबाइल, लॉजिस्टिक, आईटी कम्पनियों सहित विविध क्षेत्र से जुड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स, प्रवासी, अनिवासी राजस्थानी, सेवानिवृत्त ब्यूरोकेट्स, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रतिनिधि सहित कोई भी वर्ग, क्षेत्र इस आयोजन से जुड़े बिना नहीं रहा। अन्तरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, जिला, विभाग, सेक्टर सभी स्तरों पर इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सतत प्रयास जारी हैं। ●

मानसून की मेहरबानी से छलके

मरुधरा के बांध

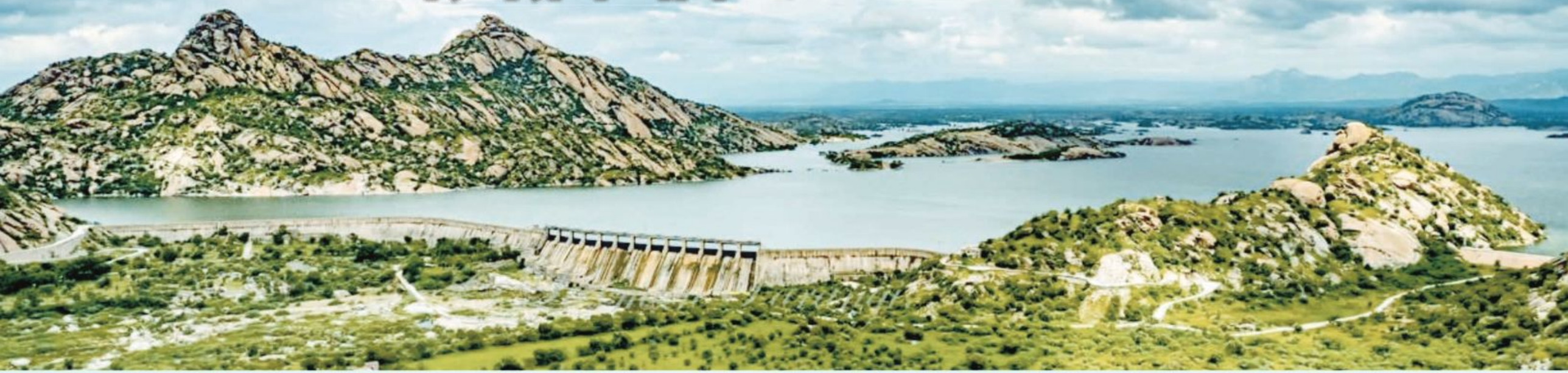

अभय सिंह, सहायक जनसंपर्क अधिकारी

राजस्थान को विशाल भौगोलिक विस्तार के साथ प्रकृति से विषम भौगोलिक एवं जलवायु परिस्थितियां मिली हैं। प्रदेश के लगभग 61 प्रतिशत भू-भाग पर गर्म एवं रेतीला थार मरुस्थल विस्तृत है। वहीं, अरावली पर्वतमाला का अरब सागरीय मानसूनी पवनों के समानांतर विस्तार होने के कारण पश्चिमी राजस्थान में वर्षा न्यूनतम होती है। पश्चिमी जिलों में अकालसम स्थितियां बारंबारता से दिखाई देती हैं। यहां पानी की कम उपलब्धता इसी से जानी जा सकती है कि राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 10.4 प्रतिशत होने के बावजूद यहां सतही जल की उपलब्धता मात्र 1. 16 प्रतिशत ही है। इसमें भी राज्य की सीमा के भीतर उपलब्ध सतही जल 25.38 बीसीएम है और विभिन्न अंतरराज्यीय संधियों से आवंटित जल 17.88 बीसीएम है। प्रदेश की विपरीत भौगोलिक परिस्थितियां, बारंबार अल्पवर्षा की स्थिति, जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ती जलापूर्ति की मांग, वर्षा की मात्रा में कमी एवं कृषि के लिए अत्यधिक भूजल दोहन जल संकट की स्थिति को अधिक विकट बना देता है।

राज्य सरकार पड़ोसी राज्यों के साथ एमओयू कर संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी, देवास, शेखावाटी में यमुना जल और मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना 2.0 एवं अन्य परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में बेहतर जल प्रबन्धन के लिए काम कर रही है। लेकिन तब भी वर्तमान और निकट भविष्य में वर्षा पर ही प्रदेश की जल उपलब्धता काफी हद तक निर्भर रहने वाली है।

राजस्थान में जल संग्रहण, प्रबंधन एवं संरक्षण के अनूठे उदाहरण परम्परागत जल स्रोत कुएं, बावड़ी, खड़ीन एवं झील के रूप दिखाई देते हैं। यहां की संस्कृति एवं जनमानस में जल की महत्ता गांव या शहर के नाम के साथ जुड़े 'सर' प्रत्यय (लूणकरणसर, कतरियासर एवं रामसर इत्यादि) गांव या शहर में स्थित सरोवर का पर्याय हैं। राजस्थान में वर्षा जल एवं भू-जल पर निर्भरता अधिक है। इस बार का मानसून मरुधरा के लिए वरदान साबित हुआ है, प्रदेश में वर्षा का सामान्य औसत 455 मिमी रहता है। इस बार अच्छी वर्षा के चलते 1 जून से 30 सितंबर 2024 के दौरान वर्षा का औसत 703 मिमी रहा। इस बार रिकॉर्ड बारिश होने से प्रदेश के बांध एवं नदियों में पानी की आवक अच्छी मात्रा हुई और इसी अच्छे मानसून की बदौलत प्रदेश के अधिकतर बांध सौ फीसदी तक भर चुके हैं।

बांधों की वर्तमान स्थिति

राजस्थान में सभी बांधों की जल भराव क्षमता 12900.817 मिलियन क्यूबिक मीटर है। वर्तमान में इन बांधों में जल भराव 11285.461 मिलियन क्यूबिक मीटर है, जो कुल क्षमता का 87.48 फीसदी है। यह सितंबर 2023 में 74.79 फीसदी से 12.69 फीसदी अधिक है। राजस्थान के बड़े, मध्यम एवं छोटे 283 बांधों में 180 पूर्ण रूप भरे, 67 आंशिक रूप से भरे एवं 36 बांध खाली हैं। वहीं, 408 लघु बांधों में 226 पूर्ण रूप से भरे, 97 आंशिक रूप से भरे और 85 बांध खाली हैं।

प्रदेश के प्रमुख बांध

राजस्थान राज्य में बड़े बांधों की संख्या 22 है, जिनकी सम्मिलित जल भराव क्षमता 8104.656 मिलियन क्यूबिक मीटर है, इनमें वर्तमान में 7787.498 मिलियन क्यूबिक मीटर जल भराव है जो कुल क्षमता का 96.09 प्रतिशत है।

राणा प्रताप सागर बांध

राणा प्रताप सागर बांध (रावतभाटा, चित्तौड़गढ़) चम्बल नदी पर चूलिया जलप्रपात के निकट निर्मित है। इस बांध की जल भराव क्षमता 2905.230 मिलियन क्यूबिक मीटर है। इसमें वर्तमान में जल भराव 2904.245 मिलियन क्यूबिक मीटर है जो कुल क्षमता का 99.97 फीसदी है। इस बांध पर चंबल घाटी परियोजना के तहत राजस्थान एवं मध्य प्रदेश का साझा पन विद्युतगृह स्थापित किया गया है, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 172 मेगावाट है। साथ ही इस बांध से रावतभाटा स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र को भी जलापूर्ति की जाती है।

जयसमंद बांध

यह बांध नव निर्मित सलूंबर जिले में गोमती नदी पर अवस्थित है। इस बांध की जल भराव क्षमता 415.130 मिलियन क्यूबिक मीटर है। वर्तमान में जल भराव 268.540 मिलियन क्यूबिक मीटर है जो कुल क्षमता का 64.69 फीसदी है।

माही बजाज सागर बांध

माही नदी पर बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले के आदिवासी किसानों को 80,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए इस बांध का निर्माण बांसवाड़ा के निकट बोरखेड़ा गांव में किया गया है। बांसवाड़ा जिले के समग्र भू-भाग का लगभग 20 प्रतिशत माही बजाज सागर बांध के जल ग्रहण क्षेत्र में स्थित है। इस बांध की जल भराव क्षमता 2180.409 मिलियन क्यूबिक मीटर है, जो वर्तमान 100 फीसदी भरा हुआ है।

बीसलपुर बांध

बीसलपुर बहुउद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत टोंक जिले की टोड़ारायसिंह तहसील के पास बीसलपुर गांव में बनास नदी पर इस बांध का निर्माण करवाया गया है। इस बांध से जयपुर, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर एवं टोंक जिलों को पेयजल सुविधा तथा टोंक जिले के किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है। इस बांध की जल भराव क्षमता 1095.840 मिलियन क्यूबिक मीटर है, वर्तमान में यह बांध 100 फीसदी भरा हुआ है।

जाखम बांध

जाखम बांध प्रतापगढ़ जिले में सोम नदी की सहायक जाखम नदी पर अनोपपुरा गांव में अवस्थित है। इस बांध की जल भराव क्षमता 142.030 मिलियन क्यूबिक मीटर है, वर्तमान में यह बांध पूर्ण रूप से भरा हुआ है।

पार्वती बांध

धौलपुर जिले में पार्वती नदी पर निर्मित इस बांध की जल भराव क्षमता 120.880 मिलियन क्यूबिक मीटर है। वर्तमान में जल भराव 120.610 मिलियन क्यूबिक मीटर है जो कुल क्षमता का 99.78 फीसदी है।

जवाई बांध

यह पाली जिले में अवस्थित पश्चिमी राजस्थान का महत्वपूर्ण बांध है। जवाई बांध का निर्माण वर्ष 1957 में जवाई नदी पर प्रमुख सिंचाई परियोजना के रूप में किया गया था। यह बांध 38,671 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई के लिए बनाया गया था। इसके बाद पाली और सिरोही में पीने के पानी की कमी के कारण हर साल संगृहीत पानी का कुछ हिस्सा पीने के लिए आरक्षित कर शेष जल सिंचाई के लिए उपलब्ध कराया जाता है। जवाई बांध की सकल क्षमता 207.510 मिलियन क्यूबिक मीटर है। वर्तमान में जल भराव 185.435 मिलियन क्यूबिक मीटर है जो कुल क्षमता का 89.36 फीसदी है।

कोटा बैराज

कोटा बैराज का निर्माण कोटा नगर के निकट चम्बल नदी पर 1954 में किया गया। इस बांध से सिंचाई के लिए दो नहरें निकाली गई हैं। इन नहरों से कोटा, बूंदी, बारां, टोंक, सवाई माधोपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। इस बांध की कुल जल भराव क्षमता 112.060 मिलियन क्यूबिक मीटर है, वर्तमान में जल भराव 110.830 मिलियन क्यूबिक मीटर है जो कुल क्षमता का 98.90 फीसदी है।

सोम कमला अंबा बांध

डूंगरपुर जिले में अवस्थित इस बांध की जल भराव क्षमता 172.500 मिलियन क्यूबिक मीटर है। वर्तमान में जल भराव 170.170 मिलियन क्यूबिक मीटर है जो कुल क्षमता का 98.65 फीसदी है।

अन्य प्रमुख बांध

इस बार अच्छे मानसून के कारण प्रदेश के अन्य प्रमुख बांध टोंक स्थित गलवा एवं टोरड़ीसागर, दौसा स्थित मोरेल बांध, बांसवाड़ा स्थित हारो बांध, पाली स्थित सरदारसमंद और बूंदी स्थित गुढ़ा बांध में कुल क्षमता का शत-प्रतिशत जल भराव हुआ है। वहीं कोटा स्थित जवाहर सागर बांध में कुल क्षमता का 95.77 फीसदी, दूदू के छापरवाड़ा बांध में 97.17 फीसदी और भीलवाड़ा स्थित मेजा बांध में कुल क्षमता का 65.95 फीसदी जल भराव हुआ है।

राजसमन्द बांध

राजसमन्द जिले में अवस्थित इस बांध की कुल जल भराव क्षमता 107.280 मिलियन क्यूबिक मीटर है, वर्तमान में जल भराव 87.529 मिलियन क्यूबिक मीटर है जो कुल क्षमता का 81.59 फीसदी है।

प्रदेश के मध्यम एवं छोटे बांध

राज्य में मध्यम एवं छोटे बांधों की संख्या 261 है जिनकी जलभराव क्षमता 4.25 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक है। इन बांधों की कुल जल भराव क्षमता 3972.223 मिलियन क्यूबिक मीटर है। वर्तमान में इन बांधों में 2944.032 मिलियन क्यूबिक मीटर जल भराव है जो कुल क्षमता का 74.12 फीसदी है। राजस्थान में बरेठा बांध भरतपुर, रामसागर बांध धौलपुर, माशी बांध टोंक, बांकली बांध जालौर, गरदडा बांध बूंदी, झालावाड़ स्थित छापी, भीमसागर, राजगढ़, कालीसिंध, चोली एवं गागरिन बांध, कोटा स्थित नवनेरा बैराज, आलनिया एवं तकली बांध, प्रतापगढ़ का वागन बांध, भीलवाड़ा के खारी एवं सरेरी बांध, चित्तौड़गढ़ के गंभीरी, ओरई एवं मातृकुंडिया बांध, शाहपुरा स्थित अरवर बांध और उदयपुर स्थित सेई, सोम कागदर, बड़गांव एवं उदयसागर प्रमुख मध्यम श्रेणी के बांध है।

प्रदेश के लघु बांध

राजस्थान में 4.25 मिलियन क्यूबिक मीटर क्षमता से कम के लघु बांधों की संख्या 408 है, जिनकी जलभराव क्षमता 823.938 मिलियन क्यूबिक मीटर है। वर्तमान में इन बांधों का जल भराव 553.930 मिलियन क्यूबिक मीटर है जो कुल क्षमता का 67.23 फीसदी है।

जल संसाधन विजन-2045

जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2045 तक जल संसाधन के सतत विकास एवं अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए रोडमैप तैयार किया गया है। इसके लक्ष्य हैं: राजस्थान को जल संसाधनों के प्रबंधन में अग्रणी प्रदेश बनाना, साथ ही सृजित सिंचाई क्षमता का पूर्ण उपयोग एवं प्रति इकाई जल में अधिकतम फसल उत्पादन करना, नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जल संसाधन का संग्रहण, संरक्षण एवं समुचित प्रबंधन सुनिश्चित करना, साथ ही प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर सूखा एवं बाढ़ का प्रबंधन करना। विभाग द्वारा प्रदेश के सभी बांधों की प्रभावी मॉनिटरिंग के माध्यम से रियल टाइम डाटा अपडेट किया जाता है। ●

माही बजाज सागर बांध

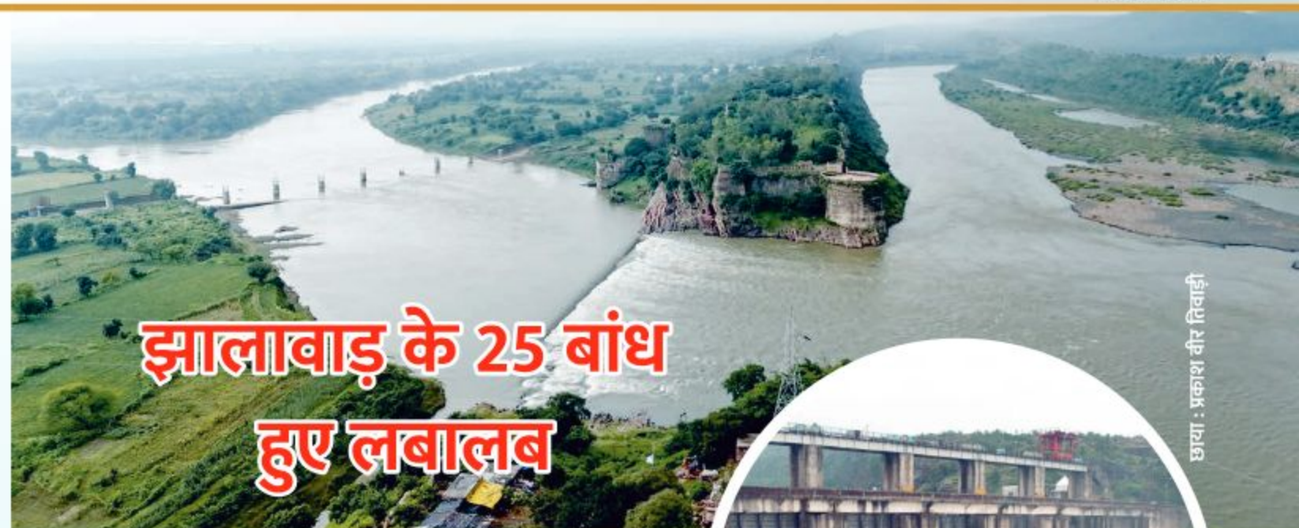

छाया : प्रकाश वीर तिवाड़ी

झालावाड़ के 25 बांध हुए लबालब

इस वर्ष सिंचाई के लिए नहीं होगी पानी की कमी

सम्पूर्ण प्रदेश में इस वर्ष मानसून के दौरान बहुत अच्छी वर्षा होने से नदियों एवं तालाबों में पानी की भरपूर आवक हुई है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार गत 14 सितम्बर को जलझूलनी एकादशी के अवसर पर सम्पूर्ण प्रदेश में पूर्ण रूप से भरे सभी बांधों, नदी एवं तालाबों पर "राजस्थान जल महोत्सव-2024" मनाया गया।

राजस्थान के चेरापूंजी के नाम से मशहूर झालावाड़ जिले में प्रति वर्ष होने वाली औसत वर्षा 950 एमएम है। अच्छी वर्षा से जिले के अधिकतर जलाशय पानी से लबालब भरे हुए हैं। इसका एक कारण पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश में हुई बारिश भी है। जल संसाधन विभाग के अनुसार जिले में पानी की अच्छी आवक से इस बार सिंचाई के लिए पानी का संकट नही आएगा। जिले के 31 में से 25 बांध पानी से पूर्ण रूप से भरे हुए हैं जबकि अन्य 6 बांध भी लगभग 90 प्रतिशत भर चुके हैं।

जिले के गागरीन, चंवली, कालीसिंध, कालीखार, भीमनी, रेवा, कनवाड़ा, सारनखेड़ी, रोशनबाड़ी, गुराड़िया, गणेशपुरा, मोगरा, जसवंतपुरा, बिनायगा, राजपुरा, बिस्तुनिया, कंवरपुरा, बोरबंद, छापी, भीमसागर एवं राजगढ़ बांधों के गेट खोलने से नदियों में पानी की आवक हुई है। जिले के 31 बांधों की क्षमता 526.49 मिलीयन क्यूबिक मीटर है। बांधों मे करीब 480 मिलीयन क्यूबिक मीटर से अधिक पानी आया है जो पिछले साल की बारिश से 22 फीसदी अधिक है। इसके अतिरिक्त जिले में स्थित कई अन्य तालाब भी पानी से सराबोर हैं, जिनमें खण्डिया तालाब, नया तालाब एवं गोमती सागर तालाब आदि शामिल हैं। ●

अनुप्रिया, सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी

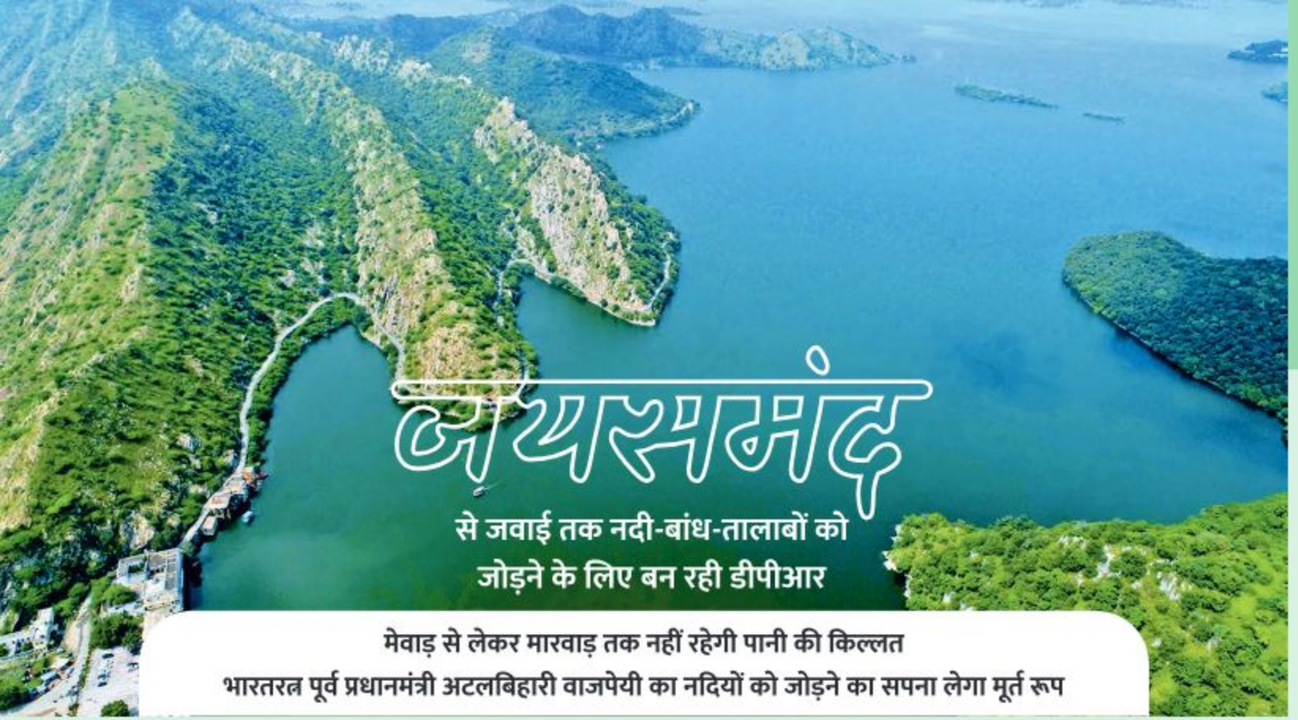

जयसमंद

से जवाई तक नदी-बांध-तालाबों को जोड़ने के लिए बन रही डीपीआर

मेवाड़ से लेकर मारवाड़ तक नहीं रहेगी पानी की किल्लत

भारतरत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी का नदियों को जोड़ने का सपना लेगा मूर्त रूप

विनय सोमपुरा, सहायक जनसम्पर्क अधिकारी

भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नदियों को जोड़ कर अकाल और बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान के सपनों को साकार करने की दिशा में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। मुख्यमंत्री की पहल से मेवाड़-वागड़ के बांध-तालाब व नदियों को जोड़ते हुए एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जयसमंद से मारवाड़ की जीवन रेखा कहे जाने वाले जवाई बांध तक पानी ले जाने के लिए विस्तृत कार्ययोजना (डीपीआर) तैयार की जा रही है। जल संसाधन विभाग ने इसके लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। इस परियोजना के पूर्ण होने पर न केवल मेवाड़ और वागड़ अपितु मारवाड़ क्षेत्र में भी कभी पानी की किल्लत नहीं रहेगी।

बजट में घोषणा

राज्य सरकार ने बजट 2024-25 में वागड़-मेवाड़ में नदी बेसिन से जुड़ी दो परियोजनाओं के तहत डीपीआर बनवाने की घोषणा की है। बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के बिन्दु संख्या 113/1/2 के अन्तर्गत माही बेसिन की जाखम नदी एवं बांध के अधिशेष जल को फीडर के माध्यम से जयसमंद बांध में लाकर चित्तौडगढ़ एवं भीलवाड़ा के बांधों को भरने संबंधी कार्य की डीपीआर के लिए 30 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया। अनुमानित 7100 करोड़ रुपए की इस परियोजना से उदयपुर, चित्तौडगढ़ एवं भीलवाड़ा में पेयजल तथा लगभग 70 हजार हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र का पुनर्स्थापन हो सकेगा। बजट घोषणा 2024-25 के बिन्दु संख्या 113/1/3 के अंतर्गत माही एवं सोम नदी का मानसून अवधि का अधिशेष जल जयसमंद बांध सहित अन्य बांधों को भरते हुए जंवाई बांध तक लाने संबंधी कार्य की डीपीआर के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 7000 करोड़ की अनुमानित लागत वाली परियोजना उदयपुर, सिरोही, पाली और जोधपुर में पेयजल तथा 16 हजार हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र के पुनर्स्थापन का आधार बन सकती है।

जाखम की बढ़ेगी क्षमता, जयसमंद को मिलेगा अतिरिक्त पानी

बजट घोषणा बिन्दु संख्या 113/1/2 के तहत तैयार की जा रही परियोजना में प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर बने जाखम बांध से जयसमंद तथा जयसमंद से चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिलों के विभिन्न बांधों को जोड़ते हुए पानी पहुंचाना प्रस्तावित है। जल संसाधन विभाग, उदयपुर के अतिरिक्त मुख्य अभियंता ऋषभ जैन ने बताया कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार जाखम बांध में प्रतिवर्ष 7000 एमसीएफटी पानी की आवक है। वर्तमान में जाखम बांध की कुल भराव क्षमता 5015 एमसीएफटी है, जिससे धरियावाद तहसील के 117 गांव एवं प्रतापगढ तहसील के 3 गांव में सिंचाई की जाती है। इस परियोजना का कुल सी.सी.ए. 28,319 हैक्टेयर एवं आईसोए 23,505.00 हैक्टेयर है। जाखम बांध पर 3 मीटर ऊंचे रेडियल गेट लगाने के प्रस्ताव हैं, जिससे इस बांध पर 1,000 एमसीएफटी अतिरिक्त पानी का भराव किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जाखम नदी की सहायक नदी सुकली एवं करमाई नदी पर बांध बनाकर क्रमशः 1.000 एमसीएफटी एवं 750 एमसीएफटी पानी का भराव किया जा सकता है। जाखम बांध तथा सलूम्बर जिले में स्थित जयसमंद झील के जल स्तर पर 60 मीटर का अंतर है। इससे कुल 2,750 एमसीएफटी अतिरिक्त पानी जाखम बांध से करीब 106 किलोमीटर लंबी फीडर बनाकर जयसमन्द झील में ग्रेविटी से लाया जा सकेगा।

जयसमंद झील से बड़गांव बांध (जिला उदयपुर) तक 50 कि.मी. लम्बे पाइपलाइन सिस्टम से 178.50 मीटर लिफ्ट के माध्यम से पानी पहुंचाया जाना प्रस्तावित है। बड़गांव बांध से 42 कि.मी. लम्बी फीडर बनाकर इस पानी को रेलमगरा नाले (जिला राजसमंद) में डाला जाएगा। रेलमगरा नाले से पूर्व निर्मित फीडर सिस्टम द्वारा पानी धमाणा बांध, चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन बांध, भूपालसागर बांध, अरनिया बांध, जाशमा बांध, डिण्डोली, मातृकुण्डिया, सिंहपुर एवं बनाकिया बांध को भरा जा सकेगा। मातृकुण्डिया बांध से पूर्व में निर्मित मेजा फीडर के माध्यम से मेजा बांध तक जल अपवर्तन किया जाएगा। इसके अलावा नंदसमंद तक पानी पहुंचाने का भी प्रस्ताव है।

माही, सोम व अनास का अधिशेष पानी जाएगा जवाई तक

बजट घोषणा बिन्दु संख्या 113/1/3 के तहत तैयार की जा रही परियोजना में माही, सोम और अनास नदियों का अधिशेष जल जवाई बांध तक पहुंचाना प्रस्तावित है। इसके तहत अनास नदी, माही नदी और सोम नदी के अधिशेष पानी को ट्रेप करके जयसमंद झील तक पहुंचाया जाएगा। वहां से अतिरिक्त पानी को सेई बांध में पहुंचाया जाएगा। सेई टनल के माध्यम से पानी जवाई बांध तक पहुंचाया जा सकेगा। सेई टनल की गहराई बढ़ाकर टनल क्षमता का विस्तार किया जा चुका है।

इसलिए पड़ी जरूरत

राजस्थान में कहीं अधिक तो कहीं न्यून वर्षा की स्थिति रहती है। प्रदेश के दक्षिणांचल में अपेक्षाकृत अच्छी बारिश होती है। माही, सोम व जाखम नदियों पर बने बांध करीब-करीब प्रति वर्ष ओवरफ्लो होते हैं तथा अधिशेष पानी बहकर गुजरात चला जाता है। दूसरी ओर मेवाड़ और मारवाड़ के कई क्षेत्रों में कम बारिश के चलते वर्ष पर्यन्त पानी की समस्या रहती है। इसलिए माही, सोम और जाखम बांधों के अधिशेष जल को संचित कर वागड़-मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र के अन्य तालाबों-बांधों के पुनर्भरण की परियोजना प्रस्तावित की गई है, ताकि क्षेत्र में पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के साथ-साथ सिंचाई सुविधाओं का भी विस्तार किया जा सके। ●

नदियों की इंट्रास्टेट लिंकिंग, जन सहभागिता से जल संचय को मिले बढ़ावा : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जल संसाधन, इंदिरा गांधी नहर एवं सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग से संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया है कि प्रदेश में इंट्रास्टेट नदियों को जोड़ने कार्य व्यापक स्तर पर किया जाए एवं जन सहभागिता के माध्यम से जल संचय को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए माही बेसिन की जाखम नदी एवं बांध के अधिशेष जल को जयसमंद बांध से जोड़ने तथा माही व सोम नदी के अधिशेष जल को जवाई बांध तक लाने की बजट घोषणाओं की प्रोजेक्ट रिपोर्ट आगामी 4 माह में तैयार करने, राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर बांध के जल अपवर्तन कार्य की बजट घोषणा की अनुपालना में ब्राह्मणी नदी पर बनाए जाने वाले बांध के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने डूंगरी बांध एवं ईसरदा बांध के ऊपरी भाग में फ्लेप निर्माण एवं विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में निर्देश दिए कि जल संग्रहण के लिए बांध निर्माण तथा जलापूर्ति के लिए नहर निर्माण के कार्य एक साथ ही कर लिए जाए। उन्होंने आईजीएनपी मुख्य नहर पर बने प्राकृतिक डिप्रेशन्स को जलाशयों में परिवर्तित किए जाने, संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी प्रथम चरण की समीक्षा करते हुए नीमराणा एवं घिलोट जापानी औद्योगिक क्षेत्र के लिए जल उपयोगिता के बिंदुओं को शामिल करने निर्देश दिए। ●

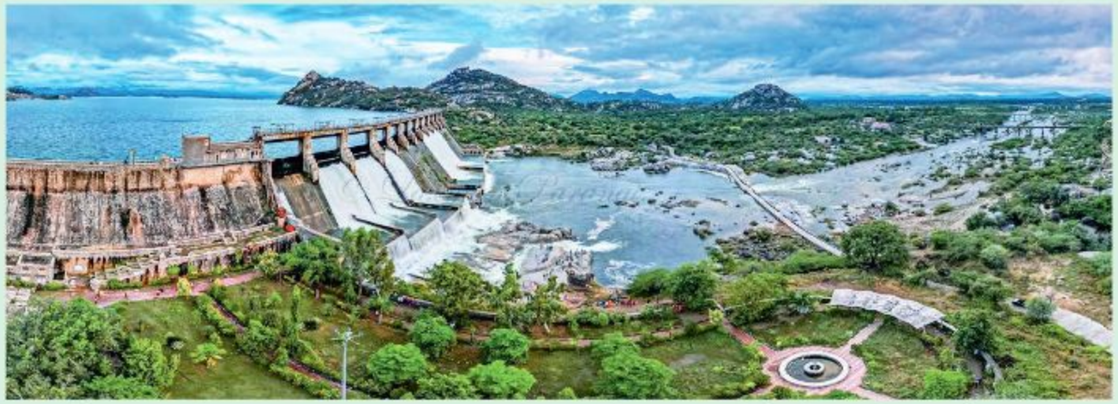

प्रदेश का ऊर्जा और सिंचाई स्तंभ

राणा प्रताप सागर

आकांक्षा शर्मा, सहायक जनसंपर्क अधिकारी

राजस्थान में स्थित राणा प्रताप सागर बांध, चंबल नदी पर बने चार प्रमुख बांधों की शृंखला का दूसरा वृहद बांध है। यह चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा के पास स्थित है और राजस्थान की ऊर्जा और सिंचाई परियोजनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इस बांध का निर्माण चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत किया गया था, जो एक अंतरराज्यीय परियोजना है। यह बांध चंबल नदी पर राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना का हिस्सा है। इस शृंखला में क्रमशः गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज शामिल हैं।

निर्माण और उद्देश्य

राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण 1970 में पूरा हुआ था। इसका नाम महान राजपूत योद्धा महाराणा प्रताप के सम्मान में रखा गया, जो अपनी वीरता और स्वातंत्र्य के लिए जाने जाते हैं। इसके निर्माण का मुख्य उद्देश्य जलविद्युत उत्पादन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण है।

तकनीकी विशेषताएं

राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के सबसे वृहद बांधों की श्रेणी में आता है, जिसकी भंडारण क्षमता 2,905.230 मिलियन घन मीटर है। यह बांध पत्थर की चुनाई से निर्मित है और इसकी कुल लंबाई 1,143 मीटर है, जबकि इसकी अधिकतम ऊंचाई 53.95 मीटर (177 फीट) है। इसमें 17 बड़े क्रेस्ट गेट्स (60'x28') और 4 स्लूस गेट्स (9.5'x11.5') लगे हुए हैं। इस बांध के स्पिलवे की लंबाई 362.71 मीटर है। बांध से जुड़े पन बिजलीघर में 43 मेगावाट की चार यूनिट्स हैं, जो कुल 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती हैं जिसका उपयोग कोटा बैराज की नहरों से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए भी किया जाता है, जिससे राजस्थान और मध्य प्रदेश के 4.58 लाख हक्टेयर कृषि क्षेत्र को सिंचित किया जाता है।

चंबल बहुउद्देशीय परियोजना का हिस्सा

राणा प्रताप सागर बांध, चंबल नदी पर बने चार प्रमुख बांधों में दूसरा वृहद बांध है। चंबल नदी पर स्थित गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज बांधों की शृंखला राजस्थान और मध्य प्रदेश के कृषि, ऊर्जा और जल संसाधनों को प्रबंधित करती है। इन बांधों से नहरें सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती हैं और क्षेत्र की खेती को सींचती हैं। राणा प्रताप सागर बांध की निर्माण क्षमता और भंडारण क्षमता इसे राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण बांध बनाती है।

जलाशय और पर्यावरणीय प्रभाव

बांध के जलाशय का क्षेत्रफल लगभग 199 वर्ग किलोमीटर है, बांध का जलाशय न केवल सिंचाई के लिए जल प्रदान करता है बल्कि रावतभाटा परमाणु विद्युत गृह के लिए भी जल आपूर्ति करता है। इससे राज्य सरकार को प्रति वर्ष लगभग 25 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है। इसके अलावा, रामगंजमंडी-पचपहाड़ पेयजल परियोजना और भीलवाड़ा चंबल पेयजल परियोजना से भी राजस्व प्राप्त होता है, जिससे यह अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में भी अपना प्रभावी योगदान देता है।

मरुधरा के बांध

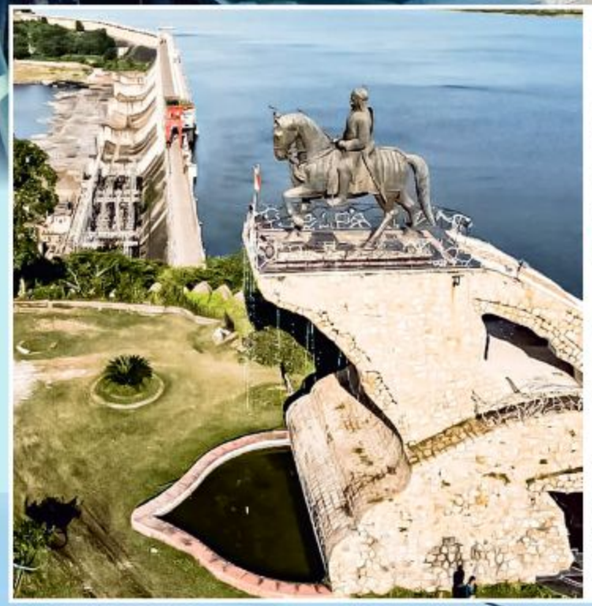

आर्थिक और सामाजिक प्रभाव

राणा प्रताप सागर बांध ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कृषि उत्पादन को सुदृढ़ किया है। इससे सिंचित भूमि का विस्तार हुआ है, जिससे किसानों की आजीविका में सुधार हुआ है। साथ ही, जलविद्युत उत्पादन ने औद्योगिक और घरेलू बिजली की मांग को पूरा किया है, जिससे क्षेत्र के आर्थिक विकास को बल मिला है।

पर्यटन और सांस्कृतिक महत्व

राणा प्रताप सागर बांध एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। इसके जलाशय की विशालता, आस-पास के हरियाली से भरे दृश्य और बांध की इंजीनियरिंग भव्यता पर्यटकों को आकर्षित करती है। इसके निकट भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य का भी दौरा किया जा सकता है, जो विभिन्न वन्यजीवों का घर है।

राणा प्रताप सागर बांध न केवल राजस्थान के लिए ऊर्जा और सिंचाई का महत्वपूर्ण स्रोत है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और पर्यावरणीय धरोहर भी है। इसके निर्माण से क्षेत्र की कृषि, जल और ऊर्जा संसाधनों में व्यापक सुधार हुआ है। महाराणा प्रताप के सम्मान में स्थापित यह बांध सशक्त, आत्मनिर्भर राजस्थान के गौरव का प्रतीक भी है। •

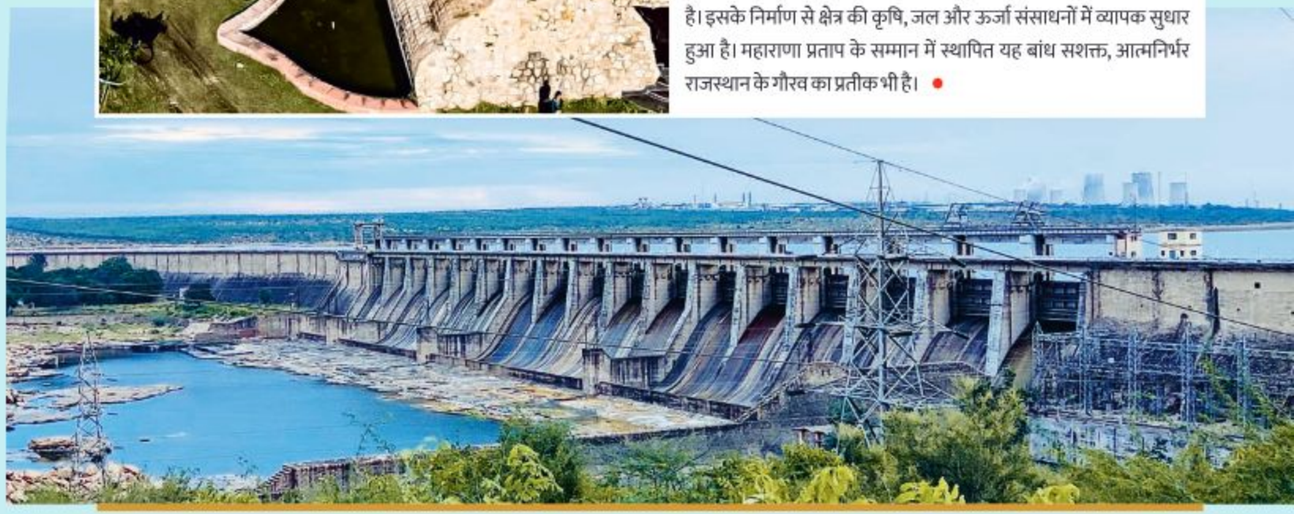

क्षेत्र की लाइफलाइन है कोटा बैराज

भारत रत्न गौड़, अधिशाषी अभियंता
जल संसाधन (से.नि.)

कोटा बैराज चंबल नदी पर स्थित एक प्रमुख बांध है। जिसका प्रमुख उद्देश्य सिंचाई, जल प्रबंधन, और बाढ़ नियंत्रण है। कोटा बैराज का निर्माण 1960 के दशक में हुआ था और यह राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में से एक है। यह कई वर्षों से राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसानों के लिए जीवन रेखा साबित हुआ है, क्योंकि इससे विशाल क्षेत्र की कृषि भूमि को पानी मिलता है। इसके अलावा, कोटा बैराज कोटा शहर के पर्यटन स्थलों में भी गिना जाता है, जहां लोग इसका सुंदर दृश्य देखने आते हैं।

चंबल घाटी विकास परियोजना चंबल नदी की ऊर्जा और पानी के उपयोग को नियंत्रित करते हुए राजस्थान एवं मध्य प्रदेश राज्यों की समृद्धि एवं खुशहाली हेतु तीन चरणों में प्रस्तावित की गई थी, जिसमें चार बड़े बांध गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज शामिल हैं। कोटा बैराज इन बांधों से निकले पानी को वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रथम चरण के अंतर्गत चंबल नदी के पानी का सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण एवं विद्युत उत्पादन में उपयोग करने के लिए मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा पर गांधी सागर बांध और राजस्थान के कोटा शहर में कोटा बैराज का निर्माण कार्य किया गया। कोटा बैराज से निकलने वाली दाईं और बाईं मुख्य नहर का निर्माण कार्य भी इसी चरण में प्रारंभ किया गया। दाईं मुख्य नहर का संचालन राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

कोटा बैराज चम्बल नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना का अंतिम कम्पोजिट स्ट्रक्चर है। कोटा बैराज का निर्माण वर्ष 1953-1960 के मध्य में कोटा शहर के नजदीक नदी का जल स्तर ऊंचा कर दाईं व बाईं मुख्य नहरों में जल प्रवाहित करने के लिये किया गया। कोटा बैराज में अतिरिक्त जल निकासी के लिये 19 रेडियल गेट और 2 स्लूयस गेट लगे हुए हैं। इनकी अधिकतम जल निकासी क्षमता 7 लाख 50 हजार क्यूसेक है। कोटा बैराज के पानी की कुल भराव क्षमता अधिकतम जल स्तर 854 फीट पर 112.06 मिलियन क्यूबिक मीटर है।

कोटा बैराज के निर्माण के बाद से राजस्थान और मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। इस बांध से दोनों राज्यों के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। यह परियोजना न केवल पानी की समस्या को हल करने में सहायक साबित हुई, बल्कि इसने बाढ़ की संभावना को भी काफी हद तक कम किया है।

कोटा बैराज को राजस्थान के जल प्रबंधन और कृषि विकास की रीढ़ की हड्डी के रूप में देखा जाता है। इसकी महत्ता केवल जल आपूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रीय आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सिंचाई सुविधा

इसके निर्माण से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। कोटा बैराज द्वारा क्रमशः 2.29 लाख हैक्टेयर भूमि राजस्थान तथा 4.50 लाख हैक्टेयर भूमि मध्यप्रदेश यानी कुल 6.79 लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। राजस्थान के शुष्क इलाकों में यह किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी है।

जलापूर्ति

कोटा बैराज कोटा शहर की जलापूर्ति प्रणाली का प्रमुख स्रोत है। यहां से कोटा एवं बून्दी शहर को पेयजल के साथ कोटा थर्मल एवं डीसीएम, एनटीपीसी अन्ता इत्यादि औद्योगिक इकाइयों को भी जलापूर्ति की जाती है।

बाढ़ नियंत्रण

मानसून के दौरान चंबल नदी में पानी की मात्रा बढ़ जाती है और इस स्थिति में कोटा बैराज बाढ़ के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। यह बांध नदी के जल स्तर को नियंत्रित करके निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को कम करता है।

विद्युत उत्पादन

यद्यपि कोटा बैराज मुख्य रूप से सिंचाई और जल प्रबंधन के लिए बनाया गया है, परंतु यह परियोजना व्यापक चंबल घाटी परियोजना का हिस्सा होने के कारण, इसके आस-पास के बांधों से विद्युत उत्पादन भी होता है।

पर्यटन और सौंदर्य

कोटा बैराज न केवल एक महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग संरचना है, बल्कि यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। इसका सुंदर नजारा और इसके किनारे की हरियाली पर्यटकों को आकर्षित करती है। शाम के समय यहां का दृश्य खासतौर पर अद्भुत होता है, जब सूर्यास्त के समय बैराज पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तब लोग यहां नाव की सवारी का भी आनंद लेते हैं। इसके आस-पास कई और पर्यटन स्थल भी हैं, जैसे कोटा गढ़ महल, चंबल गार्डन, भीतरिया कुण्ड, गरडिया महादेव, घड़ियाल सेंचुरी आदि। हाल ही में कोटा बैराज के नीचे चंबल नदी के दोनों तटों पर नगर विकास न्यास कोटा द्वारा रिवर फ्रंट का निर्माण कराया गया है। ●

मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट अनुबंध शीघ्र
संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल-ईआरसीपी लिंक परियोजना

राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच पिछले दिनों श्रमशक्ति भवन स्थित जल शक्ति मंत्रालय के कार्यालय में पार्वती-कालीसिंध-चंबल-ईआरसीपी लिंक परियोजना के संबंध में त्रिपक्षीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सीआर पाटिल, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि समीक्षा बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से दोनों राज्यों के बीच लंबित विवादों का निवारण कर लिया गया है। शीघ्र ही इस परियोजना का मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट अनुबंध होने वाला है। दोनों राज्यों की जनता के हित में मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि इसी दिशा में दोनों राज्यों में पीकेसी-ईआरसीपी लिंक परियोजना पर बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है और शीघ्र ही इसके परिणाम दिखेंगे। उन्होंने कहा कि बैठक में मध्य प्रदेश एवं राजस्थान से संबंधित विभिन्न विकास कार्यों, जल संसाधन प्रबंधन, सीमावर्ती क्षेत्रों में जल वितरण व्यवस्था तथा दोनों राज्यों के मध्य जल संबंधी मुद्दों पर भी गहन विचार-विमर्श किया गया। ●

तीन दशक बाद चली चादर

छापरवाड़ा बांध

छापरवाड़ा बांध जल संसाधन विभाग का एक वृहद बांध है। यह बांध दूदू जिले की मौजमाबाद तहसील के ग्राम छापरवाड़ा में स्थित है। छापरवाड़ा बांध का निर्माण रियासतकाल में वर्ष 1894 में हुआ था।

छापरवाड़ा बांध की चार मुख्य नहरें हैं, जिनकी कुल लम्बाई 96 किलोमीटर है। बांध की नहरों से दूदू जिले की दूदू, मौजमाबाद एवं फागी तहसील तथा टोंक जिले की मालपुरा तहसील के कुल 52 गांवों की 11,741 हैक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होती है। छापरवाड़ा बांध का कैचमेंट एरिया 824 वर्ग किलोमीटर है एवं बांध का कुल भराव 17 फीट है। इसकी पाल 4,260 मी. लम्बी है।

छापरवाड़ा बांध पर अंतिम बार वर्ष 1995 में चादर चली थी, जिसके बाद इस वर्ष अच्छा मानसून रहने से वर्ष 2024 मे चादर चली है, जिससे इस वर्ष किसानों में उमंग एवं उत्साह का माहौल बना हुआ है। छापरवाड़ा बांध का ओवरफ्लो पानी मासी नदी से होता हुआ टोंक जिले की सीमा में स्थित मासी बांध मे जाता है। इसकी भराव क्षमता 1,236 मीलियन घन फीट (35 मिलियन घन मीटर) है।

संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी में शामिल

छापरवाड़ा बांध पूर्वी नहर परियोजना में शामिल है, इससे बांध में हर वर्ष पानी की उपलब्धता बनी रहेगी। कई बार मानसून कमजोर रहने से बांध में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं होने के कारण सिंचाई के लिए पूरा पानी नही मिल पाता, लेकिन अब बांध के पूर्वी नहर परियोजना से जुड़ने के कारण बांध के सम्पूर्ण कमांड क्षेत्र 11,741 हैक्टेयर की सिंचाई हो सकेगी तथा सरप्लस पानी कालख नहर के माध्यम से जयपुर ग्रामीण जिले की माधोराजपुरा तहसील भी जा सकेगा, जिससे क्षेत्र के किसानों के साथ-साथ आस-पास के क्षेत्रों में भी किसानों को सिचाई की सुविधा प्राप्त होगी।

अभिमन्यु सिंह, सहायक जनसंपर्क अधिकारी

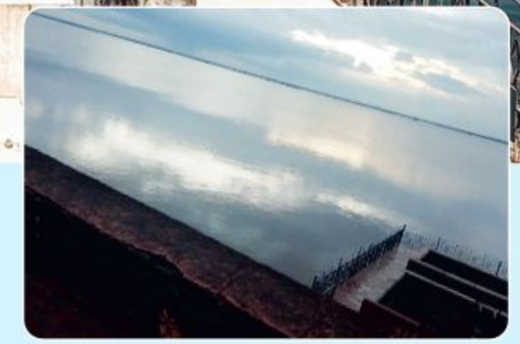

40 करोड़ की लागत से नहरों का नवीनीकरण

वर्ष 1894 मे बांध निर्माण की व्यय राशि 7.03 लाख थी। वर्ष 1995 के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2024-25 मे छापरवाड़ा बांध की नहरों के नवीनीकरण हेतु 40 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गयी है। इसके अंतर्गत नहरों को पक्का करने का कार्य एवं नहरों को सुदृढ़ करने का कार्य किया जायेगा जिससे किसानों को सिंचाई का पानी सही मात्रा मे उपलब्ध करवाया जा सकेगा। ●

सफल नहरी तंत्र का रंगमंच

धन-धान्य की धरा गंगानगर

अनिल शाक्य, सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी

नई से नई वैज्ञानिक तकनीक और खोज होने के बावजूद अभी तक जल अर्थात पानी का कोई विकल्प नहीं बनाया जा सका है। पानी की आवश्यकता जैसी युगों, सदियों और बरसों पहले थी, आज भी बिलकुल वैसी है। इसके न होने पर जहां परेशानियां आती हैं, वहीं उपलब्धता होने पर खुशियां। हाल-फिलहाल का समय ऐसी ही खुशियों वाला है, जहां भौगोलिक विषमताओं वाले राजस्थान में प्रकृति ने इस बार जमकर मेघ बरसाए हैं। इसी की बदौलत एक ओर वर्तमान में प्रदेश के बांधों में जल की पर्याप्त उपलब्धता है, दूसरी ओर बरसाती जल की बदौलत नहरों में भी जल स्तर बढ़ा है।

बांधों और नहरों में पर्याप्त जल होने से आगामी समय में कृषि उत्पादन के अलावा हरियाळो राजस्थान की संकल्पना भी साकार हो सकेगी। इससे आर्थिक संपन्नता के साथ-साथ प्रदेश में खुशियां भी आएंगी। इस संपन्नता और खुशियों में अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा पर बसे श्रीगंगानगर जिले का भी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, भाखड़ा, घग्घर और सिद्धमुख नहर के पानी से सिंचित होने वाले गंगानगर और 1994 में इसी से अलग होकर नया जिला बनने वाले हनुमानगढ़ की आर्थिक संपन्नता का आधार नहरें ही हैं। नहरी पानी की उपलब्धता की वजह से ही गंगानगर धन-धान्य की धरा है। 26 अक्टूबर 2024 को इसी गंगानगर जिले का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ऐसे मौके पर प्रदेश के बांधों और नहरों में जल की पर्याप्त उपलब्धता गंगानगर के लिए दोहरी सौगात से कम नहीं है। स्थापना दिवस पर बीकानेर रियासत के तत्कालीन महाराजा गंगासिंह का स्मरण करते हुए जानते हैं कि रेतीले धोरों में गंगनहर लाकर कैसे उन्होंने रामनगर (गंगानगर जिले का पुराना नाम) को अपना नाम देकर गंगानगर बना दिया।

हमारी गंगनहर, पंजाब की बीकानेर कैनाल

बीकानेर रियासत के महाराजा गंगासिंह की बदौलत ही पंजाब से सटा और भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बसा गंगानगर जिला अपनी स्थापना के समय से ही राजस्थान में अन्न का भंडार और देश में किन्नू उत्पादन के क्षेत्र में अपना उल्लेखनीय स्थान बनाए हुए हैं। महाराजा गंगासिंह द्वारा सतलज नदी पर फिरोजपुर के समीप बने हुसैनीवाला हैड से इस मरुभूमि को सिंचित करने के लिए 1922 से 1927 की अवधि में 330 लाख रुपए की लागत से गंगनहर का निर्माण करवाया गया। पंजाब के क्षेत्र में इस नहर को प्रारंभ से ही बीकानेर कैनाल के नाम से जाना जाता है। बीकानेर रियासत को पानी देने का बहावलपुर रियासत द्वारा विरोध किये जाने के कारण महाराजा गंगासिंह को लगभग 15 वर्ष तक संघर्ष करना पड़ा। ब्रिटिश इंडिया की सरकार के सामने बीकानेर के हित व अधिकार को लेकर वे अपना पक्ष रखते रहे। उन्होंने ब्रिटिश शासन से अपने संबंधों का प्रयोग भी बीकानेर को पानी दिलाने के लिए किया।

इस अवधि में वे भारत की तत्कालीन राजधानी कोलकाता, शीतकालीन राजधानी शिमला, ब्रिटिश पंजाब की राजधानी लाहौर और नई बनने जा रही राजधानी दिल्ली का दौरा कर अधिकारियों को बीकानेर के पक्ष से अवगत करवाते रहे। अंततः महाराजा इसमें सफल रहे और उन्होंने बीकानेर के इस क्षेत्र को सिंचित करने के लिए सहमति प्राप्त कर ली। इसके बाद ब्रिटिश पंजाब, बहावलपुर व बीकानेर के बीच 4 सितंबर 1920 को लिखित समझौता हुआ। नहर के निर्माण में दो वर्ष की अवधि लगी। उसके बाद महाराजा ने धन की व्यवस्था की, तब काम शुरू

ये दुर्लभ फोटो 1927 में गंगनहर के उद्घाटन के अवसर का है। महराजा गंगासिंह जी खेत में जुताई कर रहे हैं, जबकि पण्डित मदन मोहन मालवीय मंत्र जाप कर रहे हैं।

हो पाया। गंगनहर परियोजना का प्रारंभिक सीसीए (कल्चरेबल कमांड एरिया) 5.45 लाख एकड़ था, जिसे 1935 में बढ़ाकर 7.60 लाख एकड़ किया गया।

मूल रूप से इस कैनाल का निर्माण सतलज वैली प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया था। भारतीय सिंचाई आयोग ने 1901 से 1903 में देश के विभिन्न स्थानों के दौरे के पश्चात जो रिपोर्ट दी, उसमें सिंचाई सुविधाओं के विस्तार का सुझाव दिया गया था। बीकानेर रियासत की ओर से इस आयोग के सामने सिंचाई के लिए पानी का दावा किया गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया। बीकानेर कैनाल (गंगनहर) का निर्माण पूरा होने के बाद तब के वायसराय लॉर्ड इरविन ने श्रीगंगानगर आकर 26 अक्टूबर 1927 को इसमें शिवपुर हैड से जल प्रवाहित किया। फिरोजपुर हैडवर्क्स से बीकानेर कैनाल में जलप्रवाह लॉर्ड इरविन ने 26 अक्टूबर 1927 को किया। इसके बाद वे श्रीगंगानगर पहुंचे। यहां शानदार उत्सव का आयोजन किया गया। राजपूताना के अनेक महाराजा, राजा, ब्रिटिश भारत के अनेक अधिकारी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शुमार पंडित मदनमोहन मालवीय (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस के संस्थापक) भी श्रीगंगानगर आये। यह चूने व कंकड़ से बनी विश्व की पहली ऐसी नहर है। नहर की कुल लम्बाई 115.32 किमी है, जिसमें से 98.60 किलोमीटर का हिस्सा पंजाब में और शेष 16.72 किलोमीटर का हिस्सा श्रीगंगानगर (राजस्थान) में है। गंगनहर प्रणाली में नहरों की कुल लम्बाई 1353.93 किलोमीटर है।

सतलज के निर्मल जल और यहां के किसानों के पसीने ने एकमेय होकर इस इलाके को ऐसे हरित भू-भाग में बदल दिया, जिसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि यह कभी रेगिस्तानी क्षेत्र था। गंगनहर क्षेत्र को यदि सैटेलाइट से या गूगल से देखा जाए तो हरियाली की चादर बिछी नजर आती है। यहां के कर्मठ लोगों ने इस जिले के विकास को गति दी। यहां मंडियों की स्थापना हुई। गंगनहर में जल प्रवाह से पहले हालांकि मंडियां नहीं बस पाई थीं, लेकिन जहां-जहां मंडियों की स्थापना की जानी थी, उन प्रमुख स्थानों पर महाराजा गंगासिंह ने रेलवे लाइन का निर्माण कर इसे सूरतगढ़-भटिण्डा लाइन से जोड़ दिया था ताकि जलप्रवाह समारोह में आने वाले अतिथियों व आम नागरिकों को सुविधा रहे।

नहरी विभाग के अभियंताओं ने अथक मेहनत कर वितरिकाओं व मोघों का निर्माण किया। इन अभियंताओं में अंग्रेज अधिकारी और पंजाब के रहने वाले अनुभवी अभियंता शामिल थे। ब्रिटिश भारत की सेवा में रह चुके कई सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी महाराजा गंगासिंह ने उच्च पदों पर रखा। इन सभी के प्रयासों का ही सुफल था कि गंगानगर सिंचाई व अन्न उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी स्थान बना पाया। शुरूआती दौर में नहर में पानी की कमी भी रही, लेकिन किसानों ने उपलब्ध पानी का भरपूर सदुपयोग करते हुए अन्न उत्पादन की अच्छी शुरूआत की। गंगनहर निर्माण से पूर्व यह इलाका बार-बार अकाल की मार झेलता रहा। अकाल तो उसके बाद भी आए, लेकिन इस नहर के कारण किसानों को पहले जैसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा।

देश के विभाजन के पश्चात इस नहर को हरिके बैराज से निकाली गई फिरोजपुर फीडर की टेल से पानी उपलब्ध करवाया जाने लगा, जो बीकानेर कैनाल की आरडी 45 पर डाला जाता है। बीकानेर कैनाल (गंगनहर) में विभाजन पूर्व पानी का हिस्सा 1.11 एम.ए.एफ. (मिलियन एकड़ फीट) था, जिसे वर्ष 1965 में बढ़ाकर 1.44 एम.ए.एफ. कर दिया गया। इसमें पानी का अतिरिक्त 0.33 एम.ए.एफ. राजस्थान के लिए रावी-व्यास के निर्धारित शेयर में से दिया गया। गंगनहर के निर्माण के लिए महाराजा गंगासिंह को इस इलाके के लोग आज भी सम्मान के साथ याद करते हैं। श्रीगंगानगर शहर में सिविल लाइन्स में कलक्ट्रेट के पास चौक पर उनकी प्रतिमा स्थापित है। उनकी एक प्रतिमा जनसहयोग से शिवपुर हैड पर भी स्थापित की गई, जिसका 13 अक्टूबर 2022 को लोकार्पण किया गया। इस प्रतिमा की स्थापना में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन, जल संसाधन विभाग व किसानों का विशेष सहयोग रहा।

बजट 2024-25

प्रदेश में "राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन" प्रारम्भ किया जाएगा। इस मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जिलों में सिंचाई व्यवस्था के साथ ही जल संचय की प्रणाली विकसित करने के लिए इस कार्यकाल में 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्य करवायें जायेंगे।

'राजस्थान सरकार के प्रयासों से हुआ आधुनिकीकरण'

अंग्रेजों के जमाने में बनी इस नहर की लाइनिंग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होने के कारण इसमें सीपेज लॉसेज (जल छीजत नुकसान) निर्धारित 80 क्यूसेक से बढ़कर 400 क्यूसेक जा पहुंचा। इस कारण किसानों को उपलब्ध करवाए जाने वाले पानी में कमी होने लगी। चूने व कंकड़ से बनी नहर हुसैनीवाला हैड (फिरोजपुर) से शिवपुर हैड (श्रीगंगानगर) तक ही थी। आगे मुख्य नहर तथा शेष पूरी प्रणाली की नहरें वितरिकाएं कच्ची थीं। इस पर 1982 में राजस्थान सरकार ने नहर पुनर्निर्माण व आधुनिकीकरण की योजना को स्वीकृति दी।

इसके अंतर्गत वर्ष 1983 में इंदिरा गांधी फीडर के लौहगढ़ हैड से गंग कैनाल लिंक चैनल का निर्माण कार्य शुरू किया गया। इसमें 14 जुलाई 1993 से जल प्रवाहित किया गया। गंग कैनाल लिंक चैनल को गंगनहर में साधुवाली के समीप जोड़ा गया ताकि इससे ऊपर पंजाब में फिरोजपुर फीडर तक नहर का पुनर्निर्माण करवाया जा सके। इसके पश्चात तत्कालीन मुख्यमंत्री के प्रयासों से 31 मई 2000 को केन्द्रीय जल आयोग ने इसके आधुनिकीकरण की 445.79 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृति दी। यह कार्य वर्ष 2001 में प्रारंभ हुआ। पुनर्निमित गंगनहर में 8 जुलाई 2005 को तत्कालीन मुख्यमंत्री व तत्कालीन उप मुख्यमंत्री ने फिरोजपुर में आरडी 45 से जल प्रवाहित किया।

गंगनहर के आधुनिकीकरण पर लगभग 600 करोड़ रुपए व्यय हुए। आरडब्ल्यूएसआरपी (राजस्थान वाटर स्ट्रक्चर रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट) के अंतर्गत इसकी समस्त कच्ची नहरों की लाइनिंग की गई। गंगनहर फीडर के साथ-साथ ढाणियों, सड़कों व विद्युत लाइनों के कारण डायवर्जन के लिए जगह उपलब्ध न होने और पूर्ण जल बंदी न मिलने के बाद भी विभाग के अभियंताओं ने कठिन स्थानों पर 500-500 मीटर के टुकड़ों में लाइनिंग का कार्य करवाया।

'पंजाब से दूषित जल आने की समस्या'

गंगानगर जिला (बाद में इससे हनुमानगढ़ जिला अलग हुआ) मुख्यतः चार सिंचाई परियोजनाओं के अधीन हैं। ये हैं- घग्घर (मानसून काल में वर्षा आधारित नदी), गंगनहर, भाखड़ा नहर तथा विश्व की सबसे लम्बी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना। पंजाब में नदियों में डाले जा रहे दूषित व फैक्ट्रियों के अपशिष्ट से तीनों नहर परियोजनाओं में आ रहे दूषित जल के दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं।

गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले सहित पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई के साथ पेयजल उपलब्ध करवाने का बड़ा माध्यम भी यही नहर परियोजनाएं हैं। इस स्थिति को लेकर किसानों की चिंता को देखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री ने पंजाब को पत्र लिखकर पंजाब में इन नहरों के उद्गम स्थल पर नदियों को स्वच्छ रखने का आग्रह किया। ताकि दूषित जल इन नहर परियोजनाओं में न आ पाये। लगातार इस संबंध में राजस्थान की ओर से पंजाब सरकार से पत्राचार किया जा रहा है।

'डिग्गियों के बाद जल का अधिकतम सदुपयोग'

जल संसाधन विभाग के एसई (गंगनहर) श्री धीरज चावला के अनुसार गंगनहर प्रणाली में वार्षिक सिंचाई व जल उपयोगिता औसत लगभग 79 प्रतिशत रहा है। 1936-46 (विभाजन पूर्व) की अवधि में 1.11 एम.ए.एफ. का 85.2 प्रतिशत, 1948-1960 (सिंधु जल समझौता से पूर्व) के समय में 1.46 एम.ए.एफ. का 83 प्रतिशत और 1960-1970 (सिंधु जल समझौता अवधि) के दशक में 89.19 प्रतिशत एवं 1970 के पश्चात (सिंधु जल समझौता अवधि पश्चात) 1.60 एम.ए.एफ. का अधिकतम सदुपयोग किया जा रहा है।

गंगनहर के पुनर्निर्माण के पश्चात किसानों द्वारा अपने खेतों में जल संग्रहण के लिए राज्य सरकार की ओर से दिये जाने वाले अनुदान पर बनाई गई डिग्गियों के बाद से जल उपयोगिता निरंतर बढ़ रही है।

आरडब्ल्यूएसआरपी के अंतर्गत गंगनहर की सभी वितरिकाओं में सदस्य किसानों द्वारा चुनाव से जल उपयोक्ता समितियों का गठन किया जाता है और इन समितियों में शामिल किसान ही पानी की बारी की पर्ची जारी करने और आबियाना (सिंचाई शुल्क) का संग्रहण करते हैं।

'गंगनहर की बाराबंदी यूनिक'

श्री चावला के अनुसार राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं में गंगनहर के लिए इसके निर्माण के समय निर्धारित की गई बाराबंदी सबसे यूनिक है। यह गोलबारी के नाम से जानी जाती है और इसमें कहीं भी विवाद जैसी स्थिति देखने को नहीं मिलती। गंगनहर परियोजना जैसी बेहतरीन सिंचाई योजना का निर्माण उस समय में हुआ, जब इस तरह की सिंचाई योजना की कल्पना करना भी बड़ी मुश्किल बात थी।

तत्कालीन जिला कलक्टर के मार्गदर्शन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के राज्य और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ-साथ जल संसाधन विभाग के समन्वय से डिजिटल बाराबंदी सिस्टम का लोकार्पण 29 अप्रैल 2024 को किया गया। वर्तमान में बाराबंदी को ऑनलाइन करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। बाराबंदी व्यवस्था पूर्णतया लागू होने के उपरांत आबियाना मांग एवं वसूली भी इसी पोर्टल के माध्यम से की जानी है। ●

Transforming Water Resource Management in
RAJASTHAN

Addressing Water Scarcity in Rajasthan

The VISION 2045 Framework

Rakshita Yadav, APRO

Rajasthan spans 10.4% of India's total land area, faces a critical challenge in water management due to its limited freshwater resources. The state holds only 1.16% of the country's surface water and 1.70% of its groundwater. Rajasthan is water scarce state having per capita availability of water below 1000 m3/year which is less than national average. There are 14 defined river basins in the State but Chambal and Mahi are the only perennial rivers. The average rainfall for the State is just about 570 mm, making effective water management not just essential, but imperative for sustainable development.

The state currently faces challenges like inadequate availability of water, inadequate utilization of surface water, deteriorating condition of water supply project due to insufficient maintenance, financial constrains, reluctance to adopt modern water technologies, water degradation, lack of human resource development, inter sectoral co-ordination. To effectively address these challenges, radical changes in approach, planning and technology after a critical review of earlier and existing policies is needed. In response to these issues, the Rajasthan government's Vision 2045 seeks to revitalize and effectively implement the State Water Policy of 1999.

The State of Rajasthan has adopted the State Water Policy in 1999 to address the problems surrounding the water sector by educating, encouraging scientific method of irrigation, expansion of Intensive Extension Program to increase the water Utilization efficiency in agricultural, domestic and industrial sectors from less than 30% to over 70-90%.

Since planning and policy formulation is a dynamic process therefore for any policy to succeed, it is essential to conduct regular reviews and timely refinements of its activities. In light of this, the state government has introduced the Vision 2045 initiative to guide future progress and ensure effective implementation of State water policy.

This ambitious plan aims to address the pressing issues of water scarcity and resource management, ensuring that the state's growing population and agricultural needs along with the water requirement of other sectors including industries, power generation are met while promoting sustainable practices. To effectively tackle the challenges in water resource management, Rajasthan recognizes the need for a fundamental shift in approach, planning, and technology, following a thorough evaluation of past and current policies. Through Vision 2045, the state government aims to implement regular monitoring of ongoing projects to ensure timely completion. Additionally, it will evaluate the performance of existing projects in terms of efficiency and environmental sustainability to facilitate timely updates to the policy, priorities, and action plans to meet the objectives of the State Water Policy effectively. It aims to ensure that all data under the state water policy is consistently updated on an annual or seasonal basis.

Rajasthan's Vision 2045 represents a comprehensive and forward-thinking strategy to tackle the state's pressing water management challenges. By emphasizing regular monitoring, evaluation, and adaptation of existing policies, the initiative aims to enhance water utilization efficiency across all sectors, from agriculture to industry. Through the promotion of modern technologies and practices, as well as the establishment of effective water user associations, the govt seeks to ensure sustainable water resource management for the growing population and economic needs of the state. The commitment to continuous improvement and rigorous assessment will facilitate the optimal use of limited water resources, ultimately contributing to the long-term sustainability and development. As Rajasthan looks to the future, strategic water management will be vital in safeguarding this precious resource for generations to come. ●

दक्षिण राजस्थान का वरदान

माही बजाज सागर

जयेश पण्डया, सहायक जनसम्पर्क अधिकारी

माही नदी, जो कि पश्चिमी भारत की एक प्रमुख नदी है, बांसवाड़ा जिले से होकर बहती है। इस नदी पर बनाए गए माही बजाज सागर बांध का निर्माण 1972 में शुरू हुआ और 1983 में पूरा हुआ। इस बांध का उद्देश्य जल संरक्षण, सिंचाई, बिजली उत्पादन, मत्स्य पालन इत्यादि है। इसके निर्माण से क्षेत्र में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है और स्थानीय निवासियों हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। माही बांध के जलग्रहण क्षेत्र में द्वीपों की बड़ी संख्या है, इसलिए बांसवाड़ा "सौ द्वीपों का शहर" के नाम से लोकप्रिय है।

माही बजाज सागर सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन की एक बहुउद्देशीय परियोजना है। वर्तमान में माही परियोजना द्वारा बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले के 80 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और विद्युत गृहों से 140 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रही है। बांध की कुल भराव स्तर 281.50 आरएल मीटर पर क्षमता 77 हजार मिलियन घनफीट है। इस वर्ष हुई अच्छी बारिश की बदौलत बांध लबालब है तथा सितंबर माह में बांध के 12 गेट खोल अधिशेष जलराशि की निकासी भी की गई थी।

बांध का नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज के नाम पर रखा गया था। यह परियोजना माही नदी से जुड़ी हुई है। माही नदी मध्यप्रदेश के धार जिले में से निकलती है। माही नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है। इस परियोजना का निर्माण 1972 से शुरू हुआ था।

माही परियोजना एक नजर में

• बांध का कुल जल ग्रहण क्षेत्र	142.90 वर्ग किमी
• बांध की कुल भराव क्षमता	281.50 आरएल मीटर।
• बांध की अधिकतम भराव क्षमता	77 टीएमसी
• बांध की उपयोगी भराव क्षमता	64.75 टीएमसी
• विद्युत उत्पादन	140 मेगावाट
• निर्माण वर्ष	1983

राजस्थान के 80 हजार हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र में सिंचाई के अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रोजेक्ट के लिए 4 टीएमसी पीएचईडी के लिए 2.08 टीएमसी और बांसवाड़ा कस्बे के औद्योगिक विकास के लिए .065 टीएमसी पानी आरक्षित किया गया है।

माही बजाज सागर बांध के निर्माण के बाद, बांसवाड़ा जिले में जल संकट की समस्या में काफी कमी आई है। यह बांध मुख्य रूप से रबी और खरीफ फसलों के लिए सिंचाई का एक प्रमुख स्रोत है। यहां की मिट्टी, जो पहले सूखी और बंजर थी, अब उपजाऊ हो गई है। किसान अब धान, गेहूं बाजरा, चना और अन्य फसलों की खेती कर रहे हैं।

बांध द्वारा उपलब्ध कराए गए जल संसाधनों ने बांसवाड़ा के किसानों को कृषि में नई तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया है। आधुनिक सिंचाई प्रणालियों, जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई का उपयोग करने से उत्पादन में वृद्धि हुई है एवं किसानों की आय में भी वृद्धि हुई है।

जलाशय के तंत्र ने कुछ नए जलाशयों और आर्द्रभूमियों को भी विकसित करने में मदद की है, जो पक्षियों और अन्य जलीय जीवों के लिए आवास प्रदान करते हैं। यह क्षेत्र अब बर्ड वॉचिंग और ईको-टूरिज्म के लिए भी जाना जाने लगा है।

माही बजाज सागर ने बांसवाड़ा के स्थानीय आदिवासी बाहुल्य इलाके पर कई सकारात्मक प्रभाव डाले हैं। बहुमूल्य जल की प्रचुर उपलब्धता ने स्थानीय लोगों के जीवन स्तर को बेहतर किया है। पहले जहां लोग पानी के लिए संघर्ष करते थे, अब उन्हें पानी की पर्याप्त मात्रा मिल रही है जिससे पूरे क्षेत्र में खुशहाली है।

माही बजाज सागर परियोजना ने बांसवाड़ा जिले में सामाजिक और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा दिया है। जल संसाधनों की उपलब्धता ने नई व्यावसायिक संभावनाओं को जन्म दिया है। मत्स्य पालन, पर्यटन और कृषि आधारित उद्योगों ने स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं।

परियोजना का 'चाचा कोटा' सरीखा बैकवाटर क्षेत्र भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहां के शांत और सुंदर वातावरण में लोग पिकनिक मनाने आते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास पर भी ध्यान दिया है, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन की सुविधाएं बेहतर हुई हैं।

माही बजाज सागर, बांसवाड़ा जिले समेत समूचे दक्षिण राजस्थान के लिए एक वरदान साबित हुआ है। इसने न केवल जल संकट का समाधान किया है, बल्कि कृषि, पर्यावरण और स्थानीय समुदायों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही, यह जलाशय पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण पहलू सिद्ध हुआ है। ●

छाया - भरत कंसारा बांसवाड़ा

राज्य का गौरव बीसलपुर बांध

आकाश बैरवा, सहायक जनसम्पर्क अधिकारी

खूबसूरत हरियाली की चादर ओढ़े पहाड़ों की कोख में बना बीसलपुर बांध और बीच से बहती बनास नदी पूरे क्षेत्र और कई जिलों में जिलों के लिए खुशहाली लाती है। बनास नदी पर बना बीसलपुर बांध प्रदेश के अजमेर संभाग का सबसे बड़ा बांध है। साथ ही, प्रदेश की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना भी है। यह बांध राजधानी जयपुर से करीब 104 किमी. दूर टोंक जिले की देवली तहसील में आता है, जो देवली से 25 किमी. की दूरी पर बना एक गुरुत्व बांध है। यह बांध जयपुर, अजमेर, दौसा, नागौर, सवाई माधोपुर और टोंक जिले के एक करोड़ से अधिक लोगों की प्यास बुझाता है। इसलिए बनास नदी इस क्षेत्र की जीवनदायिनी कहलाती है।

पेयजल और सिंचाई के साथ प्राकृतिक पर्यटन स्थल भी

बीसलपुर बांध को दो चरणों में बनाया गया था। पहले चरण का उद्देश्य स्थानीय आमजन को पीने का पानी उपलब्ध करवाना था जबकि दूसरे चरण का उद्देश्य सिंचाई की सुविधाओं में सुधार लाना था। बीसलपुर राजस्थान के टोंक जिले में स्थित एक गांव है, और यह भगवान गोकर्णेश्वर के प्राचीन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि इसी क्षेत्र में रावण ने कई वर्षों तक भगवान शिव को खुश करने के लिए तपस्या की थी। इसी के साथ यहां बीसलदेव मंदिर भी स्थित है। इसे 12वीं शताब्दी के चाहमान शासक विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनवाया गया था जिन्हें बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में अब कई होटल, रिसॉर्ट तथा एडवेंचर पार्क जैसी गतिविधियां यहां मुख्य आकर्षण का केन्द्र बनती जा रही हैं। इस प्रकार बीसलपुर धार्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य के साथ आमजन के लिए मन-मोहक पर्यटन स्थल की भी पहचान बना रहा है।

बांध ने पूर्ण भराव क्षमता आरएल 315.50 मीटर का छुआ आंकड़ा

प्रदेश में इस वर्ष बनास नदी के आस-पास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश के चलते हाल ही में माह सितंबर, 2024 में बांध ने अपनी पूर्ण भराव क्षमता आरएल 315.50 मीटर का आंकड़ा छुआ था जिसके बाद कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश रावत और पूर्व मंत्री डॉ. प्रभुलाल सैनी द्वारा विधिवत पूजा अर्चना के बाद बांध के स्काडा सिस्टम के जरिए 2 गेट एक-एक मीटर खोलकर 12 हजार क्यूसेक पानी की निकासी की गई। जिससे प्रदेश के आमजन और किसानों के चेहरे खिल उठे।

स्काडा सिस्टम क्या है?

स्काडा का फुल फॉर्म है - सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। यह एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जो कैमरे और सेंसर की मदद से पानी के भंडारण और खोले गए गेटों की जानकारी देती है। स्काडा सिस्टम से बांध के गेटों को खोलने के लिए कंट्रोल रूम में कंप्यूटर सिस्टम पर छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा दर्ज कर एक बटन दबाना होता है, इस नवीन और उन्नत तकनीक से बांध के गेटों को खोलने के लिए कर्मचारियों को बांध पर आने की आवश्यकता नहीं होती। बीसलपुर बांध प्रदेश का पहला ऐसा बांध है जहां स्काडा सिस्टम लगाया गया है।

बीसलपुर बांध के रोचक तथ्य

- सन् 1999 में निर्मित बीसलपुर बांध कंक्रीट से बना हुआ प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है।
- नदी जोड़ो परियोजना के तहत इस बांध को चंबल नदी से जोड़ा जा रहा है।
- बीसलपुर बांध पर रंगीन मछलियों का प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है।
- बीसलपुर राज्य के कंजर्वेशन रिजर्व में शामिल है।
- यह बांध 574 मीटर लंबा और 39.5 मीटर ऊंचा है।
- बांध की पूर्ण भराव क्षमता 315.50 आरएल मीटर है।
- इस बांध से पानी टोंक और सवाई माधोपुर होते हुए चंबल नदी में मिलता है। इसके बाद यमुना और गंगा नदियों में मिलकर बंगाल की खाड़ी तक जाता है।

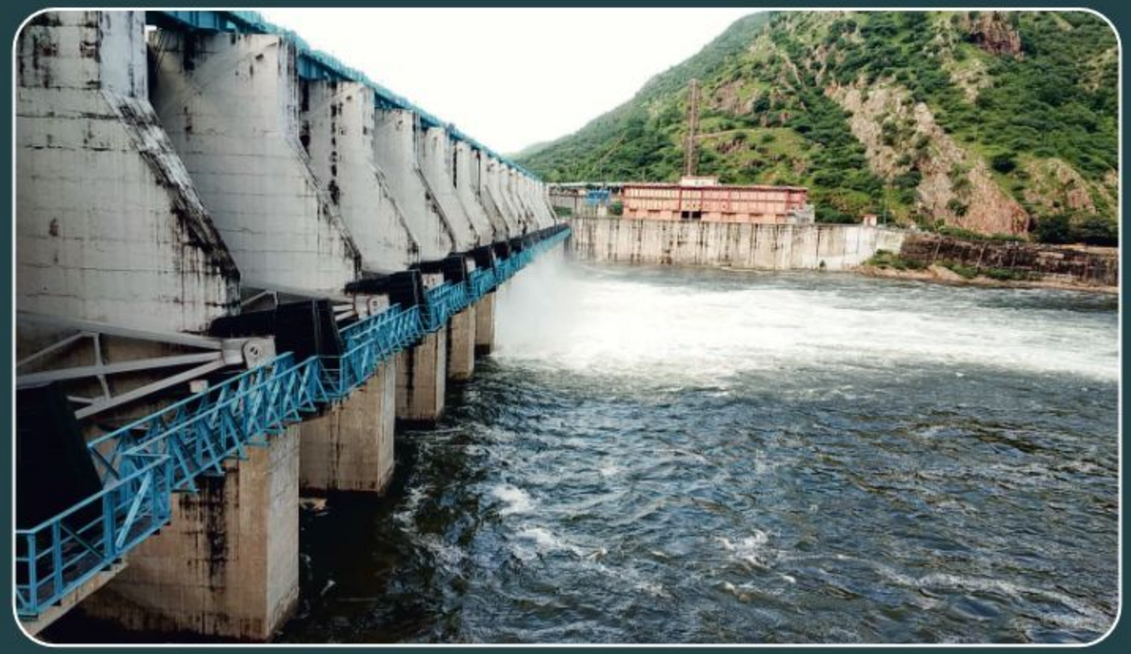

राजस्थान का मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध

पांचना

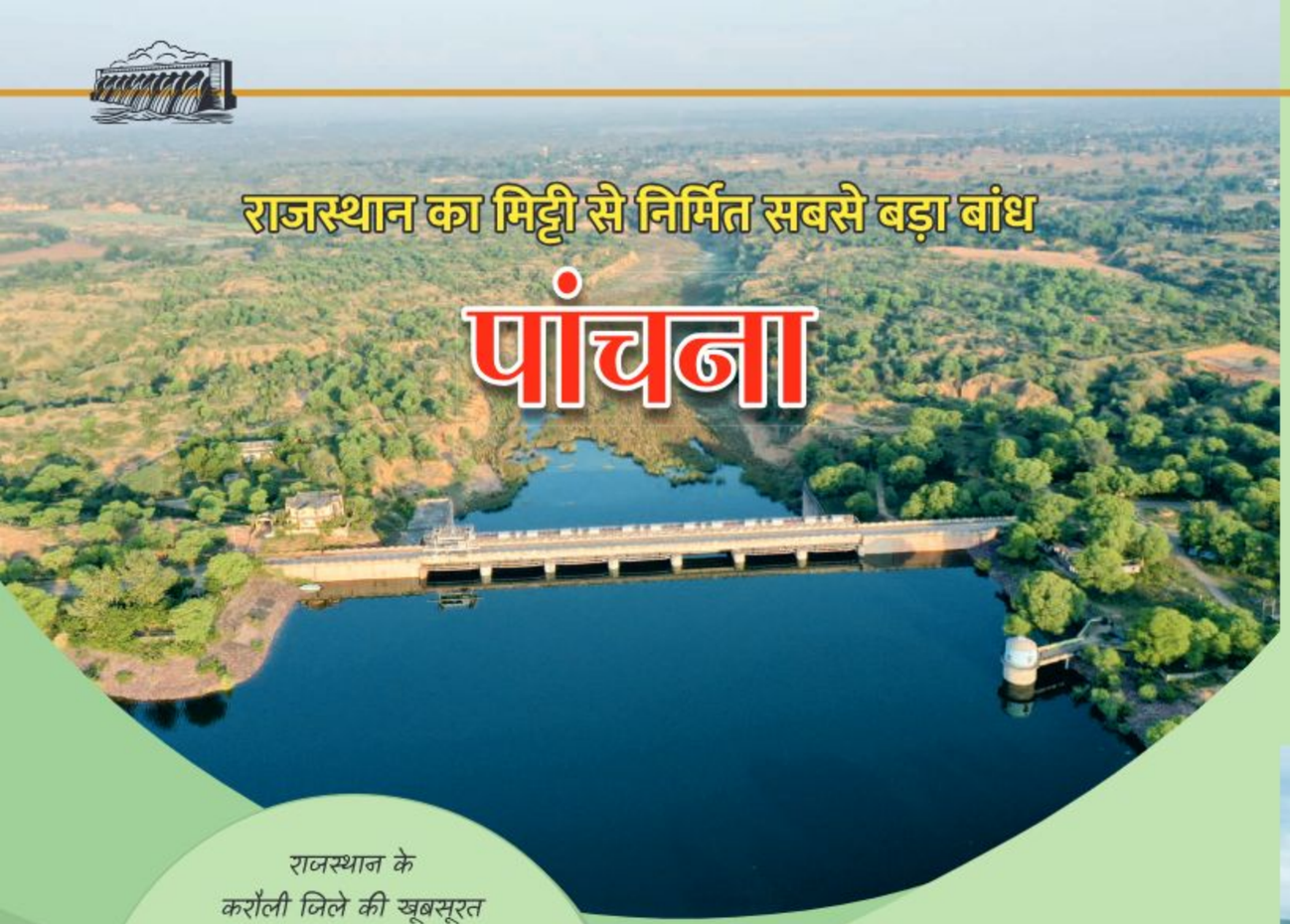

राजस्थान के करौली जिले की खूबसूरत वादियों में बसा पांचना बांध ऐतिहासिक महत्व और आधुनिक विकास का एक अद्भुत उदाहरण है। चारों ओर फैली हरी-भरी पहाड़ियां और मनोरम दृश्यों के बीच स्थित यह बांध न केवल इस इलाके की जीवनरेखा है, बल्कि पानी के बेहतर प्रबंधन के माध्यम से मानव कौशल का प्रतीक भी है।

रवि वर्मा, सहायक जनसम्पर्क अधिकारी

पांचना बांध 1977 में निर्मित, करौली जिले के सबसे महत्त्वपूर्ण मीठे पानी के स्रोतों में से एक है। यह सिंचाई और करौली शहर के पीने के पानी की आपूर्ति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह बांध काशीरामपुरा गुडला गांव के पास स्थित है, जो करौली शहर से लगभग 12 किमी उत्तर में है। पांचना बांध पांचना नदी पर बनाया गया है, जो यमुना बेसिन की गम्भीर नदी की एक सहायक नदी है। पांच छोटी नदियों- भैसावट, माची, अटकी, भद्रावती और बरखेड़ा के संगम के कारण इसे पांचना नाम दिया गया है। इसकी ऊंचाई लगभग 34.08 मीटर है और इसका ओजी आकार का क्रेस्ट है, जो ठोस रोलर बकेट प्रकार का है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है।

पांचना बांध का कुल कैचमेंट क्षेत्र 621.60 वर्ग किलोमीटर है और इसका सकल कमांड क्षेत्र 11,172 हैक्टेयर है। बांध के दरवाजे मजबूत लोहे की तारों से मोटर इंजनों द्वारा खोले और बंद किए जाते हैं। बांध की मुख्य नहर प्रणाली पांचना मेन (फीडर) नहर है, जो 11.57 किमी लंबी है और इसके अंत में दो शाखाओं में बंट जाती है - श्री महावीर जी (14.8 किमी) और पिलोदा (18.8 किमी)।

इस बांध के बनने से आस-पास के गांवों के कृषि परिदृश्य में बदलाव आया है। यह न केवल सिंचाई के लिए पानी का स्रोत बना, बल्कि इसने बाढ़ नियंत्रण और सूखे के दौरान भी पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की।

हाल के वर्षों में पांचना बांध में कई अहम सुधार किए गए हैं। जनसंख्या वृद्धि और बढ़ती कृषि आवश्यकताओं के कारण पानी की मांग भी बढ़ी है। इस चुनौती का सामना करने के लिए सरकार और स्थानीय प्रशासन ने इसकी भंडारण और वितरण क्षमता को बढ़ाने के कई प्रयास किए हैं। आधुनिक सिंचाई तकनीकों, जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम, का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि पानी की कम से कम छीजत हो और संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके।

जैव विविधता और ईको-टूरिज्म की संभावनाएं

पांचना बांध न सिर्फ कृषि के लिए, बल्कि यहां की वन्यजीव आबादी के लिए भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। पास ही स्थित कैलादेवी वन्यजीव अभयारण्य, जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है, से जानवर अक्सर यहां पानी की तलाश में आते हैं। इसके कारण इस क्षेत्र की पारिस्थितिक महत्ता बढ़ गई है। सर्दियों के मौसम में यहां प्रवासी पक्षियों का भी आगमन होता है, जिससे यह जगह पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग बन जाती है।

यहां की जैव विविधता को देखते हुए पांचना बांध में ईको-टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कोशिश कर रही है ताकि प्रकृति प्रेमी, वन्यजीव फोटोग्राफर और शांति की तलाश में आने वाले सैलानी यहां आ सकें और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को इसका लाभ मिल सकें। पांचना बांध सिर्फ एक जलाशय नहीं है। यह करौली जिले की प्रगति का प्रतीक है। कृषि में इसके योगदान से लेकर ईको-टूरिज्म और नवीकरणीय ऊर्जा तक, यह डैम एक सतत और समृद्ध भविष्य की ओर उम्मीद की किरण है। पांचना बांध लोगों के जीवन और पर्यावरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। ●

छाया : अनिल शर्मा

बरसात के साथ बरसी खुशियों की सौगात

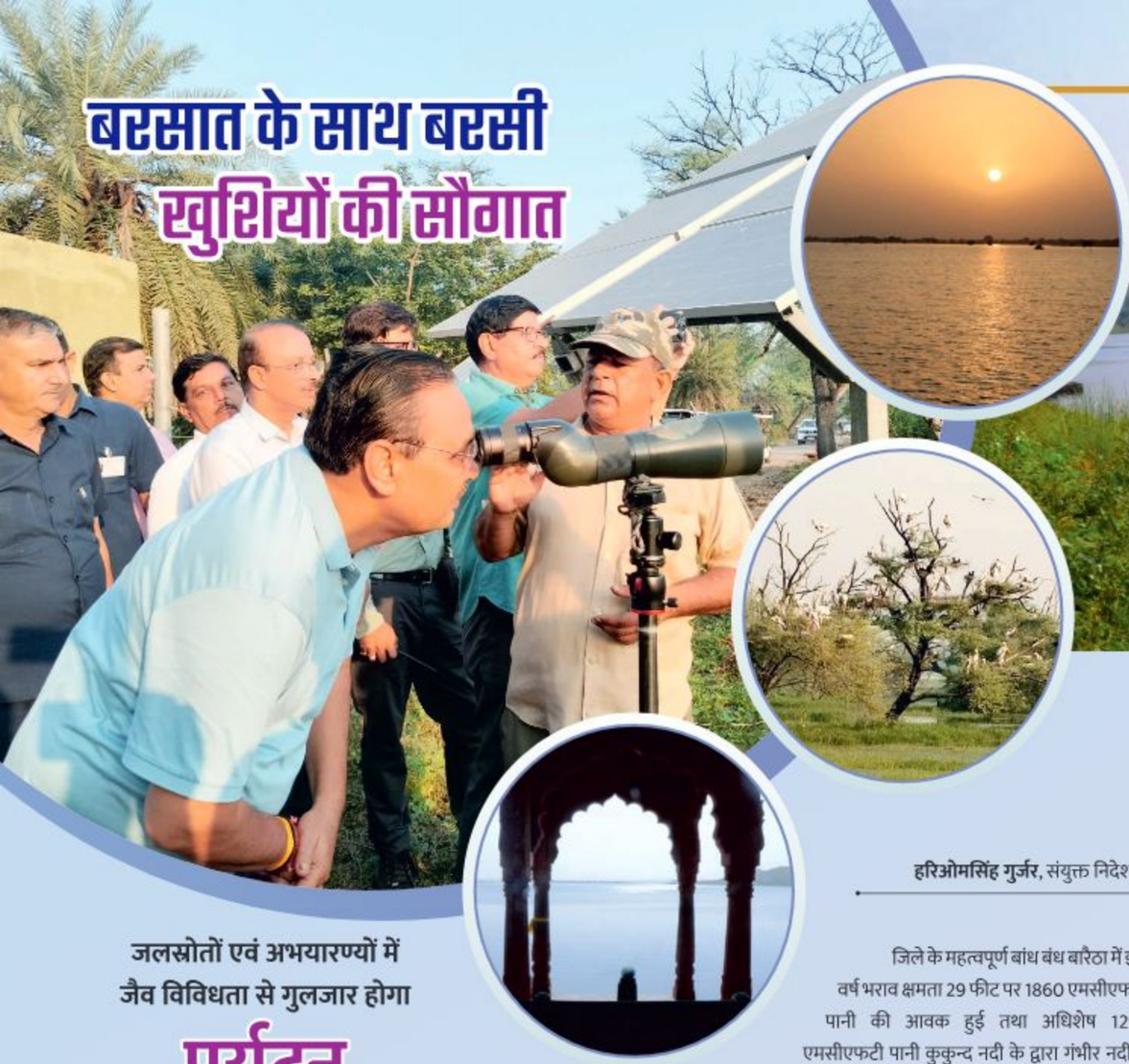

जलस्रोतों एवं अभयारण्यों में जैव विविधता से गुलजार होगा पर्यटन

हरिओमसिंह गुर्जर, संयुक्त निदेशक

राजस्थान के पूर्वी सिंहद्वार कहे जाने वाले भरतपुर जिले में इस वर्ष अच्छी बरसात से सभी जलस्रोतों में पानी की आवक से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। जिले से होकर गुजर रही गंभीर नदी में पांचना बांध से पानी छोड़े जाने से केवलादेव राष्ट्रीय घना पक्षी अभयारण्य की सभी झीलों, बंध बारैठा एवं अजान बांध में वर्षों बाद आया पानी खुशियों की सौगात लेकर आया है। इससे किसानों को रबी सीजन में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होने के साथ भूमिगत जल में भी वृद्धि हुई है। केवलादेव पक्षी अभयारण्य की झीलों एवं सभी जलस्रोतों में पानी की आवक जैव विविधता के लिए वरदान साबित हुई है। प्रतिवर्ष सर्दी के मौसम में आने वाले देशी-विदेशी परिंदों के लिए ये छिछली झील भोजन उपलब्ध कराने वाली मछलियों, विशेष वनस्पति की वृद्धि के लिए अनुकूल मानी जाती है। इससे वर्षभर पक्षियों को भोजन की उपलब्धता के साथ अनुकूल वातावरण मिलता है।

जिले के महत्वपूर्ण बांध बंध बारैठा में इस वर्ष भराव क्षमता 29 फीट पर 1860 एमसीएफटी पानी की आवक हुई तथा अधिशेष 1292 एमसीएफटी पानी कुकुन्द नदी के द्वारा गंभीर नदी में प्रवाहित किया गया है। बंध बारेठा बांध पर वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां शुरू करने तथा ईको ट्यूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। यहां प्राकृतिक रूप से सुरम्य वातावरण के साथ वर्षभर पानी की उपलब्धता आने वाले समय में पर्यटन गतिविधियों के लिए अनुकूल मानी जा रही है। रियासतकालीन यह बांध तीन तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जैव विविधता यहां वर्षभर देखी जा सकती है। जहां देशी-विदेशी पर्यटकों का आगमन बना रहता है। यहां पर राज्य सरकार द्वारा पर्यटकों के लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के साथ ईको ट्यूरिज्म के लिए बजट-2024 में प्रावधान किया गया है जो बंध बारैठा के सुनहरे भविष्य की ओर इंगित करता है। इससे स्थानीय रहवासियों को भी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने के साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बंध बारेठा की पहचान बनेगी।

चिकसाना बांध में अनेक वर्षों बाद पानी की भरपूर आवक हुई है जिसके चलते अधिशेष पानी को घना राष्ट्रीय अभयारण्य तक पहुंचाकर सभी झीलों को पूरा भरा गया है। इसके चलते केवलादेव पक्षी अभयारण्य पक्षियों के कलरव से गुंजायमान है। चिकसाना बांध से अधिशेष पानी की गत 2 माह से लगातार निकासी की जा रही है। इसके साथ ही भरतपुर में जल संसाधन विभाग द्वारा संधारित 21 बांधों में पानी की भरपूर आवक हुई है। जिले में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संधारित 132 में से पंचायत समिति रूपवास, बयाना, सेवर, वैर, कुम्हेर के 85 से अधिक बांधों मे पानी की आवक होने से लबालब भरे हुए है।

अधिशेष जल का होगा उपयोग

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बजट घोषणा 2024 में डूंगरी बांध से बंध बारैठा होते हुए सुजान गंगा भरतपुर तक लिंक का कार्य कराये जाने की घोषणा की थी। इसके लिए 2371 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार की गई है। डीग-कुम्हेर-भरतपुर में सांवई-खेड़ा डिप्रेशन से गोवर्धन ड्रेन तक 6 करोड़ 25 लाख रूपए की लागत से पानी लिफ्ट करने का कार्य करवाया जायेगा। इससे बरसात के अधिशेष पानी का सदुपयोग होने के साथ खेतों में जलभराव की समस्या से निजात भी मिलेगी। •

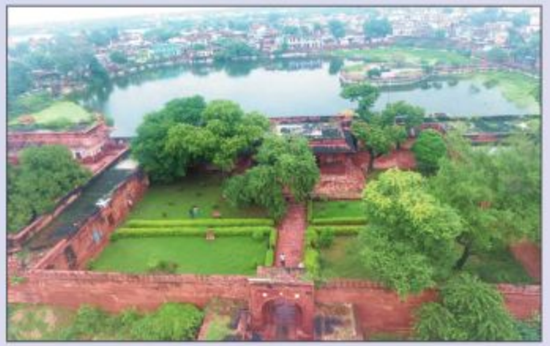

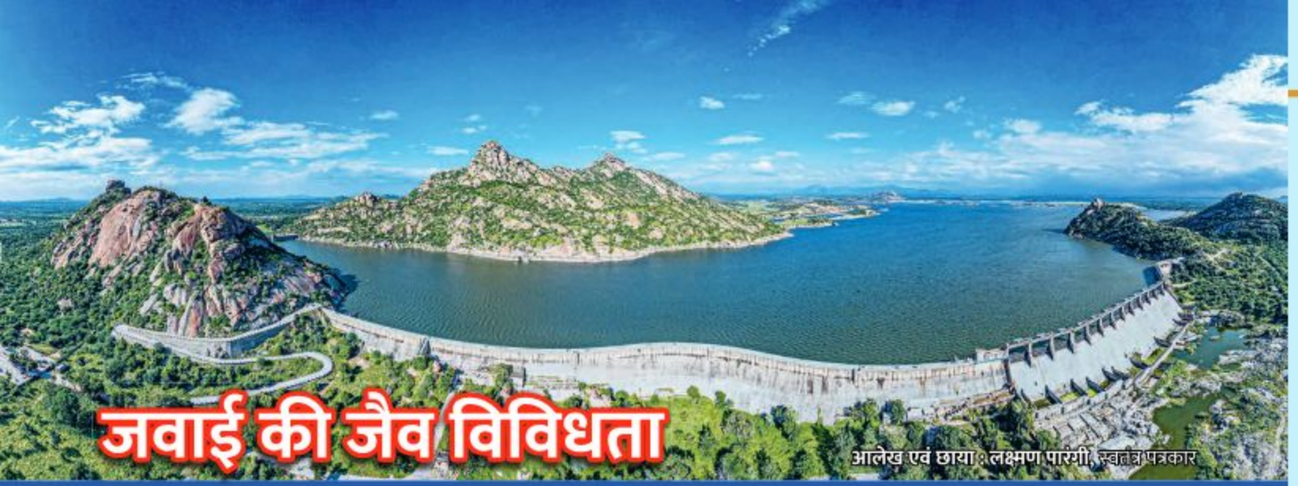

जवाई की जैव विविधता

आलेख एवं छाया : लक्ष्मण पारमी, स्वतंत्र पत्रकार

मानवीय जीवन के साथ वन्यजीवों के लिये भी वरदान

मानव-वन्यजीव साहचर्य का अनुपम उदाहरण

जवाई बांध का शिलान्यास रियासत के तत्कालीन महाराजा उम्मेदसिंह द्वारा 13 मई 1946 को किया गया। परियोजना की कुल लागत 2.60 करोड़ रुपए थी। बांध निर्माण कार्य 1957 में पूर्ण हुआ। निर्माण के बाद 1973 में प्रथम बार गेट खोल कर पानी की निकासी की गई एवं बांध का गेज 60.00 फीट (7000मि.घ.फीट) से बढ़ाकर 61.25 फीट (7327.50 मि.घ.फीट) किया गया। बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिये वर्ष 1969 से 1978 के मध्य सेई अपर्वतन योजना का कार्य करवाया गया। सेई बांध से 6776 मीटर लम्बी सुरंग के माध्यम से जवाई बांध में पानी का अपर्वतन प्रारम्भ किया गया। वर्ष 2006 के दौरान सेई बांध की ऊंचाई 8.25 मीटर से बढ़ाकर 10.93 मीटर की गई जिसमें जवाई बांध को 516 मि.घ.फीट अतिरिक्त पानी उपलब्ध हो सका। निर्माण के 63 वर्षो में अब तक अब तक जवाई बांध मात्र 9 बार ही पूर्ण भरा एवं वर्ष 1973 से 2017 के बीच आठ बार जवाई बांध के गेट खोलकर पानी को जवाई नदी में छोड़ा गया। जवाई बांध कैचमेन्ट एरिया 307 वर्ग किमी. है।

पेयजल-सिंचाई का प्रमुख स्रोत

जवाई बांध से वर्तमान में सिरोही जिले के शिवगंज कस्बे एवं पाली जिले के शहरों समेत 9 कस्बों सुमेरपुर, देसूरी, रानी, जैतारण, मारवाड जक्शन, रायपुर, रोहट, सोजत व बाली तथा 985 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। जवाई बांध से 57 गांवों के कुल सी.सी.ए 38671.00 हैक्टर (पाली जिले के 33 गांव की सिंचित क्षेत्र 25825.40 हैक्टर एवं जालौर जिले के 24 गांवों की 12845.60 हैक्टर भूमि पर सिंचाई से दोनों जिलों के 38600 किसान परिवार लाभान्वित होते हैं।

नहरों की स्थिति

जवाई कमाण्ड क्षेत्र में वर्तमान में मुख्य नहर 23.10 किमी. लम्बी है। साथ ही इन नहर की 5 वितरिकाएं 133.30 किमी. एवं 16 माइनर नहरों की लम्बाई 97.40 किमी. है। कुल 233.80 किमी. लम्बाई की इन पक्की नहरों द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

15 जल उपभोक्ता संगम

जवाई कमाण्ड क्षेत्र में सरकार व किसानों के बीच तालमेल व सिंचाई में सरकार की ओर से पारदर्शिता के लिये किसानों के लिये 15 जल उपभोक्ता संगम है। इनके सहयोग से जल वितरण समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव व निर्णयों के अनुसार टेल से हेड तक खसरों के क्षेत्रफल अनुसार काश्तकारों को समय आवंटित कर बारांबदी व्यवस्था से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जवाई बांध में पानी लाने वाली सेई बांध की सुरंग को 1.5 मीटर गहरा करने हेतु कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में जवाई 60 फीट भर चुका है।

तेंदुआ संरक्षण हेतु "जवाई लेपर्ड कन्जरवेशन रिजर्व"

जवाई बांध में मगरमच्छ पहले से ही बहुतायत में है। इनके सरंक्षण हेतु जवाई बांध को पहले से ही वन विभाग ने "क्रोकोडायल सेंचुरी" की भांति सरंक्षित किया हुआ है। बाद में यहां के तेंदुओं के साथ मानवीय सहजीवन को देखते हुये जवाई बांध के नाम से 'जवाई लेपर्ड कन्जरवेंशन रिजर्व' फेज-प्रथम 27 फरवरी 2013 में व फेज-द्वितीय 15 जून 2018 घोषित किया गया। फेज प्रथम में सेणा, जीवदा, बिसलपुर व बलवना व दूदनी को शामिल किया गया। द्वितीय फेज में चामुण्डेरी, वेलार, लुन्दाडा व मालदर गांवों को सम्मिलित किया गया, ये पाली जिले की बाली तहसील के गांव हैं। इनमें बाली तहसील के पेरवा गांव की सार्वजनिक महादेव पहाड़ी पर सहज ही तेंदुआ देखा जा सकता है। जिसे सबसे पहले वर्ष 2011 में राज्य सरकार ने पहाड़ी के आस-पास की करीब 70 बीघा भूमि समेत इसे ईको-टूरिज्म साइट घोषित किया है। जवाई लेपर्ड कन्जरवेंशन रिजर्व क्षेत्र में करीब 45 तेंदुए हैं।

जवाई में पर्यटन

जवाई क्षेत्र में पर्यटन पूरे साल अनवरत जारी रहता है। जवाई बांध क्षेत्र में सफारी करने तथा पर्यटन के लिये यहां पूरे भारत भर से व विदेश से मेहमानों का तांता लगा रहता है। यहां के तेदुओं को देखने व सफारी करने जवाई के आस-पास सभी गांवों में करीब 250 से अधिक निजी सफारी जिप्सियों के जरिये पर्यटन होता है। जवाई क्षेत्र में होटलों का जाल सा बिछ रहा है। यहां निजी होटलों के दिनों-दिन प्रसार से पर्यटन उद्योग में भारी इजाफा हो रहा है।

जैव विविधता

जवाई बांध को जवाई लेपर्ड कन्जरवेंशन रिजर्व घोंषित किया गया है जिसमें मगरमच्छों के अलावा तेंदुआ, भालू, सियार, लकड़बग्घा, सिवेट, बंदर, जंगल केट, रस्टीस्पोटेड केट, सेई, झाउ चूहे, ग्रे मंगुस, स्मॉल मंगूस, जंगली भूरे चूहे, कई प्रकार के सरिसृप भी यहां अपनी आवास स्थली बनाये हुये हैं।

जवाई बांध में अनुकूल प्रवास के समय यहां पक्षियों की करीब 83 प्रजातियां प्रवास करती हैं। इनमें मछली बाज "औस्प्र", फ्लेमिंगो, लेसर फलेमिंगो, सारस क्रेन, डौमेन्सियल क्रेन, पेलिकन्स, समुद्रि परिंदे पलास गुल, लार्ज व स्मॉल कॉरमोरेन्ट, बतखों में गरगनी, स्पॉटबिल डक, रूडीसेल डक, विसलिंग डक, बार हेडेड गुज, ग्रेलेग गुज, रिंग प्लोवर, केन्टिस प्लोवर, स्मॉल प्रेटिनकोल, स्टॉर्कस, ईग्रेट्स समेत 87 प्रजातियां प्रवास करती हैं। ये परिंदे सर्दियों की दस्तक के साथ मौसम में बदलाव आने तक यहां टिके रहते हैं।

वन्यजीवों पर निगरानी

जवाई लेपर्ड कन्जरवेंशन रिजर्व में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वन्यजीवों पर निगरानी के लिये 8 टॉवर कैमरे स्वीकृत किये गये। इसमें से 4 कैमरे जवाई बांध, वन विभाग, लिलोडा पहाड़ी कोठार, मोती महाराज की धूणी, मादकी पहाड़ वेलार व जगत बावड़ी क्षेत्र में लगाये गये हैं। जवाई बांध स्थित वन विभाग कार्यालय में सभी चार निगरानी टॉवरों पर लगाये गये थर्मल, आष्टिकल व इन्फ्रारेड कैमरों समेत 26 कैमरों की सहायता से बड़ी टीवी स्क्रीन पर वन विभाग व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निगरानी की जाती है। शेष 4 टॉवर कैमरों के लिये सैणा, पेरवा, हीरोला व लुन्दाड़ा के लिये इन गांवों में फाइबर केबल बिछा दी गई है। •

रेत के धोरों में 'पेंगोंग झील'

साइबेरिया और चीन से 250 से अधिक प्रजातियों के पक्षी पहुंचते हैं हनुमानगढ़ की बड़ोपल झील

राजपाल लंबोरिया
सहायक जनसंपर्क अधिकारी

राजस्थानी के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री शिव मृदुल की निम्न अग्रलिखित पंक्तियां राजस्थान की उत्तरी दिशा में भटनेर के नाम से प्रसिद्ध "हनुमानगढ़" जिले के सेमग्रस्त और घग्घर बहाव क्षेत्र में बनी प्राकृतिक झील "बड़ोपल" पर सटीक बैठती हैं। हनुमानगढ़-श्रीगंगानगर जिले की एकमात्र मानसूनी नदी घग्घर में अधिक पानी आने पर इसके बहाव क्षेत्र में पानी के बिखराव के कारण छोटे-छोटे मनमोहक टापू बन जाते हैं। सेमग्रस्त क्षेत्र होने के कारण सेम का पानी भी इकट्ठा रहता है। मानसून में घग्घर में पानी की आवक होने के बाद बड़ोपल सहित आस-पास के गांवों में जलभराव के क्षेत्र एक झील का रूप ले लेते हैं, जो लद्दाख की "पेंगोंग झील" की तरह नजर आती है। चारों तरफ रेत के टीलों के बीच में पानी से भरी यह झील प्रकृति प्रेमियों को अपनी और आकर्षित करती है।

पानी की बहुतायत होने के बाद, अक्टूबर के बाद यहां प्रवासी पक्षियों का आगमन भी शुरू हो जाता है, जिन्हें देखने के लिए हजारों टूरिस्ट प्रति वर्ष पहुंचते हैं। यहां साइबेरिया, चीन और आस्ट्रेलिया से पक्षियों के झुंड आते हैं। यहां गांव में खुदाई के दौरान प्रारंभिक गुप्तकाल की टेराकोटा की प्राचीन थेरिस (टीले) में कलाकृतियों मिली है। बड़ोपल क्षेत्र को बर्ड लाइफ इंटरनेशनल कार्यक्रम के माध्यम से पहचानी गई पक्षी प्रजातियों के संरक्षण के लिए आईबीए (महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र) साइट के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है।

"आभै सूं जद इमरत झुळकै, मुळकै हियो फूंवारां में
मरुधर थारो रूप रसीलो, सावण तीज तुंवारां में।
हरियाळी सिंगार करें है, थारी ओरां-छोरां में
कोयल, बुलबुल, मोर बिखेरै, हेत रेत रा धोरां में।"

साइबेरिया और चीन से आते हैं पक्षी

यहां प्रति वर्ष अक्टूबर से मार्च के दौरान यूरेशिया से 250 से अधिक प्रवासी पक्षियों की और 200 से अधिक देशी पक्षियों की प्रजातियां आती हैं। फ्लेमिंगो सबसे प्रसिद्ध प्रवासी पक्षी है जो सर्दियों के मौसम में आता है। इनमें वाटर फ्लेमिंगो, कोमन सेल्डक, स्पूनबिल, फेलिकंस, डार्टर, डोमोईसले क्रेन, ग्रेल, पिंनटेल, गीज सहित 250 से अधिक प्रजातियों के पक्षी शामिल हैं। फ्लेमिंगो झील में मछलियों, छोटे जलीय जीवों, और शैवालों का सेवन करते हैं, जो उनके चमकीले गुलाबी रंग का कारण बनता है। बड़ोपल क्षेत्र और इसके आस-पास विभिन्न प्रकार की वनस्पति मौजूद हैं, जो एक विशिष्ट क्षेत्रीय पैटर्न के साथ स्थलाकृति बनाती हैं। बड़ोपल पर स्थानीय वन विभाग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट अनुसार क्षेत्र में पक्षियों की अनेकों प्रजातियों की पहचान की गई और जलीय और स्थलीय पक्षियों की कुल संख्या हजारों में है। कई लुप्तप्रायः प्रजातियों (आईयूसीएन की रेड डेटा बुक सूची के अनुसार) को भी इस क्षेत्र में देखा जाता है। इस क्षेत्र में ब्लू बुल, ब्लैक बक, जंगली सूअर, रेगिस्तानी बिल्ली, रेगिस्तानी लोमड़ी, छिपकली, ब्लैक कोबरा, हेज हॉग भी देखने को मिलते हैं।

आकर्षण का केंद्र सफेद टापू

बड़ोपल के नजदीक ही झील में एक सफेद रंग का टापू स्थित है, जो यहां मुख्य आकर्षण का केंद्र है। सेमग्रस्त क्षेत्र होने के कारण टापू पर स्थित सभी वृक्ष सूख गए हैं, जिनके ऊपर व्हाइट फ्लेमिंगो के बैठने से, तथा घास के सफेद रंग के होने से दूर से यह टापू बर्फ की चादर ओढ़े नजर आता है।

दूर से ही यह प्रकृति प्रेमियों का दिल जीत लेता है। पर्यटन क्षेत्र में कार्यरत श्री लोकेंद्र सिंह भाटी बताते है कि बड़ोपल में पक्षियों का विचरण, पर्यटकों और प्राकृतिक जीवन के शौकीनों के लिए एक आकर्षक विकल्प हो सकता है। पक्षियों की इस समृद्धता से यहां के निवासी और पर्यटक दोनों को मनमोहक अनुभव होता है। जो यहां विभिन्न पक्षी प्रजातियों का अध्ययन और अवलोकन करने आते हैं। इसके अलावा, बड़ोपल झील का पर्यावरण संरक्षण और उसकी जैव विविधता को बनाए रखने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में पहली बार झील में बोटिंग के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं।

ग्रीन पिजन

बार हेडेडगूस

रोजी पेलिकन

पेंटेड स्टोर्क

मोर

बांध के बंधन से बंधी परवाजें

राजस्थान के बांध एवं अन्य वाटर बॉडीज अपने वन क्षेत्र में वनस्पतियों, फूलों एवं विभिन्न प्रकार के पशु-पक्षियों की विविध प्रजातियों को आश्रय और फलने-फूलने, संवर्धन करने का वातावरण प्रदान करते हैं। इन बांधों में प्रमुख रूप से जवाई सागर, माही बजाज, राणा प्रताप सागर, बीसलपुर, कानोता, मेजा, मोरेल, गांधी सागर बांध शामिल हैं। पक्षियों की न केवल भारतीय प्रजातियां यहां फलती-फूलती हैं, बल्कि सुदूर देशों से भी पक्षी बहुतायत में यहां प्रवास करने आते हैं जिनमें पेंटेड स्टोर्क, रोजी पेलिकन, हिमालय पार से सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले बार हेडेड गूस आकर्षण का केंद्र हैं। देसी प्रजातियों में कठफोड़वा, हरियल कबूतर, ब्राह्मिनी मैना, किंगफिशर, इंडियन व्हाइट आई जैसी प्रजातियां प्रकृति के रंगों की विस्तृत श्रेणियों का प्रदर्शन करती हैं।

आलेख एवं छाया
राज कुमार शिवानी, अतिरिक्त निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

व्हाइट थ्रॉटेड किंगफिशर

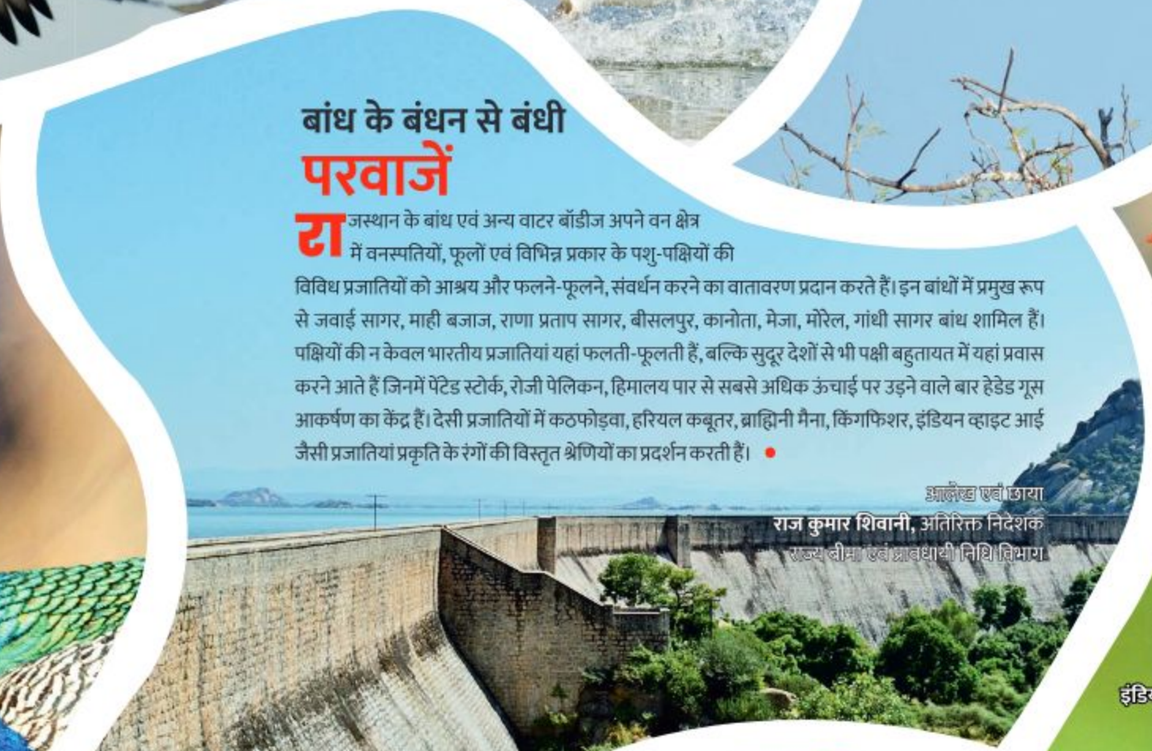

इंडियन व्हाइट आई

ब्राह्मिनी मैना

लैसर व्हिस्टलिंग डक

ग्रेट कोर्मोरेंट

फ्लेमेबैक वुडपेकर

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धासुमन

मुख्यमंत्री ने खादी प्रदर्शनी से वस्त्र खरीदकर भुगतान यूपीआई से किया।

गांधी सर्किल पर **पुष्पाजंलि** अर्पित करते मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा

RISING RAJASTHAN

REPLETE • RESPONSIBLE • READY

राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आयोजित होने वाले 'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार बड़े पैमाने पर देशी और विदेशी निवेशकों, संस्थाओं और कॉरपोरेट जगत के शीर्ष अधिकारियों से लगातार बैठकें एवं संवाद कर रही हैं ताकि आने वाले समय में प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश हो सके और 'विकसित राजस्थान' के लक्ष्य को पूरा करने की ओर तेजी से बढ़ा जा सके।

जयपुर में दिसम्बर माह में होने वाले 'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 के लिए विदेशी निवेशकों, कॉरपोरेट जगत और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को प्रदेश में निवेश हेतु आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने अक्टूबर माह में जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम (यूके) का दौरा किया।

समिट को सफल बनाने और प्रदेश में निवेश का आधार तय करने के लिए अब तक दिल्ली, मुंबई, सियोल, टोक्यो, ओसाका, दुबई ,अबू धाबी, दोहा और सिंगापुर में इन्वेस्टर रोड शो आयोजित किये जा चुके हैं ताकि निवेशकों को राजस्थान से जुड़ने, प्रदेश में निवेश हेतु आमंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा बनायी गयी निवेशक-अनुकूल नीतियों और अवसरों से अवगत कराया जा सके। इस व्यापक आउटरीच के परिणामस्वरूप राजस्थान सरकार द्वारा अब तक 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव (एमओयू) हस्ताक्षरित हो चुके हैं, जो सरकार के प्रयासों में निवेशक और व्यापार समुदाय के विश्वास को दर्शाता है।

इन्वेस्टर रोड शो के जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम में हो रहे कार्यक्रमों का आयोजन म्यूनिख में मौजूद भारत के वाणिज्य दूतावास और लंदन में मौजूद भारतीय उच्चायोग एवं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से किया गया। फिक्की 'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का इंडस्ट्री पार्टनर है। साथ ही पीडब्ल्यूसी इंडिया इस इन्वेस्टमेंट समिट का नॉलेज पार्टनर है।

तीन दिन चलेगा समिट

'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन 9, 10 और 11 दिसंबर को राजधानी जयपुर में होगा। इसका आयोजन राजस्थान सरकार के तत्वावधान में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और रीको के सहयोग से किया जा रहा है। इसका नोडल विभाग बीआईपी है। इस त्रि-दिवसीय मेगा समिट का उद्देश्य देश-विदेश की बड़ी-छोटी कंपनियों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और निवेशकों को राज्य में आकर निवेश और काम करने के लिए आमंत्रित करना, प्रदेश में विभिन्न तरह के उद्योग-धंधे लगाने में मदद करना और अन्य सुविधाएं मुहैय्या कराना है। इस ग्लोबल समिट के दौरान कृषि, ऊर्जा, शिक्षा व कौशल, ऑटो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, केमिकल, पेट्रो-केमिकल, पर्यटन, स्टार्टअप, खनन और ईएसडीएम, आईटी सहित विभिन्न क्षेत्रों पर विशेष सत्र के आयोजन होंगे। •

दिवस 1

'राइजिंग राजस्थान'
ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024
यूरोप अन्तरराष्ट्रीय 'इन्वेस्टर मीट'
म्यूनिख, जर्मनी

14 अक्टूबर, 2024

★ जापान की तर्ज पर जर्मन निवेशकों के लिए विशेष निवेश क्षेत्र की पेशकश

★ जर्मनी को समिट में पार्टनर कन्ट्री बनने का आमंत्रण

राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने यूरोप में जर्मनी एवं ब्रिटेन का छह दिवसीय दौरा किया। यूरोप के निवेशकों और कंपनियों से मुलाकात के इस दौरे की शुरुआत में प्रतिनिधिमंडल ने 14 अक्टूबर को जर्मनी में बवेरिया राज्य चांसलरी के प्रमुख और संघीय मामलों के राज्य मंत्री डॉ. फ्लोरियन हरमन के साथ म्यूनिख में मुलाकात की।

बैठक में मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने जर्मनी को 'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 का 'पार्टनर कंट्री' बनने के लिए आमंत्रित किया। साथ ही नीमराणा स्थित जापानी निवेश क्षेत्र की तर्ज पर राजस्थान में जर्मन निवेशकों के लिए एक विशेष निवेश क्षेत्र स्थापित करने की भी पेशकश की। मुख्यमंत्री ने जर्मनी के बवेरिया राज्य और राजस्थान के बीच अक्षय ऊर्जा पर विशेष जोर के साथ एक "सिस्टर पार्टनरशिप" स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा एवं राजस्थान में बवेरिया का एक कार्यालय स्थापित करने का भी उन्होंने डॉ. हरमन से अनुरोध किया। साथ ही राज्य में निवेश आकर्षित करने में जर्मन सरकार से सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की। बैठक के दौरान बवेरिया और राजस्थान के बीच स्किल्ड मैन पॉवर की जरूरतों को पूरा करने के लिए आपसी साझेदारी पर भी चर्चा की गई।

बवेरिया राज्य चांसलरी के प्रमुख और संघीय मामलों के राज्य मंत्री डॉ. हरमन से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री श्री शर्मा के अलावा उपमुख्यमंत्री सुश्री दिया कुमारी, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री शिखर अग्रवाल, म्यूनिख में भारत के महावाणिज्यदूत श्री शत्रुघ्न सिन्हा, डिस्कॉम्स की अध्यक्ष और जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक सुश्री आरती डोगरा, उद्योग विभाग और ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स (बीआईपी) के आयुक्त श्री रोहित गुप्ता

और राजस्थान सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि जर्मनी भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक और रणनीतिक साझेदारों में शामिल है और विभिन्न मामलों में उसकी तकनीकी विशेषज्ञता विश्व प्रसिद्ध है।

डॉयचेस और जयपुर के अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के मध्य सहयोग पर चर्चा

इसके बाद मुख्यमंत्री श्री शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने म्यूनिख स्थित डॉयचेस म्यूजियम का भी दौरा किया जो 1903 में स्थापित एक प्रमुख विज्ञान एवं उद्योग संग्रहालय है। डॉयचेस म्यूजियम के दौरे में राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने डॉयचेस म्यूजियम और जयपुर के अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के बीच व्यापक सहयोग पर चर्चा की जिसमें दोनों संग्रहालयों द्वारा संयुक्त प्रदर्शनियों का आयोजन, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पर्यटन को बढ़ावा देना, अनुसंधान कार्यक्रमों में आपसी सहयोग, डॉयचेस संग्रहालय में राजस्थानी युवाओं के लिए इंटर्नशिप के अवसर पैदा करना और राजस्थान में अन्य ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना शामिल है। दोनों संग्रहालयों के बीच इस सहयोग का उद्देश्य सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। जयपुर का अल्बर्ट हॉल संग्रहालय अपनी इंडो-सारसेनिक वास्तुकला और राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को व्यापक रूप से प्रदर्शित करने के लिए प्रसिद्ध है।

हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स कम्पनी को आमंत्रण

इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने हाइड्रोजन और डायरेक्ट मेथनॉल फ्यूल सेल्स की अग्रणी कंपनी एसएफसी एनर्जी एजी के परिसर का भी दौरा किया और इस दौरान एसएफसी एनर्जी को राजस्थान में निवेश करने हेतु आमंत्रित किया। यहां हुई बैठक के दौरान राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने एसएफसी एनर्जी के अधिकारियों को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान की अग्रणी भूमिका, हरित ऊर्जा के प्रति राज्य के महत्वाकांक्षी लक्ष्य और फ्यूल सेल्स के उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश के अंदर मौजूद संभावनाओं की जानकारी भी दी।

इस बैठक के दौरान एसएफसी एनर्जी ने राज्य के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने में रुचि दिखाई।

राजस्थानी मूल के लोगों से मुलाकात

इससे पहले म्यूनिख पहुंचने पर मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा और राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल का राजस्थान एसोसिएशन जर्मनी (आरएजी) के सदस्यों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान आरएजी के श्री हरगोविंद सिंह राणा, श्री शांतनु दवे और एसोसिएशन के अन्य सदस्य मौजूद थे। इस दौरान हुई बातचीत में मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने राजस्थान मूल के लोगों से अपनी जन्मभूमि से संबंधों को मजबूत बनाने का आह्वान किया और उन्हें प्रदेश में व्यवसाय करने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने म्यूनिख में भारत के महावाणिज्यदूत श्री शत्रुघ्न सिन्हा के साथ मुलाकात की और उन्हें राजस्थान में निवेश बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे आर्थिक और नीतिगत सुधारों के बारे में जानकारी दी। ●

दिवस 2

'राइजिंग राजस्थान'
ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024
यूरोप अन्तरराष्ट्रीय 'इन्वेस्टर मीट'
म्यूनिख, जर्मनी
रोड-शो, 15 अक्टूबर, 2024

★ अब तक 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू हस्ताक्षरित

★ राजस्थान में निवेश के लिए सकारात्मक वातावरण

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने अपनी जर्मनी यात्रा के दूसरे दिन 15 अक्टूबर को म्यूनिख में 'राइजिंग राजस्थान' इन्वेस्टर रोड शो में भाग लिया और जर्मनी के निवेशकों और इनोवेटर्स को राजस्थान में इकाइयां लगाने के लिए आमंत्रित किया।

इन्वेस्टर रोड शो को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जर्मनी के व्यावसायिक जगत और कारोबारी समूह से राजस्थान में ऑटोमोबाइल, ईएसडीएम, सप्लाई चेन एवं लॉजिस्टिक्स, पर्यटन, पेट्रोलियम, खान एवं खनिज, अक्षय ऊर्जा, रक्षा, पैकेजिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने का आह्वान किया और कहा कि राजस्थान में निवेश के लिए बनाए गए सकारात्मक वातावरण के सुपरिणाम मिलने लगे हैं और 'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की घोषणा के दो महीने के भीतर ही, अब तक 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत को वैश्विक कंपनियों के लिए एक सप्लाई चेन डेस्टिनेशन के रूप में देखा जा रहा है और अपनी सक्रिय और विकासोन्मुखी नीतियों के कारण राजस्थान भारत में इन कंपनियों का विश्वसनीय भागीदार बनने के लिए तैयार है। साथ ही इनके निवेश को समृद्ध और सुरक्षित बनाने के लिए राजस्थान सरकार हर कदम पर साथ है।

कई प्रमुख जर्मन कंपनियों के साथ एमओयू

म्यूनिख में आयोजित इस इन्वेस्टर रोड शो में राजस्थान सरकार ने अल्बाट्रॉस प्रोजेक्ट्स, फ्लिक्सबस, पार्टेक्स एनवी, वेउली टेक्निक्स जीएमबीएच, और इंगो श्मिट्ज जैसी कई बड़ी जर्मन कंपनियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। ये कंपनियां रक्षा, मोबिलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ऑटोमोबाइल और कौशल विकास क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों में काम करती हैं। मुख्यमंत्री श्री शर्मा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने जर्मनी के निवेशकों, व्यापारिक समूहों और इनोवेटर्स के साथ भी बातचीत की और उन्हें राजस्थान में निवेश हेतु आमंत्रित किया।

जर्मन कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात

निवेशक रोड शो के अलावा, मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने मल्टीवैक सेप हैगेनमुलर एसई एंड कंपनी केज (पैकेजिंग), एचएडब्ल्यूई हाइड्रोलिक जीएमबीएच(इंजीनियरिंग) अल्बाट्रॉस प्रोजेक्ट्स(रक्षा क्षेत्र) ब्रेनलैब (स्वास्थ्य सेवा) यूनेक्स ट्रैफिक- अर्बन ट्रांसपोर्ट जैसी कई प्रमुख जर्मन कंपनियों के अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें राजस्थान में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। इन कम्पनियों में नॉफ इंजीनियरिंग जीएमबीएच, होराइजन ग्रुप, वेउली टेक्निक्स जीएमबीएच, रोडल एंड पार्टनर, पार्टेक्स भी शामिल हैं।

मल्टीवैक ने विस्तार में दिखायी रुचि

जर्मनी की पैकेजिंग क्षेत्र की बड़ी कंपनी मल्टीवैक सेप हैगनमुलर एसई एंड कंपनी केजी के साथ राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल की बैठक के दौरान कंपनी के अधिकारियों ने राजस्थान में अपने कारोबार के विस्तार में रुचि दिखाई। इसमें, राज्य में एक आईटी हब स्थापित करना, अपने मौजूदा ऑपरेशन्स को बढ़ाना और

जर्मनी से सहयोग को उत्सुक

"राजस्थान नवाचार को अपनाकर, तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देकर और अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे में निवेश करके अपनी विशाल क्षमता को अनलॉक करने के लिए तैयार है। राजस्थान जर्मनी के साथ तकनीक और अन्य प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए उत्सुक है।"

दिया कुमारी, उपमुख्यमंत्री

"हम राजस्थान और संभावित जर्मन निवेशकों के बीच सेतु बनने तथा राजस्थान सरकार के साथ निकट समन्वय रखते हुए प्रदेश में निवेश को सुगम बनाने के लिए तैयार हैं।"

शत्रुघ्न सिन्हा, म्यूनिख में भारत के महावाणिज्यदूत

राजस्थान एक आदर्श व्यापार स्थल

"मैं सभी को राजस्थान में निवेश करने और समृद्ध भविष्य के निर्माण के हमारे प्रयासों में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। राज्य में निवेश करने वाले प्रत्येक उद्यमी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। जर्मनी वैज्ञानिक नवाचारों, तकनीकी कौशल, समृद्धि और विकास का एक शक्तिशाली प्रतीक है। हम जर्मनी के साथ अपनी मजबूत साझेदारी स्थापित करना चाहते हैं। राजस्थान रणनीतिक रूप से एक आदर्श गंतव्य है और हमारे पास मजबूत बुनियादी ढांचा और प्रचुर मात्रा में संसाधन हैं। इसके अलावा, व्यापारिक जगत के अनुकूल हमारी नीतियां हमें जर्मन कंपनियों के लिए एक आदर्श व्यापार स्थल बनाती हैं।"

भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री

राजस्थान द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों का लाभ उठाना शामिल है। एकीकृत प्रसंस्करण और पैकेजिंग क्षेत्र की यह कंपनी खाद्य, लाइफ सांइसेज, स्वास्थ्य सेवा और औद्योगिक वस्तुओं जैसे उद्योगों के लिए पैकेजिंग की सुविधा मुहैया कराती है और राज्य के घिलोट औद्योगिक क्षेत्र में इसका एक प्रोडक्शन यूनिट है।

'राइजिंग राजस्थान' टूरिज्म मीट

मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में मौजूद संभावनाओं और विकास के अवसरों को प्रदर्शित करने और जर्मनी के हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट क्षेत्रों के निवेशकों को राज्य में पर्यटन इकाइयां स्थापित करने के लिए आमंत्रण देने हेतु विशेष रूप से आयोजित 'राइजिंग राजस्थान' टूरिज्म मीट में भी भाग लिया।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किलों और महलों के अलावा राजस्थान में पर्यटन के कई नए द्वार खोले जा रहे हैं और यहां लग्जरी रिसॉर्ट्स, इको-फ्रेंडली रिसॉर्ट्स, वेलनेस टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म जैसे पर्यटन के कई क्षेत्र में अपार अवसर हैं। राज्य सरकार ग्रीन टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा, राजस्थान की जीवंत संस्कृति, जिसमें तीज और पुष्कर मेला जैसे त्योहार शामिल हैं, काफी प्रतिष्ठित हैं और इसका अनुभव सभी को करना चाहिए। सरकार यह

अक्षय ऊर्जा में निवेश का आमंत्रण

राजस्थान 2031-32 तक अपनी अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 115 गीगावाट करेगा जो अभी 28 गीगावाट है। इसके लिए 5.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की आवश्यकता है। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में वर्ल्ड लीडर जर्मनी राजस्थान में सौर और पवन ऊर्जा क्षेत्र में परियोजनाएं शुरू कर सकता है।

भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री

सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि पर्यटन के सभी क्षेत्रों का तेजी से विकास हो।

उपमुख्यमंत्री सुश्री दिया कुमारी ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र राजस्थान की अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। ऐतिहासिक किलों और मनमोहक महलों से लेकर विशाल बाघ अभयारण्यों और वन्यजीव अभयारण्यों तक, राज्य में एक पर्यटक को मिलने वाले अनुभवों की विविधता वास्तव में असाधारण है।

टूरिस्ट मीट में उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मोबिलिटी, इंजीनियरिंग, कंसल्टिंग, ऑटोमोटिव और स्वास्थ्य क्षेत्रों की प्रमुख जर्मन कंपनियों से मुलाकात की। इनमें वेउली टेक्निक्स जीएमबीएच, नॉफ इंजीनियरिंग जीएमबीएच, होराइजन इंडस्ट्रीज जीएमबीएच, रोडल एंड पार्टनर, फैकलमैन जीएमबीएच और पार्टेक्स एनवी के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठकें शामिल हैं। इन मुलाकातों के दौरान इन कंपनियों के अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि भारत में होने वाले उनकी विस्तार योजनाओं में राजस्थान प्रमुख रूप से शामिल है।

ऑटोमोटिव कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी वेउली टेक्निक्स जीएमबीएच के साथ बैठक के दौरान राजस्थान में इस क्षेत्र में उपलब्ध निवेश अवसरों पर बातचीत की गई। कंपनी की महाराष्ट्र में पहले से ही एक इकाई है और म्यूनिख में आयोजित निवेशक रोड शो के दौरान इसने राजस्थान में अपनी दूसरी ऑटोमोटिव पार्ट्स निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए राज्य सरकार के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है।

इसके अलावा, दुनिया के पहली डिजिटल फार्मा प्लेटफॉर्म और अग्रणी एआई-संचालित ड्रग एसेट्स कंपनी पार्टेक्स एनवी के साथ चर्चा में राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान को एक प्रमुख फार्मा हब बनाने के सरकार के महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण की जानकारी दी और कंपनी को राज्य में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। ●

निवेशकों से मिला अपूर्व रेस्पॉन्स

"इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हमने जो बड़ी-बड़ी कंपनियों से आउटरीच किया है, उसके सकारात्मक परिणाम आए हैं। दक्षिण कोरिया, जापान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, और सिंगापुर के निवेशक प्रदेश में कारोबार करने के इच्छुक हैं। विदेशी निवेशकों के प्रति राजस्थान की प्रतिबद्धता नीमराणा में जापानी निवेश क्षेत्र की सफलता से स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हमारा राज्य निवेश लिए एक आदर्श विकल्प है।"

रोहित गुप्ता, आयुक्त उद्योग विभाग व ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन

समिट 9, 10 और 11 दिसंबर को जयपुर में

'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन 9, 10 और 11 दिसंबर को राजधानी जयपुर में होगा। इसका आयोजन राजस्थान सरकार के तत्वावधान में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन और रीको के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इसका नोडल विभाग बीआईपी है। इस त्रि-दिवसीय मेगा समिट का उद्देश्य देश-विदेश की बड़ी-छोटी कंपनियों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और निवेशकों को राज्य में आ कर काम करने के लिए आमंत्रित करना, प्रदेश में विभिन्न तरह के उद्योग-धंधे लगाने में मदद करना और अन्य सुविधाएं मुहैया कराना है। इस ग्लोबल समिट के दौरान कृषि, ऊर्जा, शिक्षा व कौशल, ऑटो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, केमिकल, पेट्रो-केमिकल, पर्यटन, स्टार्टअप, खनन और ईएसडीएम, आईटी सहित विभिन्न क्षेत्रों पर विशेष सत्र के आयोजन होंगे।

दिवस 3

'राइजिंग राजस्थान'
ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024
यूरोप अन्तरराष्ट्रीय 'इन्वेस्टर मीट' तृतीय दिवस
म्यूनिख, जर्मनी
16 अक्टूबर, 2024

★ **राजस्थान में व्यापार बढाएगी जर्मन कम्पनी फ्लिक्स**

★ **राजस्थान में परिवहन नेटवर्क को मिलेगी मजबूती**

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने अपनी जर्मनी यात्रा के तीसरे दिन 16 अक्टूबर को ट्रैवल-टेक कंपनी फ्लिक्स बस के म्यूनिख स्थित मुख्यालय का दौरा किया और इसके आला अधिकारियों से बातचीत की।

फ्लिक्स बस कंपनी के सह-संस्थापक और सीईओ आंद्रे श्वाम्लेन, और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मैक्स ज़्यूमर के साथ हुई इस बैठक में दोनों पक्षों के बीच राजस्थान में निवेश करने और राज्य के अंदर कंपनी के परिचालन के विस्तार हेतु एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

फ्लिक्स बस परिवहन क्षेत्र की एक बड़ी कंपनी है और राजस्थान में इसका कारोबार पहले से है। इस कंपनी के साथ हुई साझेदारी का उद्देश्य राज्य में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को बढ़ाना, परिवहन सेवाओं में सुधार करना और राज्य के आर्थिक विकास में योगदान देना है, ताकि रोजगार के नए अवसरों का निर्माण हो सके। इस बैठक में राज्य के परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने में फ्लिक्स बस द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर भी जोर दिया गया, जिससे राजस्थान के निवासियों और राज्य में आने वाले पर्यटकों, दोनों को अच्छी परिवहन सेवा मिल सके। राज्य के परिवहन क्षेत्र को आधुनिक और कुशल बनाने के लक्ष्य के मद्देनजर, प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में फ्लिक्स बस के कारोबार को आगे बढ़ाने में सरकार के समर्थन का आश्वासन दिया।

इस मीटिंग के साथ ही, 'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत जर्मनी के निवेशकों से सीधे आउटरीच के दौर का समापन हुआ। इसके बाद, राज्य सरकार का यह प्रतिनिधिमंडल इंग्लैंड की राजधानी लंदन के लिए रवाना हो गया। ●

दिवस 4

'राइजिंग राजस्थान'
ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024
यूरोप अन्तरराष्ट्रीय 'इन्वेस्टर मीट'
लंदन, ब्रिटेन
रोड-शो, 17 अक्टूबर, 2024

★ राजस्थान में व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह

★ हीरा निर्माण, आईटी सहित कई फर्मों के प्रतिनिधियों से मुलाकात

यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी में निवेशकों से सफल संपर्क के बाद, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों ने 17 अक्टूबर को ब्रिटिश सरकार की मंत्री (इंडो-पैसिफिक क्षेत्र) सुश्री कैथरीन वेस्ट के साथ मुलाकात की।

इसके अलावा, प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने लंदन के पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर में स्थित ब्रिटेन की संसद का दौरा किया और भारतीय मूल के चुनिंदा सांसदों के साथ बैठक की। इन बैठकों के दौरान, मुख्यमंत्री ने राजस्थान में इंग्लैंड की कंपनियों द्वारा निवेश के लिए ब्रिटिश सरकार से सहयोग की अपील की और 9-10-11 दिसंबर को जयपुर में आयोजित 'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में भाग लेने के लिए उन्हें आमंत्रित किया।

इसके बाद, मुख्यमंत्री श्री शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), हीरा निर्माण, और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों की यूके स्थित फर्मों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इन बैठकों में एलीमेंट सिक्स (डी बीयर्स ग्रुप की कंपनी जो सिंथेटिक डायमंड, प्रोसेसिंग टूल्स आदि का कारोबार करती है), स्यानकॉनोड (नैरोबैंड आरएफ मेश नेटवर्क विकसित करने में दुनिया की अग्रणी कंपनी), जेसीबी (जो कंस्ट्रक्शन और इंडिस्ट्रियल उपयोग वाले वाहन बनाती है और जिसकी राजस्थान में मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट है) और ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स (ब्रिटेन की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी) के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात शामिल है।

"भारत और ब्रिटेन के बीच कई शताब्दियों पुराने संबंध हैं। हमने ब्रिटेन सरकार के अधिकारियों और सांसदों के साथ बहुत ही उपयोगी और व्यापक बातचीत की है और इस दौरान, प्रदेश में निवेश लाने के प्रयासों में उनसे सहयोग करने की अपील की। इसके अलावा, हमने प्रदेश में कारोबार स्थापित करने और नए निवेश के लिए वहां की कई कंपनियों के साथ चर्चा की और उनसे राजस्थान में मौजूद व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया।"

भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री

"हम राजस्थान की निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ब्रिटिश कंपनियों के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं। हमारा लक्ष्य अगले पांच वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 180 बिलियन डॉलर से दोगुना करके 350 बिलियन डॉलर करना है और ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी), डिजाइन और एडवांस्ड मैन्यूफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में ब्रिटेन की कंपनियों की विश्व-प्रसिद्ध विशेषज्ञता से न केवल राजस्थान को, बल्कि पूरे भारत को बहुत फायदा हो सकता है।"

भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री

इसके अलावा, प्रतिनिधिमंडल ने वांडरलस्ट (जो इंग्लैंड की एक प्रमुख ट्रैवल पत्रिका और वेबसाइट है) के अधिकारियों के साथ भी मुलाकात की और उनको राजस्थान को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए आमंत्रित किया। इस बैठक के दौरान प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जीवंत परिदृश्य और वैश्विक यात्रियों को प्रेरित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे विविध कदमों पर भी चर्चा की गयी।

इन्वेस्टर रोड शो के अलावा राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने अल्फा वेव (एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी) के अधिकारियों से मुलाकात की। इसके अलावा,

"हमारी प्रगतिशील नीतियों ने पर्याप्त विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित किया है और इससे हमारे आर्थिक विकास में काफी मदद मिली है। साथ मिलकर हम अपने राज्य के विशाल संसाधनों को अनलॉक कर सकते हैं और अपने इतिहास में एक नया अध्याय लिख सकते हैं।"

दिया कुमारी, उपमुख्यमंत्री

"इन्वेस्टमेंट समिट से पहले राजस्थान सरकार द्वारा किए गए व्यापक आउटरीच को देखकर हम उत्साहित हैं। भारतीय उच्चायोग ब्रिटेन स्थित निवेशकों को राजस्थान सरकार से जोड़ने में हरसंभव कोशिश करेगा।"

विक्रम के. दोराईस्वामी, ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त

"खनिज भंडारों और प्रचुर भूमि भूखंडों से परिपूर्ण हमारा राज्य व्यापार के लिए सर्वाधिक अनुकूल क्षेत्र के रूप में उभरा है। पर्यटन, कपड़ा, पेट्रो केमिकल्स और अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में राज्य परिवर्तनकारी विकास के लिए तैयार है।"

रोहित गुप्ता, आयुक्त, उद्योग विभाग और बी.आई.पी.

प्रतिनिधिमंडल ने भारत की अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी रीन्यू पावर के संस्थापक, अध्यक्ष और सीईओ सुमंत सिन्हा के साथ भी बैठक की। आईयूआईएच के साथ बैठक के दौरान, आईयूआईएच ने राजस्थान में एक बायो-मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के लिए राज्य सरकार से एक एमओयू भी किया।

रिप्स 2024 का अनावरण

लंदन में आयोजित इन्वेस्टर रोड शो के दौरान, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (आरआईपीएस) 2024 का अनावरण किया। इस अवसर उप मुख्यमंत्री सुश्री दिया कुमारी, यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त श्री विक्रम के दोराईस्वामी और राजस्थान सरकार के प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्य उपस्थित थे। रिप्स-2024 में सूचना प्रौद्योगिकी, बिजली, लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों के लिए नए प्रोत्साहन दिए गए हैं और कई नए क्षेत्रों को सनराइज सेक्टर के अंदर शामिल किया गया है। लंदन इन्वेस्टर रोड शो में राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने इंडो-यूके इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (बायो-मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट), हिंदुस्तान सिलिकॉन रिसोर्सेज लिमिटेड (रक्षा क्षेत्र), और रिन्यू पावर (अक्षय ऊर्जा) जैसी कंपनियों से प्रदेश में निवेश के लिए एमओयू किया।

प्रवासी राजस्थानियों से मुलाकात

प्रतिनिधिमंडल ने 17 अक्टूबर की शाम को प्रवासी राजस्थानियों से मुलाकात के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रवासी राजस्थानियों को अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए राज्य सरकार एक विशेष अभियान चला रही है। इसके तहत, अनिवासी राजस्थानी समुदाय से जुड़ना और मातृभूमि के साथ उनके संबंधों को जीवंत बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। इसके अलावा अनिवासी राजस्थानी समुदाय से राज्य में निवेश और नए व्यावसायिक उपक्रमों की स्थापना में सहायता करने का भी अनुरोध किया जा रहा है। ●

दिवस 5

'राइजिंग राजस्थान'
ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024
यूरोप अन्तरराष्ट्रीय 'इन्वेस्टर मीट'
लंदन, ब्रिटेन
18 अक्टूबर, 2024

★ लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में एमओयू
★ इंपीरियल इनोवेशन हब-स्केल स्पेस परिसर का दौरा

राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के अन्तर्गत ब्रिटेन के निवेशकों तक पहुंचने के प्रयास को जारी रखते हुए 18 अक्टूबर को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान सरकार के प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों ने कई ब्रिटिश कंपनियों के साथ बैठकें कीं। प्रतिनिधिमंडल ने इलेक्ट्रिक व्हीकल, एडवांस्ड मैन्यूफैक्चरिंग, खाद्य प्रसंस्करण, फिनटेक, स्वास्थ्य, खेल, प्राइवेट इक्विटी फंड, नवाचार, और अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाली ब्रिटेन की कंपनियों के आला अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें राज्य में व्यापार का आमंत्रण दिया गया। इनमें नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड केयर एक्सीलेंस के अधिकारियों के साथ हुई बैठक और लंदन के इंपीरियल कॉलेज के परिसर में स्थित इंपीरियल इनोवेशन हब-स्केल स्पेस के परिसर का दौरा शामिल है। ●

जयपुर में विकसित होगा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर

"जयपुर को स्पोर्ट्स का हब बनाने के हमारे प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है। इसके लिए हमने राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम की मालिक कंपनी रॉयल मल्टीस्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों के संग 18 अक्टूबर को लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में एक एमओयू किया है। इसके तहत, जयपुर में खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्टेडियम और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को भी विकसित किया जाएगा।"

भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री

दिवस 6

'राइजिंग राजस्थान'
ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024
यूरोप अन्तरराष्ट्रीय 'इन्वेस्टर मीट'
लंदन, ब्रिटेन
19 अक्टूबर, 2024

★ वेदान्ता चेयरमैन ने 'पूंछरी का लौठा' विकास योजना में सहयोग की इच्छा जताई
★ ब्रिटिश फिल्म निर्माताओं से राजस्थान में शूटिंग करने की अपील

ब्रिटेन की यात्रा के आखिरी दिन, 19 अक्टूबर को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्राकृतिक संसाधन समूह वेदांता ग्रुप के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल से लंदन में मुलाकात की और उन्हें राजस्थान की प्रगति में भागीदार बनने के लिए आमंत्रित किया। बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री सुश्री दिया कुमारी और राजस्थान सरकार के प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्य मौजूद थे। राजस्थान में एक लाख करोड़ रुपए अधिक के निवेश की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए वेदांता ग्रुप के चेयरमैन श्री अग्रवाल ने कहा कि यह निवेश वेदांता की कंपनियों- हिंदुस्तान जिंक, केयर्न ऑयल एंड गैस और सेसेंरिटका रिन्यूएबल्स के विस्तार में होगा और इसके अलावा, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए गैर-लाभकारी (नॉन प्रॉफिट) आधार पर वेदांता उदयपुर के पास एक औद्योगिक पार्क भी स्थापित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री और श्री अग्रवाल के बीच 'पूंछरी का लौठा' (गोवर्धन परिक्रमा से संबंधित एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल) और उसके आस-पास के क्षेत्रों के एकीकृत विकास पर भी चर्चा हुई और सरकारी प्रतिनिधिमंडल द्वारा राजस्थान के कृष्ण भूमि विकास के तहत आने वाले क्षेत्रों पर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया गया। 'पूंछरी का लौठा' की विकास योजना से प्रभावित होकर श्री अग्रवाल ने राज्य सरकार की इस परियोजना को आगे बढ़ाने में मदद करने की अपनी इच्छा व्यक्त की।

बैठक के बाद मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि बैठक में श्री अग्रवाल के साथ बेहद सार्थक चर्चा हुई और वे व्यापार जगत के अनुकूल राज्य की नीतियों से काफी प्रभावित हुए। राजस्थान में अपने निवेश को दोगुना करने एवं राज्य के व्यापारिक माहौल को और मजबूत बनाने के लिए श्री अग्रवाल ने राज्य सरकार से हाथ मिलाया है। मुख्यमंत्री ने उन्हें 'राजस्थान की प्रगति में भागीदार'

मुख्यमंत्री श्री शर्मा और राजस्थान सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने लंदन में मौजूद ब्रिटिश संग्रहालय का दौरा किया और राजस्थान स्थित कला संग्रहालयों और दीर्घाओं के साथ सहयोग की संभावनाओं पर संग्रहालय के अधिकारियों के साथ चर्चा की। मुख्यमंत्री ने लंदन में किंग हेनरी रोड स्थित अंबेडकर हाउस का भी दौरा किया और भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. भीम राव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की।

बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा, "लंदन के जिस घर में बाबा साहेब अंबेडकर रहते थे, उसे कुछ सालों पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी के नेतृत्व में भारत सरकार ने संग्रहालय बना कर देश को एक अनमोल उपहार दिया है।"

बनने और 'विकसित राजस्थान' के प्रयासों का समर्थन करने के लिए भी आमंत्रित किया है।" वेदांता ग्रुप के चेयरमैन के साथ हुई इस बैठक में ब्रिटेन के कई अन्य प्रतिष्ठित निवेशक भी मौजूद थे। इस दौरान राजस्थान में निवेश के अवसरों पर चर्चा की गई। इन निवेशकों ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद संभावनाओं को तलाशने में काफी दिलचस्पी दिखाई।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा लंदन स्थित ऐतिहासिक अंबेडकर हाउस में।

"भारत का पर्यटन परिदृश्य काफी जीवंत है और पर्यटन उद्योग के वर्ष 2029 तक 31 बिलियन यूरो के होने की उम्मीद है। इसमें राजस्थान का महत्वपूर्ण योगदान होगा। प्रदेश में पर्यटन को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए सरकार जल्द ही एक नई राजस्थान पर्यटन नीति भी शुरू करने जा रही है, जो इस क्षेत्र में सुधार करेगी और इसे निवेशकों के लिए और अधिक आकर्षक बनाएगी,"

भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री

पर्यटन सम्मेलन

इससे पहले मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने 'राइजिंग राजस्थान' पर्यटन सम्मेलन में भाग लेते हुए प्रदेश में बिजली, पानी एवं इंफ्रास्टक्चर के विकास के साथ ही निवेश के अनुकूल नितियों के संबंध में जानकारी देते हुए ब्रिटेन के निवेशकों को राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र की समृद्धि में भागीदार बनने के लिए आमंत्रित किया था।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में अपार संभावनाओं की चर्चा की और राज्य की विरासत और वन्यजीव पर्यटन में निवेश का आह्वान किया। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश फिल्म निर्माताओं से राजस्थान में शूटिंग करने की भी अपील की।

मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और विज्ञान, इंजीनियरिंग, मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में राजस्थान स्थित शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। इस संबंध में मैनचेस्टर विश्वविद्यालय द्वारा जल्द ही राज्य सरकार के साथ एक एओयू का प्रस्ताव दिया जाएगा।

इसके अलावा, यूरोप की सबसे बड़ी पावर एनालिटिक्स कंपनी ऑरोरा एनर्जी के साथ भी प्रतिनिधिमंडल की एक उपयोगी चर्चा हुई, जिसमें कंपनी ने राज्य सरकार और निजी कंपनियों को एनालिटिक्स सहायता देने करने के लिए राजस्थान में अपना कारोबार स्थापित करने में रुचि दिखाई। इन बैठकों के साथ ही प्रतिनिधिमंडल का लंदन के निवेशकों से संपर्क अभियान पूर्ण हुआ। इस दौरान व्यापारिक समूहों के बैठकें, निवेशक रोड शो, पर्यटन रोड शो और अनिवासी राजस्थानी (एनआरआर) समुदाय के साथ संपर्क साधा गया। ●

"अकेले 2023 में राजस्थान के अंदर 18 करोड़ घरेलू और 17 लाख अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आये थे। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारा लक्ष्य इस क्षेत्र में ब्रिटिश निवेशकों के साथ पारस्परिक संबंध बनाना है जिससे न केवल पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिले बल्कि हमारे दो महान देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध और भी मजबूत हों।"

दिया कुमारी, उपमुख्यमंत्री

भव्य स्वागत

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम की सफल विदेश यात्रा के बाद जयपुर पहुंचने पर जयपुर एयरपोर्ट परिसर में राज्य मंत्रिपरिषद् के सदस्यों एवं विधायकों सहित उच्च अधिकारियों ने स्वागत किया और बधाई दी। इस दौरान जयपुर शहर के प्रमुख स्थानों पर आमजन ने श्री शर्मा का अभिनंदन किया और प्रदेश की आर्थिक समृद्धि एवं विकसित राजस्थान की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। उल्लेखनीय है कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 के तहत राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए अन्य देशों में इन्वेस्टर मीट और रोड-शो आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने जर्मनी के म्यूनिख और यूनाइटेड किंगडम के लंदन में आयोजित इन्वेस्टर मीट में हिस्सा लिया और निवेशकों से मुलाकात कर उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। ●

'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024

इन्वेस्टर मीट

नई दिल्ली

रोड-शो, 30 सितम्बर, 2024

★ एक ही दिन में 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश एमओयू हस्ताक्षरित

मुम्बई में ठीक एक माह पहले 'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के अन्तर्गत प्रथम 'इन्वेस्टर मीट' के बाद 30 सितम्बर 2024 देश की राजधानी नई दिल्ली में 'इन्वेस्टर मीट' का सफलतापूर्वक आयोजन मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में किया गया।

इस 'इन्वेस्टर मीट' के दौरान राजस्थान में निवेश के लिए राज्य सरकार के ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और विभिन्न कंपनियों के बीच 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश संबंधी एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। ज्ञातव्य है कि मुम्बई में प्रथम इन्वेस्टर मीट में 4.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। दिल्ली इन्वेस्टर मीट के साथ ही प्रदेश में निवेश के लिए किए गए एमओयू का कुल मूल्य 12.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक हुआ । जो बाद में बढ़कर 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। यह वर्ष 2047 तक राज्य को 'विकसित राजस्थान' में बदलने के राजस्थान सरकार के प्रयासों में निवेशक और व्यापार समुदाय के दृढ़ विश्वास को दर्शाता है।

निवेशकों और कारोबारियों को आमंत्रण

"राजस्थान एक परिवर्तनकारी युग की दहलीज पर खड़ा है और विकास और समृद्धि के लिए हमने एक नए दृष्टिकोण को अपनाया है। हम न केवल एक मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव रख रहे हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी भविष्य का निर्माण भी कर रहे हैं। हमारी सरकार अगले पांच वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर से दोगुना करते हुए 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बनाने के लिए कृतसंकल्प है।"

भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री

दिल्ली में आयोजित 'इन्वेस्टर मीट' में मुख्यमंत्री श्री शर्मा के अलावा उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री शिखर अग्रवाल, उद्योग विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री अजिताभ शर्मा और राजस्थान सरकार के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

कई बड़ी कंपनियों से एमओयू

दिल्ली 'इन्वेस्टर मीट' में उद्योग एवं व्यापार जगत की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुई और इस दौरान अक्षय ऊर्जा, पावर ट्रांसमिशन, तेल और गैस, सीएनजी, लॉजिस्टिक्स, एग्रोटेक जैसे कई क्षेत्रों में निवेश के लिए एमओयू किये गए। प्रदेश में निवेश के लिए जिन प्रमुख कंपनियों और औद्योगिक समूहों ने सरकार के साथ एमओयू किये, उनमें टाटा पॉवर, इंडियन ऑयल, अवाडा ग्रुप, एनएचपीसी, रिलायंस बायो एनर्जी, टोरेंट पावर, स्टरलाइट पॉवर ट्रांसमिशन, महिंद्रा सस्टेन प्राइवेट लिमिटेड, टीएचडीसी इंडिया, ऑयल इंडिया, जिंदल रिन्यूएबल पॉवर, एस्सार रिन्यूएबल्स, इंद्रप्रस्थ गैस, अडानी लॉजिस्टिक्स, जेके सीमेंट, बीएल एग्रो इंडस्ट्रीज, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स जैसी कई बड़ी कंपनियां शामिल हैं।

इस दौरान, देशी-विदेशी निवेशकों, उद्योग और व्यापार जगत के दिग्गजों, इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स और अन्य संबंधित स्टेक होल्डर्स को राज्य में निवेश करने और 9-10-11 दिसंबर 2024 को जयपुर में आयोजित 'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया गया।

उद्योग जगत के दिग्गजों ने लिया हिस्सा

दिल्ली के इन्वेस्टर मीट में उद्योग जगत के कई दिग्गजों ने हिस्सा लिया। इनमें डीसीएम श्रीराम लिमिटेड के अध्यक्ष और सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर अजय एस. श्रीराम, टाटा पॉवर के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. प्रवीर सिन्हा, अवाडा ग्रुप के चेयरमैन विनीत मित्तल, जेसीबी इंडिया लिमिटेड के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक शेट्टी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ संजय अग्रवाल, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बनर्जी और जेके सीमेंट लिमिटेड के डेप्युटी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ माधव सिंघानिया शामिल थे। 'इन्वेस्टर मीट' के बाद मुख्यमंत्री ने व्यापार एवं कारोबार जगत की कई बड़ी हस्तियों से मुलाकात की और शाम को सीईओ राउंडटेबल को संबोधित किया। दिल्ली में इस इन्वेस्टर्स रोड शो का आयोजन कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंड्स्ट्री के सहयोग से किया गया। सीआईआई 'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का समिट इंडस्ट्री पार्टनर है। इसके अलावा पीडब्ल्यूसी इंडिया इस इन्वेस्टमेंट समिट का नॉलेज पार्टनर है। ●

निवेशकों के अनुकूल सरकारी प्रयास

प्रदेश में औद्योगिक भूमि के अधिग्रहण और विकास को सरल बनाया गया है और निजी औद्योगिक पार्क योजना और लैंड एग्रीगेशन एंड मॉनेटाइजेशन पॉलिसी जैसी पहलें शुरू की जा रही हैं ताकि कारोबारियों को अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया जा सके। सरकार का ध्यान व्यवसायों को सुविधाजनक बनाने का है और इसके लिए सरकार अपनी नीतियों में बदलाव ला रही है, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित बनाने में लगी है, अनुपालन का बोझ कम करने में लगी है और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता को बढ़ावा देने में लगी है। राज्य सरकार का ध्यान केवल निवेश संबंधी एमओयू करने पर नहीं है, बल्कि उन्हें धरातल पर लाकर परियोजनाओं में बदलने पर भी है।"

भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री

राज्य में निवेश करने का यह उपयुक्त समय

"यह इन्वेस्टमेंट समिट अगले 5 वर्षों में राज्य को 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की शुरुआत है। राज्य में निवेश करने का यह उपयुक्त समय है, क्योंकि सरकार समन्वित और सरलीकृत नीतियों, रेगुलेटरी कम्प्लायंस में आसानी जैसे कदमों के जरिए आपसी साझेदारी बढ़ाना चाहती है और निवेशकों को संसाधनों, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश का वांछित लाभ उठाने की सुविधा प्रदान कर रही है।"

सुधांश पंत, मुख्य सचिव

राजस्थान असीम संभावनाओं की धरती

"हम एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं, जहां राजस्थान न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध हो, बल्कि समावेशी और सतत विकास के लिए एक मानक भी स्थापित करे। मैं सभी निवेशकों से राजस्थान आने का आह्वान करता हूं। हमारे राज्य में निवेश करके, आप हमारे प्रचुर संसाधनों और स्ट्रेटैजिक लोकेशन का उपयोग आप मजबूत सप्लाई चेन और सहयोगी उपक्रम बना सकते हैं, जिससे निवेशकों और राज्य दोनों को लाभ होगा। राजस्थान असीम संभावनाओं की धरती है। जहां मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है और जहां एक ऐसी सरकार है जो आपके साथ साझेदारी करने के लिए तत्पर है।"

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री

'राइजिंग राजस्थान'
ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ कॉन्क्लेव
नई दिल्ली
1 अक्टूबर, 2024

"राजस्थान में अक्षय ऊर्जा, डिफेंस मैन्यूफैक्चरिंग, पेट्रोकेमिकल्स और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। हमारे पास जमीन की कमी नहीं है, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अपार क्षमता है, प्रचुर खनिज भंडार हैं और कुशल कार्यबल है। इनके जरिए हम राज्य और सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों - दोनों के लिए साझा समृद्धि सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ मिलकर हम सब 'विकसित भारत' और 'विकसित राजस्थान' के लक्ष्य को साकार कर सकते हैं।"

भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री

नई दिल्ली में निवेशकों की बैठक के बाद राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ 1 अक्टूबर को एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इन उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों को राज्य में मौजूद व्यवसाय व निवेश से संबंधित जानकारी देते हुए उन्हें प्रदेश में कारोबार बढ़ाने और नए निवेश करने का न्यौता भी दिया। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने इस अवसर पर 50 से अधिक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों को राज्य के व्यापारिक परिदृश्य, निवेश के नए अवसरों और राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे प्रमुख व्यापार-अनुकूल बदलावों की जानकारी दी। सीपीएसई कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों के अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे फिस्कल इन्सेंटिव्स और कारोबार को आसान बनाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी।

इस सीपीएसई कॉन्क्लेव में भाग लेने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों में हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकोर), एनटीपीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आईआरईडीए, पीजीसीआईएल, इंडियन ऑयल, एनटीपीसी, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (आईटीडीसी), फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई), न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल), राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआई-एमएसएमई), आईआरसीटीसी, एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया (एएससीआई), ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), एफआईसीएसआई (खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए सेक्टर स्किल काउंसिल), मैनेजमेंट एंड आंत्रप्रिन्योरशिप एंड प्रोफेशनल स्किल्स काउंसिल (एमईपीएससी) शामिल हैं।

सीपीएसईज़ कॉनक्लेव के बाद मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न देशों के राजदूतों, राजनयिकों के संग एक राउंडटेबल बैठक में हिस्सा लिया और राज्य में निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए उनके सहयोग और समर्थन का अनुरोध किया। इस राउंडटेबल में फिलीपींस, डेनमार्क, सिंगापुर, मेक्सिको, ओमान, मोरक्को, केन्या, इटली, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, डेनमार्क, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, तुर्की, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, ब्राज़ील, कतर, दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों के राजनयिकआमंत्रित थे।

इससे पहले, दिल्ली में 30 सितम्बर को आयोजित हुए इन्वेस्टर रोड शो में राजस्थान सरकार ने विभिन्न कंपनियों के संग 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश संबंधित एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। इन एमओयू के साथ ही, 'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 2024 के तहत प्रदेश में निवेश के लिए किए 12.50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा एमओयू हुए जो बढ़कर 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गये है। यह 2047 तक राज्य को 'विकसित राजस्थान' में बदलने के राजस्थान सरकार के प्रयासों में निवेशक और व्यापार समुदाय के दृढ़ विश्वास को दर्शाता है। 30 सितम्बर को हस्ताक्षर किए एमओयू में कई निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां शामिल थीं, जिनमें इंडियन ऑयल, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, एनएचपीसी, टीएचडीसी इंडिया, ऑयल इंडिया, इंद्रप्रस्थ गैस जैसी कई प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की कई केंद्रीय उपक्रम (सीपीएसई) शामिल हैं। इस दौरान अक्षय ऊर्जा, पावर ट्रांसमिशन, तेल और गैस, सीएनजी, लॉजिस्टिक्स, एग्रोटेक जैसे कई क्षेत्रों में निवेश के लिए एमओयू किया गया। इस इन्वेस्टर रोड शो के बाद मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने कई कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात कीं और उनसे प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को तलाशने की अपील की।

मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात करने वाली कंपनियों में माइक्रोसॉफ्ट, टाटा पावर, डीसीएम श्रीराम, अवाडा ग्रुप, एस्कॉर्ट्स कुबोटा, टीटागढ़ रेल सिस्टम, डालमिया सीमेंट्स भारत, श्री सीमेंट, सैमटेल एवियोनिक्स, जैक्सन ग्रुप जैसी कई बड़ी कंपनियां शामिल हैं। ●

"इस कॉन्क्लेव में भाग लेने वाले सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज राजस्थान की अर्थव्यवस्था को अगले पांच वर्षों में दोगुना करके 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने के राज्य सरकार के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य राजस्थान के मेहनती और प्रतिभाशाली युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना है और इन प्रयासों को सफल बनाने के लिए हम आपकी ओर बहुत उम्मीद से देख रहे हैं।"

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री

"हमारी कंपनी राज्य द्वारा व्यापार जगत के लिए उठाए जा कदमों के लाभार्थियों में से एक है और एचपीसीएल द्वारा विकसित की जा रही बाड़मेर रिफाइनरी इसका एक उदाहरण है। राजस्थान सरकार को आगामी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए शुभकामनाएं।"

रजनीश नारंग, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, एचपी

"देश के डिफेंस मैन्यूफैक्चरिंग के क्षेत्र में राजस्थान एक बड़े औद्योगिक राज्य के रूप में उभर रहा है। हमारी कंपनी की राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और सॉफ्टवेयर विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने की योजना है।"

मनोज जैन, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, बीईएल

मुख्यमंत्री से अमेरिकी राजदूत की मुलाकात

राइजिंग राजस्थान में अमेरिकी निवेशकों को किया आमंत्रित

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से 21 अक्टूबर को भारत में अमेरिकी राजदूत श्री एरिक गार्सेटी ने मुख्यमंत्री कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आगामी 9 से 11 दिसम्बर को आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में श्री गार्सेटी एवं अमेरिकी निवेशकों को आमंत्रित किया।

इस अवसर पर श्री शर्मा ने कहा कि राज्य में अक्षय ऊर्जा, खनन, आईटी और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सौर एवं पवन ऊर्जा के क्षेत्र में देश में पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एक नई पर्यटन नीति लाई जा रही है, जिसमें निवेशकों को कई तरह के लाभ दिए जाएंगे। राज्य में कौशल विकास, आई टी, बुनियादी ढ़ांचे के आधुनिकीकरण एवं रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं तथा इन क्षेत्रों में निवेशकों के लिए ढेरों अवसर हैं।

मुख्यमंत्री ने राज्य में जलवायु, सतत विकास, ग्रीन टैक्नोलॉजी, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा अनुसंधान, पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में अमेरिकी साझेदारी एवं सहयोग पर जोर दिया। श्री शर्मा ने अमेरिकी विश्वविद्यालयों के राजस्थान में कैम्पस खोलने, जीसीसी एवं डाटा सेन्टर के क्षेत्र में भी काम करने के लिए आमंत्रित किया। अमेरिकी राजदूत ने महिला विकास, ऊर्जा, शहरी विकास, खेलकूद इत्यादि के क्षेत्र में भी अमेरिका द्वारा सहयोग की इच्छा व्यक्त की। श्री गार्सेटी के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमण्डल ने श्री शर्मा द्वारा दिए प्रस्तावों पर गहन रुचि दिखाई। इस अवसर पर प्रतिनिधिमण्डल में यूएस एम्बेसी से आर्थिक मामलात अधिकारी श्री डेमन ड्यूबोई, वरिष्ठ राजनैतिक सलाहकार श्री ए. सुकेश, वाइस कौंसिल श्री एलेक्जेण्डर व्हाइट, राजनीतिक अधिकारी श्रीमती हिना राव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, (मुख्यमंत्री कार्यालय) श्री शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव उद्योग श्री अजिताभ शर्मा उपस्थित रहे। ●

अक्षय ऊर्जा में 3 लाख करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर

यूएई के निवेश मंत्री सुवैदी ने की मुख्यमंत्री से मुलाकात

राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में तीन लाख करोड़ रुपए के निवेश के ऐतिहासिक एमओयू पर 22 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और यूएई के निवेश मंत्री श्री मोहम्मद हसन अल सुवैदी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। यह निवेश प्रदेश के पश्चिमी जिलों में 60 गीगावाट क्षमता की सोलर, विंड एवं हाइब्रिड परियोजना की स्थापना के लिए किया जाएगा।

यूएई के निवेश मंत्री श्री मोहम्मद हसन अल सुवैदी और उद्योग विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री अजिताभ शर्मा ने इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए। यह एमओयू अक्षय ऊर्जा से संबंधित आधुनिकतम तकनीक का उपयोग करते हुए दीर्घ अवधि विद्युत परियोजना की स्थापना के माध्यम से प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से किया गया। इस पहल के अंतर्गत यूएई एक डेवलपर की नियुक्ति भी करेगा जो प्रदेश में शासन-प्रशासन के स्तर पर समन्वय स्थापित कर परियोजना को तेजी से साकार रूप प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही हैं। केन्द्र सरकार ने देश में 500 गीगावॉट सौर ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राजस्थान को 250 गीगावॉट के सोलर प्लांट लगाने होंगे। यूएई के साथ यह साझेदारी इस लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। श्री शर्मा ने कहा कि अनुकूल निवेश नीतियों से राजस्थान अक्षय ऊर्जा में निवेशकों की पसंद बना है। आज राजस्थान भारत में अक्षय ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर है। अगले 10 वर्षों में बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए कार्ययोजना तैयार कर बिजली तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ 2 लाख 24 हजार करोड़ रुपये के एमओयू किए हैं। लगभग 10 महीने के कार्यकाल में 32 हजार मेगावॉट के संयंत्र लगाने के एमओयू साइन किए गए हैं। यूएई के निवेश मंत्री श्री मोहम्मद हसन अल सुवैदी ने कहा कि राजस्थान की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां ऊर्जा क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। निश्चित रूप से ये नवाचार ही आगे चलकर ऊर्जा क्षेत्र की तस्वीर बदलेंगे। मुलाकात के दौरान श्री शर्मा ने आगामी 9 से 11 दिसम्बर तक जयपुर में आयोजित होने जा रहे राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 में श्री सुवैदी को आमंत्रित किया। ●

RISING RAJASTHAN
REPLETE • RESPONSIBLE • READY

रांची में 'राइजिंग राजस्थान' प्रवासी और औद्योगिक सम्मेलन

28 सितम्बर, 2024

प्रवासी राजस्थानियों को जड़ों से जुड़ने का आह्वान

"मारवाड़ी और अनिवासी राजस्थानी (एनआरआर) समुदाय के सम्मानित सदस्य आगामी 'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 को सफल बनाने की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। प्रवासी राजस्थानी समुदाय की व्यावसायिक कौशल और कारोबारी क्षमताओं का दुनियाभर में सम्मान किया जाता है। मैं इस समुदाय लोगों और उद्यमियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने मूल राज्य राजस्थान के साथ फिर से जुड़े और प्रदेश की समृद्धि एवं आर्थिक पुनरुत्थान की यात्रा का हिस्सा बनें।"

भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री

प्रवासी राजस्थानी और मारवाड़ी समुदाय को राजस्थान से जोड़ने के अभियान के तहत मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 28 सितम्बर को झारखंड की राजधानी रांची में 'राइजिंग राजस्थान' प्रवासी और औद्योगिक सम्मेलन में हिस्सा लिया।

यह सम्मेलन जयपुर में 9, 10, 11 दिसंबर को होने वाले 'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के क्रम में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर झारखंड में रहने वाले प्रवासी राजस्थानी और मारवाड़ी समुदाय के नेताओं और व्यापारिक जगत के लोगों से मुलाकात कर उन्हें राजस्थान में कारोबार करने व अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया।

इस मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने कहा कि इन्वेस्टमेंट समिट से पहले राजस्थान सरकार द्वारा की गई तैयारियों और जमीनी कार्य को पैदा हुई चर्चा दूर-दूर तक फैल रही है। उन्होंने झारखंड के व्यावसायिक समुदाय के सदस्यों से राजस्थान को एक संभावित और सबसे अधिक व्यापार-अनुकूल क्षेत्र के रूप में देखने और यहां निवेश करने की ओर बढ़ने का आग्रह किया।

प्रवासी और औद्योगिक सम्मेलन में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, पूर्व राज्यसभा सांसद श्री महेश पोद्दार, पूर्व राज्यसभा सांसद श्री अजय मारू, झारखंड विधानसभा के विधायक श्री समरी लाल, धनबाद के पूर्व मेयर श्री चंद्रशेखर अग्रवाल, रांची के पूर्व डिप्टी मेयर श्री संजीव विजयवर्गीय, राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव श्री कृष्ण कुणाल, राजस्थान फाउंडेशन की आयुक्त श्रीमती मनीषा अरोड़ा, क्रेडाई की राजस्थान इकाई के चेयरमैन श्री अनुराग शर्मा एवं कई जनप्रतिनिधि एवं मारवाड़ी समुदाय के व्यापारिक समुदाय के सदस्य शामिल थे।

इससे पहले, झारखंड पहुंचने पर प्रवासी राजस्थानी और मारवाड़ी समुदाय के नेताओं ने रांची हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और राज्य प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों का भव्य स्वागत किया। रांची में आयोजित इस 'राइजिंग राजस्थान' प्रवासी और औद्योगिक सम्मेलन का आयोजन राजस्थान फाउंडेशन द्वारा 28 सितम्बर को झारखंड मारवाड़ी प्रांतीय सम्मेलन के सहयोग से किया गया था। ●

RISING RAJASTHAN
REPLETE • RESPONSIBLE • READY

'राइजिंग राजस्थान' पर्यटन प्री समिट

प्रदेश को बनायेंगे विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल

★प्रस्तावों से प्रदेश में 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश

★लगभग 59 हजार लोगों को मिलेगा प्रत्यक्ष रोजगार

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में पर्यटन क्षेत्र को गति देने के लिए नई राजस्थान पर्यटन इकाई नीति लाई जा रही है तथा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार की रियायतों का प्रावधान किया जा रहा है। पिछले दिनों जयपुर स्थित होटल ललित में आयोजित राइजिंग राजस्थान पर्यटन प्री-समिट को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस समिट में पर्यटन क्षेत्र में 142 निवेश प्रस्तावों के एमओयू से प्रदेश में लगभग 14 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा। इससे राज्य में 59 हजार प्रत्यक्ष और 10 लाख से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम राजस्थान को एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाना चाहते हैं। इसके लिए राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन कर राजस्थान टूरिज्म इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड बनाकर पर्यटन क्षेत्र में 5 हजार करोड़ रुपये के कार्य करवाए जाएंगे। साथ ही, रिप्स-2024 में स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज के तहत इन्सेंटिव हेतु पर्यटन के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ रुपये से घटाकर 10 करोड़ रुपये कर दी गई है।

राजस्थान में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन की अपार संभावनाएं

मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान एक विश्व-प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र है, जिसे शांत, सुरक्षित एवं सौहार्द्रपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता है। इसलिए पुरे भारत वर्ष एवं दुनिया भर से पर्यटक यहां खिंचे चले आते है। 2023 में राज्य में करीब 18 करोड़ घरेलू और 17 लाख अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आए। पर्यटकों के सुगम आवागमन के लिए हवाई अड्डों का उन्नयन और विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जयपुर हवाई अड्डे में नए स्टेट टर्मिनल के निर्माण के साथ ही इसकी यात्री क्षमता भी बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है।

वैडिंग टूरिज्म, धार्मिक ट्यूरिज्म, वन्यजीव पर्यटन कई क्षेत्र में प्रदेश अपना नाम बना रहा है। हाल ही में जयपुर में नाहरगढ़ टाइगर सफारी की शुरुआत भी की गई है। साथ ही, माही नदी के द्वीपों में द्वीप पर्यटन तथा जैसलमेर के खुड़ी में पर्यटकों को डेजर्ट सफारी की असीम संभावनाएं हैं। हमें ऐसे पर्यटन स्थलों पर उपयुक्त भूखंड चिह्नित कर होटल स्थापित करने के प्रयास करने चाहिए। श्री शर्मा ने कहा कि हमारा प्रदेश फिल्म शूटिंग के लिए भी उपयुक्त है। इन संभावनाओं को भुनाने के लिए काम करने की आवश्यकता है।

पर्यटन क्षेत्र में कम निवेश पर भी अधिक लाभ

श्री शर्मा ने निवेशकों से आह्वान किया कि वे राजस्थान में अधिक से अधिक संख्या में निवेश करें। राज्य सरकार हर कदम पर उनका सहयोग करने के लिए तैयार है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार निवेश प्रस्तावों को धरातल पर लाकर पर्यटन में ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में राजस्थान को नंबर एक राज्य बनाएगी। पर्यटन मंत्री ने कहा कि आगामी मार्च माह में जयपुर में आईफा 2025 का ऐतिहासिक आयोजन किया जाएगा जो कि राजस्थान में पर्यटन के नये द्वार खोलेगा। ●

RISING RAJASTHAN
REPLETE • RESPONSIBLE • READY

भरतपुर में इन्वेस्टर मीट

उद्यमियों से संवाद कार्यक्रम

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान को एक विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है और 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाली 'राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट' इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करने के लिए छोटे एवं स्थानीय निवेश भी महत्वपूर्ण हैं।

मुख्यमंत्री श्री शर्मा 12 अक्टूबर को भरतपुर में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट के तहत आयोजित उद्यमियों के संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए छोटे उद्योगों को

सब्सिडी, जमीन आदि में विशेष रियायतें प्रदान की जा रही हैं। साथ ही, उद्योगों को सभी जरूरी मंजूरी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम विकसित किया गया है। ●

आर्थिक क्षेत्र के प्रबुद्धजनों का निवेश के लिए आह्वान

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से राजस्थान में उद्योगों को एक नई दिशा मिलेगी तथा सभी के सहयोग से इस समिट को सफल बनाते हुए राज्य में निवेश का सकारात्मक माहौल तैयार किया जा रहा है। श्री शर्मा अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में मुख्यमंत्री निवास पर राइजिंग राजस्थान के संबंध में आर्थिक क्षेत्र के प्रबुद्धजनों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में विपुल प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता के चलते निवेश की अपार संभावनाएं है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीए-सीएस सहित अन्य प्रोफेशनल्स राज्य की बड़ी ताकत हैं। इन प्रोफेशनल्स की विश्वसनीयता रहती है तथा ये सरकार व उद्यमियों के हित में काम करते हैं। उन्होंने आशा जताई कि प्रोफेशनल्स राज्य को निवेश का हब बनाने तथा अधिक से अधिक निवेश लाने में अपनी महती भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली, पानी तथा आधारभूत संरचना का योजनाबद्ध तरीके से विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राइजिंग राजस्थान को सफल बनाने के लिए टीमें दिन-रात काम में जुटी हुई है।

उद्योगपतियों ने युवाओं में उद्योग परक कौशल प्रशिक्षण बढ़ाने, फिनटेक को प्रोत्साहित करने, निवेश को बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का उपयोग, स्टार्ट अप को प्रमोट करने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सहित विभिन्न विषयों पर अपने सुझाव

दिए। इस दौरान खनन, रियल एस्टेट, हैंडीक्राफ्ट, सीए, मेडिकल डिवाइस, शिक्षा, फर्नीचर सहित विभिन्न क्षेत्रों के उद्योगपतियों ने अपने विचार व्यक्त किए।

इस अवसर पर जीनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर के चेयरमैन श्री आई सी अग्रवाल, एआरजी ग्रुप के चेयरमैन श्री आत्मा राम गुप्ता, सीएस इन्स्टीट्यूट के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. श्याम अग्रवाल, सीए इन्स्टीट्यूट के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुनील गोयल, गोलचा ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन श्री विक्रम गोलचा, महर्षि अरविंद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री संजय पाराशर, पॉली मेडिकेयर के अध्यक्ष श्री विशाल बैद, मर्चेन्ट बैंकर श्री अशोक होलानी, सीए नरेन्द्र मित्तल, सीए प्रकाश शर्मा, सीए पीपी पारीक सहित विभिन्न उद्योगपति एवं सीए-सीएस मौजूद रहे। ●

पधारों म्हारे गांव

ग्रामीण पर्यटन की झलक

देवमाली गांव

बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड से सम्मानित भगवान देवनारायण का गांव

सोनू शर्मा, सहायक जनसम्पर्क अधिकारी

भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है महात्मा गांधी का यह कथन हिंदुस्तान के गांवों में लहलहाते खेतों, उनके बीच से गुजरती पगडंडियों, गार से बने मकान...जिन पर गोबर का लीपणा, घरों पर केलुओं की छाया, बरगद का बड़ा सा पेड़, उसके नीचे हथाई पर पटेलाई करते लोग, पनघट पर महिलाओं का जमघट, बैलों के गले में घण्टियों का रूनझुन संगीत की खूबसूरत तस्वीर को बयां करता है। इस तस्वीर को यथार्थ में बदलता राजस्थान का देवमाली गांव, अजमेर से करीब 60 किलोमीटर दूर मसूदा उपखंड का ऐसा गांव जो आज भी गांव के वास्तविक मानकों को, मूल्यों को और मौलिकता को अपने में संजोए हुए है। गांव के सारे घर कच्चे हैं, घरों के ऊपर मिट्टी के केलुओं की छत है, सारा गांव एक परिवार है, लोगों में प्यार है और आने वालों का अच्छा सत्कार है।

भारतीय समाज की जड़ों को मजबूत और उसमे मिठास घोलने वाले देवमाली गांव को विश्व पर्यटन दिवस (27 सितंबर) के अवसर पर केन्द्र सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत के गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2023 में सर्वश्रेष्ठ गांव प्रतियोगिता शुरू की गई थी। इस प्रतियोगिता के दूसरे संस्करण 2024 में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 991 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें 8 श्रेणियों के अंतर्गत 36 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 में सम्मानित किया गया।

नई दिल्ली में स्थित विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में देवमाली गांव को यह पुरस्कार कम्यूनिटी बेस्ड टूरिज्म की श्रेणी में प्राप्त हुआ है। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में ब्यावर जिले के तत्कालीन कलक्टर श्री उत्सव कौशल और देवमाली गांव की सरपंच श्रीमती पूजा गुर्जर ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वर्ष 2023 में उदयपुर के मेनार गांव को भी बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड प्राप्त हुआ था।

गांव की 3200 बीघा जमीन भगवान देवनारायण के नाम

देवमाली गांववासियों की भगवान श्री देवनारायण में गहरी आस्था है। यहां स्थित करीब 1100 साल पुराना भगवान श्री देवनारायण मंदिर प्रदेशवासियों, खासकर गुर्जर समाज के आस्था का प्रमुख केंद्र है। गांव की करीब 3200 बीघा जमीन भी मंदिर के नाम ही है, जो कि सामाजिक समरसता का अद्वितीय उदाहरण

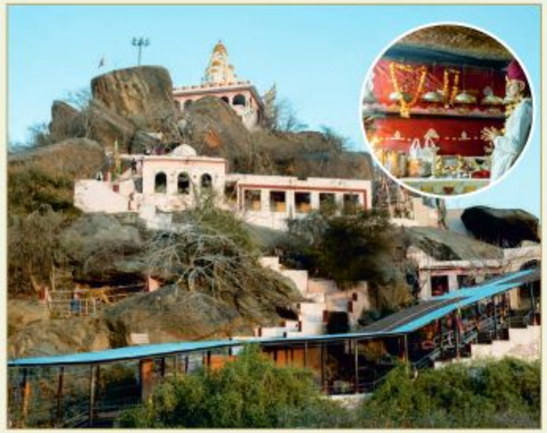

> "यह विशिष्ट सम्मान न केवल देवमाली के लिए अपितु समस्त राजस्थान के लिए गर्व का विषय है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह उपलब्धि हमारे प्रदेश के पर्यटन उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।"
>
> भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री

हैं। करीब दो हजार की आबादी वाले इस गांव के निवासी मुख्यतः कृषि और पशुपालन के जरिये अपना जीवनयापन करते हैं। देवमाली की विशेषता है कि यहां सभी घर कच्चे है जिनमें छत छप्पर की बनी है। मंदिर और सरकारी भवनों के ही पक्के निर्माण हैं।

शुद्ध शाकाहारी, जीरो क्राइम

देवमाली गांव के लोगों की जीवनशैली अतीत की परम्पराओं को सहेजने के साथ भविष्य के विकसित एवं आदर्श गांव का निर्माण करती है। यहां हर व्यक्ति शाकाहार अपनाने और शराब का सेवन नहीं करने के वचन को ताउम्र निभाता है। इन समृद्ध परम्पराओं के कारण देवमाली जीरो क्राइम वाला गांव बना हुआ है।

गांव में बने करीब 300 कच्चे मकान, जहां चूल्हे पर भोजन बनता है, साथ ही मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग यहां देशी-विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहां के मकान पीली मिट्टी से पत्थरों की चुनाई कर बनाये गए हैं, जिन पर चिकनी मिट्टी के साथ गोबर मिलाकर दीवारों पर लेप किया गया है, यह ईको-फ्रेंडली मकान सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडे रहते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में भारत के प्रयास विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हुए अपनी समृद्ध विरासत को संरक्षित करने पर केन्द्रित हैं। भारत का दृष्टिकोण संस्कृत श्लोक 'अतिथि देवो भवः' जिसका अर्थ 'अतिथि भगवान है' पर आधारित है। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा राजस्थान के ब्यावर जिले के देवमाली गांव को "सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार" से पुरस्कृत किया गया है। भगवान श्री देवनारायण की यह पावन भूमि अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक महत्व के लिए विख्यात है। यह पुरस्कार देवमाली की विशिष्टता और राजस्थान में पर्यटन क्षेत्र में इसके अद्वितीय योगदान को रेखांकित करता है। ●

पैरा ओलंपिक में राजस्थान के खिलाड़ियों ने लहराया परचम

अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल और सुंदर गुर्जर ने भारत की झोली में डाले पदक

पेरिस पैरालंपिक में राजस्थान के खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया। अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल और सुंदर गुर्जर ने अपने सुनहरे प्रदर्शन से पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत का परचम लहरा कर हर भारतवासी को गौरवान्वित कर दिया। जयपुर की अवनी लेखरा और मोना अग्रवाल ने शूटिंग के एक ही कॉम्पिटिशन में भारत को दो मेडल दिलाए। अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता, वहीं मोना अग्रवाल ने ब्रॉन्ज मेडल भारत की झोली में डाला। अवनी लेखरा का पैरालंपिक में यह दूसरा गोल्ड मेडल है। इससे पहले अवनी टोक्यो पैरालंपिक में भी गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। इसके साथ ही वे पैरालंपिक में तीन मेडल जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान की दोनों शूटर्स को फोन कर व्यक्तिगत रूप से बधाई दी।

आर-2 महिला 10 एम एयर राइफल एसएच-1 के फाइनल राउंड में अवनी पहले और मोना तीसरे नंबर पर रहीं। गोल्ड पर निशाना साधने वाली अवनी ने अपना ही पैरालंपिक रिकॉर्ड भी तोड़ा। टोक्यो पैरालंपिक में उन्होंने 249.6 पॉइंट हासिल कर पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया था। इस बार 249.7 पॉइंट हासिल कर नया रिकॉर्ड बनाया। मोना अग्रवाल ने 228.7 का स्कोर कर मेडल जीता। अवनी लगातार दो स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। राजस्थान की अवनी ने 11 साल की उम्र में कार दुर्घटना में अपने दोनों पैर गंवा दिए थे। साथ ही कमर का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त होने से व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा। इस हादसे से अवनी पूरी तरह टूट चुकी थी। डिप्रेशन में चली गई थी। मगर, पिता ने उनका हौसला बढ़ाया। अवनी ने गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा की बायोग्राफी पढ़ी और 2015 में जयपुर के जगतपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ट्रेनिंग शुरू की। टोक्यो पैरालंपिक

नरेन्द्र सिंह शेखावत, सहायक जनसम्पर्क अधिकारी

पैरालंपिक में राजस्थान के इन खिलाड़ियों ने लिया भाग

अवनि लेखरा, मोना अग्रवाल, सुंदर सिंह गुर्जर, कृष्णा नागर, संदीप सिंह, श्याम सुंदर, अनीता चौधरी, रुद्राक्ष खंडेलवाल व निहाल सिंह।

2020 में एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता और आज वह दो स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी हैं।

राजस्थान की बेटी मोना अग्रवाल ने दिसंबर 2021 से ही शूटिंग करना शुरू किया। मोना अग्रवाल ने इसी साल 9 मार्च को अपने कॅरियर के चौथे इंटरनेशनल टूर्नामेंट डब्ल्यूएसपीएस पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने विमेन्स 10 मीटर एयर राइफल एसएच-1 कैटेगरी में गोल्ड जीतकर 2024 पेरिस पैरालंपिक का कोटा हासिल कर लिया था। वहीं, इस कैटेगरी में अवनी लेखरा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इससे पहले मोना ने गोला फेंक और वेट लिफ्टिंग में स्टेट लेवल तक खेला है। मोना अपने जन्म के कुछ महीनों बाद ही पोलियो से पीड़ित हो गई थीं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में राजस्थान के सुंदर गुर्जर ने जेवलिन थ्रो में 64.96 मीटर की दूरी तक भाला फेंक कर कांस्य पदक अपने नाम किया। सुंदर गुर्जर गंगापुरसिटी के टोडाभीम के देवलेन गांव के रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राजस्थान के करौली जिले के प्रतिभाशाली एथलीट सुंदर गुर्जर ने पेरिस पैरालंपिक में भाला फेंक (एफ-46) प्रतियोगिता में कांस्य पदक प्राप्त कर न केवल देश बल्कि पूरे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने फोन पर दी खिलाड़ियों को बधाई

Narendra Modi
@narendramodi

India opens its medal account in the #Paralympics2024!

Congratulations to @AvaniLekhara for winning the coveted Gold in the R2 Women 10M Air Rifle SH1 event. She also creates history as she is the 1st Indian woman athlete to win 3 Paralympic medals! Her dedication continues to make India proud.

Narendra Modi
@narendramodi

Congratulations to Mona Agarwal on winning the Bronze medal in R2 Women 10m Air Rifle SH1 event at the Paris #Paralympics2024!

Her remarkable achievement reflects her dedication and quest for excellence. India is proud of Mona!

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने फोन पर दी खिलाड़ियों को बधाई

Bhajanlal Sharma
@BhajanlalBjp

राजस्थान की दो बेटियों ने रचा नया इतिहास!

पेरिस पैरालंपिक 2024 की शूटिंग प्रतियोगिता में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल (SH1) स्पर्धा में राजस्थान की बिटिया अवनि लेखरा को स्वर्ण पदक व मोना अग्रवाल को कांस्य पदक जीताने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

आप दोनों के अविरल परिश्रम एवं दृढ़ संकल्प से अर्जित यह स्वर्णिम उपलब्धि से राजस्थान सहित सम्पूर्ण राष्ट्र गौरवान्वित है।

उज्ज्वल भविष्य हेतु ढेरों शुभकामनाएं!

जय हिन्द! जय भारत!

राजस्थान का मान बढ़ाया है। सुंदर गुर्जर ने 2023 में आयोजित एशियाई पैरा गेम्स में भी इतिहास रचा था। उन्होंने 68.60 मीटर थ्रो कर गोल्ड मेडल जीता था। 2021 में आयोजित पैरालंपिक खेलों में भी सुंदर गुर्जर ने कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुंदर गुर्जर को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बधाई दी थी।

पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत ने किया अभूतपूर्व प्रदर्शन

खेल जगत में भारत लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने वो करके दिखाया जो अबतक नहीं हुआ था। भारत के खिलाड़ियों ने पैरालंपिक के अपने पिछले साल के रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए शानदार प्रदर्शन किया। टोक्यो पैरालंपिक के मुकाबले भारत ने पेरिस पैरालंपिक में ज्यादा पदक हासिल किए। भारत ने पेरिस 2024 खेलों में पैरालंपिक इतिहास में अपना सबसे सफल प्रदर्शन करते हुए कुल 29 पदक जीत कर अंकतालिका में 18वां स्थान हासिल किया। जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल थे। इस उपलब्धि ने टोक्यो 2020 के 19 पदकों को भी पीछे छोड़ दिया। जिसमें पांच स्वर्ण पदक शामिल थे। इस रिकॉर्ड उपलब्धि के साथ भारत ने अपने पैरालंपिक इतिहास में 60 पदकों के आंकड़े को छू लिया।

28 अगस्त से 8 सितंबर तक फ्रांस की राजधानी में आयोजित हुए पेरिस 2024 पैरालंपिक में रिकॉर्ड 84 पैरा-एथलीटों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत ने 12 डिस्सिलिन में प्रतिस्पर्धा की, जो टोक्यो 2020 से तीन अधिक हैं। भारतीय पैरा-एथलीटों ने पेरिस 2024 में तीन नए खेलों पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो में हिस्सा लिया। अवनि लेखरा पैरालंपिक खेलों में दो स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच-1 शूटिंग स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ अपने खिताब को डिफेंड किया। भारत ने पहली बार एथलेटिक्स में दो रिकॉर्ड दर्ज किए। जिसमें धर्मबीर और परनव सूरमा ने पुरुषों की क्लब थ्रो एफ-51 स्पर्धा में स्वर्ण और रजत पदक जीते। धर्मबीर ने 34.92 मीटर का नया एशियाई रिकॉर्ड भी बनाया। इसके बाद प्रवीण कुमार ने हाई जंप टी-64 खिताब जीतने के साथ एशियाई रिकॉर्ड भी दर्ज किया और भारत को छठा स्वर्ण दिलाया। जो पैरालंपिक में भारत के सबसे ज्यादा जीते गए स्वर्ण पदक हैं।

भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल ने भी पैरालंपिक में अपना खिताब डिफेंड करने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी के रूप में इतिहास रचा। उन्होंने पुरुषों की भाला फेंक एफ-64 में 70.59 मीटर के शानदार थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। जो एक नया पैरालंपिक रिकॉर्ड है। सुमित ने टोक्यो 2020 पैरालंपिक में बनाए गए अपने ही पिछले रिकॉर्ड को एक बार नहीं बल्कि प्रतियोगिता के दौरान तीन बार तोड़ा। इसके अलावा हाई जंप टी-42 वर्ग में कांस्य पदक के साथ, मरियप्पन थंगावेलु लगातार तीन पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रीति पाल ने महिलाओं की 100 मीटर टी-35 दौड़ में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ कांस्य पदक जीता। यह पैरालंपिक के ट्रैक इवेंट में भारत का पहला पदक था।

भारत ने पेरिस 2024 में ट्रैक स्पर्धाओं में चार पदक जीते। इसमें दीप्ति जीवनजी भी शामिल थीं। जो महिलाओं की 400 मीटर टी-20 वर्ग में कांस्य के साथ पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली बौद्धिक रूप से कमजोर भारतीय एथलीट बनीं। पैरा तीरंदाज शीतल देवी ने दूसरे स्थान पर रहने से पहले रैंकिंग राउंड में कुछ समय के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया। लेकिन बाद में उन्होंने राकेश कुमार के साथ मिलकर कंपाउंड मिश्रित टीम क्वालिफिकेशन स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड स्कोर हासिल किया। महज 17 साल की उम्र में, शीतल ने राकेश के साथ मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य हासिल करके भारत की सबसे कम उम्र की पैरालंपिक पदक विजेता के रूप में इतिहास रच दिया। भारत को हरविंदर सिंह के रूप में अपना पहला पैरालंपिक तीरंदाजी चैंपियन भी मिला। •

चरैवेति.... चरैवेति....

हेमेन्द्र सिंह
सहायक जनसंपर्क अधिकारी

'चरन् वै मधु विन्दति चरन् स्वादुमुदुम्बरम।
सूर्यस्य पश्य श्रेमाणं यो न तन्द्रयते चरँश्चरैवेति।।

ऐतरेय ब्राह्मण उपनिशद का यह श्लोक, जीवन में अहर्निश गतिशील बने रहने के गहरे अर्थ को रेखांकित करता है।

निरंतर काम करते रहने और गतिशील बने रहने का यही सनातन मंत्र मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का जीवन-मंत्र है। धरातल पर विकास कार्यों के निरीक्षण से लेकर निवेश के लिए विदेश की ओर उड़ान चरैवेति-चरैवेति के इस जीवन-मंत्र को सारगर्भित करती है। मुख्यमंत्री की निरंतर सक्रियता के फलस्वरूप ही प्रदेश में जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण व विकसित राजस्थान के रोडमैप को नई दिशा और गति मिल रही है और प्रदेश में सुशासन के नित-नए अनुकरणीय आयाम स्थापित हो रहे हैं। इसी क्रम में प्रस्तुत है अक्टूबर माह की कुछ सक्रियताओं का समेकित संयोजन.......

लोकार्पण

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के नाहरगढ़ में टाइगर सफारी सुविधा का फीता काटकर लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नाहरगढ़ जैविक उद्यान में दो बाघ शावकों का नामकरण भी किया। मुख्यमंत्री ने मादा बाघ शावक का नाम 'स्कंदी' तथा नर बाघ शावक का नाम 'भीम' रखा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वन्य जीवों की रक्षा तथा प्रकृति को संजोए रखना हम सभी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि वन विभाग और जेडीए के संयुक्त प्रयासों से शुरू हो रही टाइगर सफारी से बाघों के संरक्षण एवं संवर्धन को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि जयपुर जिले में जीरोता में नगर वन एवं नेवटा के पास बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित किए गए हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की स्वच्छता, सुरक्षा, सम्मान व समृद्धि की प्रतिबद्धता हो रही साकार

प्रदेश में 21 हजार आवासविहीन परिवारों को मिले आवासीय पट्टे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की स्वच्छता, सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि की प्रतिबद्धता को मूर्त रूप प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने घुमंतू, अर्द्धघुमंतू, विमुक्त समुदायों के आवासहीन परिवारों को व्यक्तियों को भूमि आवंटित किए जाने को ऐतिहासिक एवं अनुकरणीय पहल की है। गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं आवासीय पट्टा वितरण कार्यक्रम के तहत प्रदेशभर के लगभग 21 हजार लाभार्थियों को आवासीय पट्टे सौंपे गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में आयोजित समारोह में लाभार्थियों को आवासीय भूखंड के पट्टे वितरित किए और लाभार्थियों से संवाद भी किया।

प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन को दिया जन आंदोलन का रूप

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि गांधीजी का मानना था कि 'स्वच्छता ही सेवा' है और यही विचार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्ष 2014 में गांधी जयंती पर शुरू किए गए 'स्वच्छ भारत मिशन' का मूल आधार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस मिशन को जन आंदोलन बनाया और स्वयं पहल कर देशवासियों को इस अभियान से जोड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाखों शौचालयों का निर्माण, खुले में शौच से मुक्ति और स्वच्छता के प्रति बढ़ती जागरूकता ने हमारे गांवों, शहरों और कस्बों को स्वच्छ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

घुमंतू, अर्द्धघुमंतू, विमुक्त समुदाय हमारी संस्कृति और समाज का जीवंत हिस्सा हैं, जिन्होंने देश को आजादी दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रदेश में आवास विहीन परिवारों को स्वयं को आवासीय पट्टों के साथ ही स्वयं का आवास उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार भरसक प्रयास कर रही है।

भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री

''हम पीढ़ियों से भटकते रहे, आपने दिया आसरा''

मुख्यमंत्री ने घुमंतू, अर्द्ध घुमंतू एवं विमुक्त समुदाय के परिवारों को आवासीय भूखंड के पट्टे वितरण के दौरान तथा लाभार्थियों से संवाद भी किया। बीकानेर जिले के लाभार्थी श्री मनफूल नाथ ने मुख्यमंत्री से कहा कि हम स्थाई आवास के अभाव में वर्षों तक भटकते रहे मगर आज राज्य सरकार ने हमें आवासीय पट्टा देकर हमें आसरा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भूखंड का पट्टा मिला है तो आगे प्रधानमंत्री आवासीय योजना में मकान भी बनाकर दिया जाएगा। चित्तौड़गढ़ से एक अन्य लाभार्थी श्री रूपेश ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने समुदाय के हित में संवेदनशील कार्य किया है। कार्यक्रम में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत उल्लेखनीय कार्य के लिए विभिन्न ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही, सफाई कार्मिकों को पीपीई किट बांटे गए तथा 'सबकी योजना-सबका विकास' विषय पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया गया।

भरतपुर दौरा

धरातल पर विकास कार्यों का जायजा

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर प्रवास के दौरान बस में सवार होकर भरतपुर शहर का मैराथन दौरा करते हुए विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने आरबीएम जिला अस्पताल परिसर पहुंचकर नवीन भवन निर्माण कार्य का जायजा लिया और निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने लोहागढ़ किले में किशोरी महल प्लाजा विकास कार्य, टाउन हॉल विकास कार्य, बिहारी जी परिक्रमा मार्ग, बिहारी जी पार्क, सुजान गंगा एवं लोहागढ़ किले तथा गंगा मंदिर सहित विभिन्न विकास कार्यों का अवलोकन किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

भरतपुर संभाग समीक्षा

बजट घोषणाओं को समयबद्ध रूप से करें पूरा

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर संभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि लोकसेवक जनसेवा की भावना को सर्वोपरि रखते हुए अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा और लगन से पालन करें। मुख्यमंत्री ने बैठक में 'एक जिला-एक उत्पाद' योजना के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही भरतपुर संभाग के खनिज एवं हथकरघा संबंधी उत्पादों को विशेश रूप से प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि कनेक्शनों के लम्बित आवेदनों के कनेक्शन जारी करने, पीएम कुसुम योजना से अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने, रबी सीजन में उर्वरक एवं बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में प्रभावी निर्देश दिए। उन्होंने मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिये जलभराव वाले क्षेत्रों से पानी की निकासी करने तथा पर्याप्त साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि महिलाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, शिक्षक एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की टीम बनाकर उन्हें अपराधों के प्रति जागरूक किया जाए। उन्होंने अवैध खनन एवं संगठित अपराध पर पुलिस कार्यवाही को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री का विजन

आमजन की हर समस्या का हो समाधान

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर जिला मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर आमजन के अभाव अभियोग सुने तथा मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जन सुनवाई के दौरान संवेदनशीलता दिखाते हुए दिव्यांग शिक्षक विजयसिंह के पास पहुंचकर उनकी परिवेदना सुनी तथा अधिकारियों को उचित कार्यवाही के निर्देश दिए।

सनातन परम्परा का पालन : कर्म के साथ धर्म

त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में दर्शन करते मुख्यमंत्री

माँ कैलादेवी के दरबार में मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री निवास में प्रथम सामूहिक क्षमावाणी समारोह

राज राजेश्वरी मंदिर में पूजा-अर्चना

शारदीय नवरात्रि की महानवमी पर देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन कर भोजन ग्रहण कराते मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा।

विजयादशमी पर जयपुर में आयोजित विशाल दशहरा महोत्सव में सहभागिता करते मुख्यमंत्री।

पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी, प्रदेश के 70 लाख किसान हुए लाभान्वित

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना की 18वीं किस्त तथा कृषि एवं पशुपालन से संबंधित विभिन्न नवीन योजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, भी जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास से वीसी के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के किसानों को पीएम किसान योजना के 6 हजार रुपये के अतिरिक्त 2 हजार रुपये प्रतिवर्ष, गेहूं के 2275 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य के ऊपर 125 रुपए का बोनस प्रदान कर 2400 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। उल्लेखनीय है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत राजस्थान के 70 लाख 36 हजार 501 किसानों को कुल 1546.6 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं।

प्रथम आदि गौरव सम्मान समारोह

अंजलिका पंवार, सहायक जनसम्पर्क अधिकारी

जनजाति के संघर्ष, शौर्य और बलिदान की कहानी बयां करता मानगढ़ धाम देश के तीन राज्यों (राजस्थान, गुजरात व मध्य प्रदेश) की सीमाओं से घिरा है। बांसवाड़ा में स्थित यह ऐतिहासिक स्थल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और आदिवासी संघर्ष का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यह स्थान विशेष रूप से गोविंद गुरु और उनके नेतृत्व में हुए आदिवासी आंदोलन से जुड़ा है। यह स्थान न केवल आदिवासी वीरता और बलिदान बल्कि उन आदिवासियों की स्मृति को भी संजोए हुए हैं, जिन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। आज मानगढ़ धाम एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल और स्मारक के रूप में स्थापित हो चुका है। यहां हर साल हजारों लोग गोविंद गुरु और अन्य शहीद आदिवासियों को श्रद्धांजलि देने आते हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने पिछले दिनों मानगढ़ धाम में आयोजित 'आदि गौरव सम्मान' समारोह के अवसर पर आमजन को संबोधित करते हुए यहां के अविस्मरणीय इतिहास व समृद्ध लोक कलात्मक जीवन की प्रशंसा की और सम्मान प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों को बधाई देते हुए खुशी जताई कि महिलाओं की संख्या सम्मान प्राप्त करने वालों में अधिक रही। आदिवासी महिलाएं आगे बढ़ रही है, यह राजस्थान और पूरे देश के लिए गर्व की बात है। इस दौरान उन्होंने मानगढ़ आंदोलन से जुड़े भील समुदाय के गीत भूरेटिया नई मानूं रे नई मानूं का भी उल्लेख किया। उन्होंने जनजातीय समुदायों, किसानों और महिलाओं सहित वंचित वर्गों के कल्याण और विकास हेतु अनेक क्षेत्रों में सक्रियता के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को साधुवाद भी दिया।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 'आदि गौरव सम्मान' समारोह के दौरान मानगढ़ धूणी क्षेत्र के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए व मानगढ़ धाम में पुलिस चौकी खोलने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पहली बार आदि गौरव सम्मान के माध्यम से जनजाति क्षेत्र के विकास में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं को सम्मानित किया गया। इससे आदिवासी समाज के अन्य लोग भी प्रेरणा लेकर क्षेत्र के विकास में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

आदिवासी समुदाय का तीर्थस्थल मानगढ़ धाम पूरे भारत में एक ऐतिहासिक धरोहर है। यहां गोविंद गुरु जी के नेतृत्व में आदिवासी समुदाय ने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़कर साहस और बलिदान की अनुपम मिसाल पेश की। हमारी सरकार आदिवासी समुदाय के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मानगढ़ धाम को एक प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। जिससे इस क्षेत्र की संस्कृति के प्रचार के साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित हो सकेंगे।

भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री

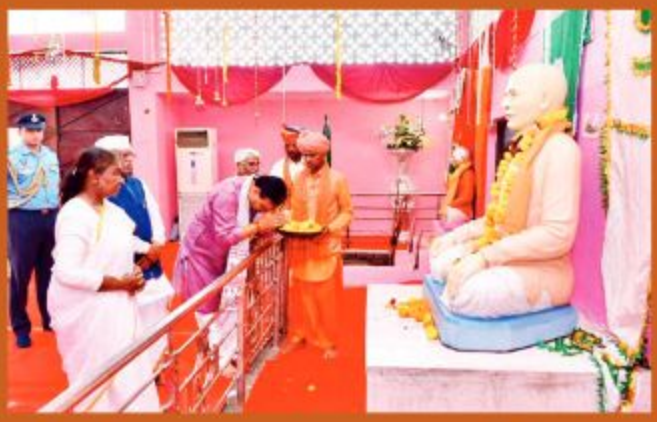

आदि रत्न गौरव सम्मान

- वकील राज डिंडोर, सुनीता मीणा, सिमरन मीणा, तुलसी राम गमेती और डिंपल चंडात।

आदि सेवा गौरव सम्मान

- थावरी बाई, जगदीश जोशी और रिन्युअल एनर्जी टेक्नोलॉजी (दुर्गा सोलर)।

आदि ग्रामोत्थान गौरव सम्मान

- भवरीदेवी मीणा, गुलाब देवी डामोर, रेखा कुमारी, आशादेवी खराड़ी, शीला कटारा, रूपहिंग कटारा, दुर्गाशंकर नागर, कन्हैयालाल, धुलीराम मीणा।

भीमलत महादेव मंदिर

प्रकृति की गोद में स्थापित भीमलत महादेव मंदिर बूंदी जिले में चित्तौडगढ़ मार्ग पर स्थित है। यहां बने शिवालय में प्रकृति स्वयं महादेव का अभिषेक करती है, जहां पहाड़ों से बारहमासी निकलने वाले पानी से महादेव का अनवरत जलाभिषेक होता है। मान्यता है कि महाभारत काल में पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान यहां आये थे। इस दौरान पीने के पानी का इंतजाम करने के लिए भीम ने जमीन पर पैर मारा तो वहां पानी की धारा निकल पड़ी, वही जलधारा आज भी बह रही है। इसी कारण इस स्थान का नाम भीमलत यानी भीम द्वारा लात मारना है। प्राचीन भीमलत महादेव मंदिर के पास ही भीमलत झरना स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 150 फीट है। सावन में यहां आस-पास झरनों के बहने से वातावरण अत्यंत मनोरम व रोमांचक हो जाता है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में आने से यह क्षेत्र ईको टूरिज्म का प्रमुख केंद्र बनेगा। यहां चिंकारा, चीतल, पैंथर, गिद्ध, भेड़िए सहित विभिन्न प्रजातियों के पक्षी व वनस्पति मौजूद है। •

आलेख एवं छाया: **संतोष मीणा**
सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी

Postal Regd. No. Jaipur City/413/2023-25
Registered with Registrar of Newspapers for India under R. No. 56175/1991

Government of Rajasthan

RISING RAJASTHAN
9-10-11 DEC 2024 • JAIPUR

REPLETE • RESPONSIBLE • READY

BHAJANLAL SHARMA
Chief Minister

NARENDRA MODI
Prime Minister

Rajasthan is Rising.
Let's Grow Together!

Rajasthan has set out to realise Hon'ble Prime Minister's vision of Viksit Bharat@2047, with its 'Viksit Rajasthan' Action Plan for becoming a $350 billion economy in next 5 years.

Rising Rajasthan goes beyond being an extraordinary 3-day Investment Summit.

It is the State's socio-economic transformational journey towards inclusive prosperity through... a journey with geographical equity, inclusivity, diversity, sustainability, promotion of MSMEs and job creation as its cornerstones.

The Rising Rajasthan Summit will be preceded by a series of investor Meets in leading business cities across the country and the world, and Sector-focused Conclaves in Jaipur.

- *Rajasthan Opportunity Showcase*
- *Strategic Sector Sessions*
- *Country Sessions*
- *One-on-one Business Meetings*
- *MSME Conclave*
- *Startup Conclave*
- *Non-Resident Rajasthani Summit*

Come, be a part of this Rising!

Department of Industries
Government of Rajasthan

Submit your investment Intent for MoU with Government of Rajasthan

राजस्थान सुजस का यह अंक
https://dipr.rajasthan.gov.in/pages/sm/government-order/attachments/134/85/10/1702
पर देखा जा सकता है।

#DIPRRajasthan

प्रकाशक व मुद्रक - सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त, सुनील शर्मा द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के लिए, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) से प्रकाशित
सम्पादक - श्रीमती अलका सक्सेना, मैसर्स, प्रिन्ट 'ओ' लैण्ड, सी-4,49,50, बाईस गोदाम, जयपुर से मुद्रित, 'राजस्थान सुजस' - पृष्ठ संख्या 68, मूल्य 1.00 रुपये • 30,000 प्रतियां